



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 1991/श्रावण 2, 1913
No. 149] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 1991/SRAVANA 2, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बजट प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1991

सं. एफ. 8(1)-बी(जी)/91 :—आदरणीय वित्त मंत्री
का 1991-92 के बजट का भाषण सर्वसाधारण की जानकारी
के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

बजट
1991-1992
वित्त मंत्री
श्री मनमोहन सिंह
का
भाषण
24 जुलाई, 1991
भाग 'क'

महोदय,

मैं वर्ष 1991-92 का बजट प्रस्तुत करता हूँ। इस
समय मुझे एकाकीपन की अनोखी अनुभूति हो रही है।
मैं बजट भाषण को एकाग्रचित्त सुनने वाले एक मनोहर,
मुस्कुराने चेहरे को अनुपस्थित पा रहा हूँ। श्री राजीव गांधी
प्रव नहीं रहे। परंतु भारत को 21वीं सदी में ले जाने का
सपना, भारत को एक भव्यत, संगठित व तकनीकी रूप से
विकसित परंतु एक उदार भारत का उनका सपना आज भी
जीवित है। मैं इस बजट को उनकी प्रेरणाशक्ति स्मृति को
समर्पित करता हूँ।

2 नई सरकार, जितने सुशिक्षित व एक महान्त पढ़ने
ही कार्यभार सम्भाला है, को एक संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था
विरासत में मिली है। भुगतान संतुलन को स्थिति बहुत ही
नाजुक है। नवम्बर, 1989 तक, जब हमारी पार्टी सत्ता
में थी, हमारी अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास काफ़ी
मुद्द था। लेकिन, उसके पश्चात् की राजनीतिक अस्थिरता,
राजनीय असंतुलनों में वृद्धि तथा खाड़ी संकट, इन सभी

के मिलेजुले प्रभाव के कारण इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वास में अत्यधिक कमी आई। वार्षिक ऋणों तथा अनिवारसी भारतीयों द्वारा जमाओं में कमी के कारण पूंजी प्रवाह में भारी कमी हुई है। परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जुलाई, 1990 तथा जनवरी, 1991 में लिए गए भारी ऋणों के बावजूद हमारे विदेशी मुद्रा भंडारों में भारी कमी आई। हम, दिसम्बर, 1990 से तथा विशेष रूप से अप्रैल, 1991 में एक संकट के कगार पर खड़े हैं। विदेशी मुद्रा का यह भारी संकट हमारी विकास प्रक्रिया को बनाए रखने तथा विकास कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से कार्यान्वित करने के लिए एक गंभीर चुनौती है। बिपरित आर्थिक और बाह्य कारणों के मिश्रण से, 1990 के मध्य से मूल्य स्तर पर भारी मुद्रास्फीतिकारी दबावों में वृद्धि हुई है। भारत के लोगों को दो अंकीय मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हमारे समाज के निर्धन वर्गों को सर्वाधिक आघात पहुंचता है। संक्षेप में, हमारी अर्थव्यवस्था का संकट काफी गहरा और तीव्र है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस तरह की परिस्थिति पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई है।

3. बड़े और निरंतर वृद्धि-आर्थिक असंतुलन और निवेश के कम प्रतिफल के कारण तथा विशेष रूप से पिछले निवेशों पर लाभ की कम दरों के फलस्वरूप हम समस्या का प्राथमिक हुआ है। सरकारी व्यय में अचानक वृद्धि हुई है। वजतीय आर्थिक सहायता, जिसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव शंकास्पद हैं, खतरनाक गति से बढ़ने दी गई है। हमारी कर प्रणाली में अभी भी अनेक खामियां हैं। इस प्रणाली में सुस्पष्टता नहीं है, जिसके कारण इस प्रणाली में दी गई विभिन्न रियायतों के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र को इस ढंग से नहीं चलाया गया, जिससे कि निवेश हेतु यथेष्ट अधिशेष धनराशियां का मूल्य हो सके। उद्योगों को अत्यधिक तथा प्रायः अविवेकपूर्ण ढंग से संरक्षण प्रदान करने से एक स्पन्दनशील नियंत्रण क्षेत्र का विकास करने के लिए प्रोत्साहन में भी कमी आई है। इससे आय और सम्पत्ति संबंधी विषमताओं में बढ़ोतरी हुई है। इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हितों के विरुद्ध कार्य किया है। सरकार के आय और व्यय के बीच बढ़ते हुए अंतर में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आय और व्यय के बीच के अंतर में बढ़ोतरी हुई है। यह वृद्धि भुगतान संतुलन के बालू खाते के घाटों में परिलक्षित होती है।

4. राजकोषीय व्यवस्था का संकट एक गंभीर चिंता का विषय है। केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा, जो कि राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है, वर्ष 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत से भी अधिक होने का अनुमान है, जब कि 1980 के दशक के प्रारम्भ में यह 6 प्रतिशत तथा 1970 के दशक के मध्य में 4 प्रतिशत था। इस राजकोषीय घाटे को उधार लेकर

पूरा करना पड़ा। परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सरकार का आर्थिक कर्ज बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 55 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इस कर्ज का परिशोधन करना अब मुश्किल हो गया है। केवल धातु की आयातियों की राशि ही सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4 प्रतिशत है और यह केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय का लगभग 20 प्रतिशत बैठती है। अगर कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति ऐसी हो जाएगी, जिसका मुद्धार करना सम्भव नहीं हो पाएगा।

5. भुगतान संतुलन की स्थिति बहुत कठिन है। बालू खाते का घाटा, जो कई वर्षों तक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 प्रतिशत था, 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत से भी अधिक होने का अनुमान है। इन लगातार घाटों के परिणामस्वरूप, जिनका वित्तपोषण अनिवार्यतः विदेशों से उधार लेकर करना पड़ा, विदेशी ऋणों में, जिनमें अनिवारसी भारतीयों की जमा राशियां भी सम्मिलित हैं, निरंतर वृद्धि होती रही है तथा 1990-91 के अंत में इन ऋणों की राशि सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 23 प्रतिशत होने का अनुमान है। परिणामस्वरूप ऋण परिणाम भार, 1990-91 की वर्तमान लेखा प्राप्तियों का लगभग 21 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह दबाव पिछले वर्ष खाड़ी संकट के कारण चरम बिंदु पर पहुंच गया। दिसम्बर, 1990 के बाद से, भुगतान संतुलन की स्थिति लड़खड़ाती हुई एक संकट से दूसरे संकट में पहुंचती गई। विदेशी मुद्रा भंडार के वर्तमान स्तर से, जो इस समय लगभग 2,500 करोड़ रुपये हैं, मात्र एक पखवाड़े की अवधि के लिए आयात का वित्तपोषण हो सकेगा।

6. मूल्य संबंधी स्थिति, जो हम सभी लोगों के लिए तात्कालिक चिंता का विषय है, एक गंभीर समस्या बन गई है, क्योंकि मुद्रास्फीति दो अंकीय स्तर तक पहुंच चुकी है। 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले राजकोषीय वर्ष के दौरान शोक मूल्य सूचकांक में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 13.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 1990-91 में मुद्रास्फीति के संबंध में मुख्य चिंता की बात यह रही कि मुद्रास्फीति आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर ही केन्द्रित रही। लगातार तीन अच्छे मानसूतों और इस प्रकार तीन शानदार फसलों के बावजूद इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। मुद्रास्फीति से सभी को दुख होता है, विशेषरूप से हमारी जनसंख्या के निर्धन वर्गों को, जिनकी आय सूखीबूझ नहीं होती है।

7. अब गंवाने के लिए कोई समय बचा नहीं है। वर्ष प्रतिवर्ष न तो सरकार और न ही कोई अर्थव्यवस्था अपने साधनों की सीमा से बाहर चल सकती है। युक्तिवाहन करने, धन अथवा समय उधार लेकर गुजारा करने को अब कोई गुंजाइश नहीं है। वृद्धि-आर्थिक समायोजन, जो काफी पहले ही किए जाने चाहिए थे, को और अधिक टालने का अर्थ यह होगा कि भुगतान संतुलन की स्थिति, जो इस समय काफी जटिल है, नियंत्रण से बाहर हो जाएगी तथा मुद्रास्फीति, जो

पहले ही काफी अधिक है, बरबाद की सीमा को पार कर जाएगी। अर्थव्यवस्था के प्रबंध को सुधारने के लिए हमारी कार्य नीति का प्रारंभिक बिन्दु और निस्संदेह केन्द्र-बिन्दु, चालू वित्त वर्ष के दौरान विश्वसनीय राजकोषीय समायोजन तथा वृहत्-आर्थिक स्थिरिकरण होना चाहिए और उसके पश्चात् राजकोषीय स्थिति को सतत् रूप से सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में, अनिवार्य रूप से, अधिक नहीं तो कम से कम तीन वर्ष लगेगें। लेकिन परेशानी उठाये बिना कोई भी समायोजन नहीं किया जा सकता। आर्थिक स्वतंत्रता को बनाए रखने तथा अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बनाने के लिए, लोगों को आवश्यक त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

8. अर्थव्यवस्था के इस वृहत् प्रबंध कार्य के लिए, बीच की इस अवधि में हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे कम किया जाए, राजस्व घाटे में भी पर्याप्त रूप में कमी लाई जाए तथा भुगतान संतुलन के मौजूदा खते के घाटे को कम किया जाए। केवल ऐसे विवेकपूर्ण प्रबंध द्वारा ही हम आन्तरिक और बाह्य ऋण में हो रही घातकीय वृद्धि को रोकने में समर्थ हो सकेंगे और सरकार तथा देश पर पड़ने वाले ऋण परिशोधन भार को प्रबंध योग्य सीमाओं में रख सकेंगे। वास्तव में, हमें सरकार के आन्तरिक ऋण तथा देश के बाह्य ऋण भार को कम करने के लिए सजग रूप से प्रयास करने चाहिए, ताकि विकास प्रक्रिया के वित्तपोषण के लिए हम अधिकाधिक अपने ही संसाधनों पर निर्भर कर सकें। परिवर्तन की इस अवधि के दौरान हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि इस समायोजन से निर्धन वर्ग पर कम से कम भार पड़े। हम मानवीय तरीके से समायोजन करने के लिए वचनबद्ध हैं। हमारा यह भी प्रयास होगा कि समायोजन प्रक्रिया हमारी अर्थव्यवस्था के अन्तर्निहित विकास की प्रेरणाओं को प्रतिकूल रूप में प्रभावित न करे। समायोजन और स्थिरिकरण को अब टाला नहीं जा सकता। हमें तेजी से और दृढ़ता से कार्य करना होगा। यदि हम इन आवश्यक सुधारों को आरम्भ नहीं करेंगे तो मौजूदा स्थिति से विकास में बाधा आएगी, आर्थिक संदी पैदा होगी तथा भ्रष्टास्फीति में वृद्धि होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को और हानि पहुंचेगी तथा निर्धन लोगों पर और अधिक भार पड़ेगा।

9. मात्र वृहत्-आर्थिक स्थिरिकरण और राजकोषीय समायोजन ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही समायोजन प्रक्रिया के एक अभिन्न भाग के रूप में आर्थिक नीति और आर्थिक प्रबंध में सुधार किए जाने चाहिए, जिनसे बर्बादी और कार्यकुशलता दूर हो सके और हमारी अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया के लिए गतिशीलता का एक नया तत्व शामिल किया जा सके। सुधार प्रक्रिया में औद्योगिक उत्पादन की कार्यकुशलता और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए धिगत की तुलना में अधिक मात्रा में विदेशी निवेश और विदेशी औद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे निवेश

की उत्पादकता बढ़ाई जा सके और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाए कि भारत के वित्तीय क्षेत्र को तेजी से आधुनिक बनाया जाए तथा सरकारी क्षेत्र के निष्पादन को सुधारा जाए। इसके फलस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, इस तेजी से बदलती हुई विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी पर्याप्त प्रौद्योगिकीय तथा प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनाए रख सकेंगे। मुझे विश्वास है कि आवश्यक संरचनात्मक और नीति संबंधी सुधारों और स्थितिकरण उपायों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के पश्चात् हमारी अर्थव्यवस्था समृद्धि मूल्यस्थिरता और अधिक सामाजिक समानता के साथ पुनः सतत् विकास के रास्ते पर लौट आएगी।

10. हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी के प्रयत्नों का आभारी होना चाहिए, जिनके कारण हमने एक अच्छा विविधीकृत औद्योगिक ढांचा विकसित किया है। जैसे-जैसे हम विभिन्न संरचनात्मक सुधार लागू करते हैं, यह हमारे लिए एक बड़ी परिसंपत्ति का कार्य करना है। तथापि, प्रवेश पर सीमाओं एवं फर्मों की आकार वृद्धि पर रोक लगाए जाने से प्रायः लार्जमेंसिंग में एक एकाधिकारक की मात्रा में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय उद्योग के कुछ हिस्से जकड़े गए हैं, जिनसे उत्पादकों के हितों की रक्षा होती है, लेकिन उपभोक्ताओं के हितों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। लागतों को कम करने, प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने और गुणवत्ता मानकों को सुधारने पर अपर्याप्त रूप से बल दिया गया है। घरेलू बाजार में फर्मों के बीच प्रतियोगिता की मात्रा बढ़ाना जरूरी है, जिससे कि उत्पादकता बढ़ाने, कार्यकुशलता में सुधार करने और लागतों को कम करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो सकें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की घोषणा की है, जिनसे घरेलू क्षेत्र में विनियमन में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। यह प्रगति हमारे सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप होगी और भुगतान संतुलन संबंधी अपरिहार्य बर्बादों से सुसंगत भी होगी।

11. औद्योगिक विकास संबंधी नीतियों का व्यापार संबंधी नीतियों के साथ घनिष्ठ संबंध है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे औद्योगिक विकास के प्रारंभिक चरण में संरक्षण जरूरी था, जिससे कि हम प्रारंभिक अवस्था में बिना किसी बाधा के काम कर सकें। पिछले चार दशकों में आयात प्रतिस्थापन का काम किया गया, जो सदा ही सुचारू नहीं रहा बल्कि कभी-कभी अविबेकपूर्ण रहा। अब समय आ गया है कि भारतीय उद्योग को विदेश में एक क्रमिक ढंग से प्रतियोगी बनाने के लिए मजबूत बनाया जाए। इस दिशा में प्रारंभिक कार्रवाई के रूप में सरकार ने आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन लागू किए हैं; जिनका उद्देश्य आयात लाइसेंसिंग में कटौती करना, तेज निर्यात संयंत्रों और आयात में इष्टतम कमी लाना है। 1 और 3 जुलाई, 1991 को किये गए विनिमय दर संबंधी समायोजन तथा प्रतिपूर्ति (रेपलिशमेंट) लाइसेंस प्रणाली को उदार बनाना, व्यापार नीति में सुधार की दिशा में दो प्रमुख प्रारंभिक उपाय

हैं। ये सुधार मातात्मक प्रतिबंधों की तुलना में मूल्य आधारित तंत्र की दिशा में परिवर्तन करने की एक शुरुआत है।

12. औद्योगिकरण के लिए योजना तैयार करने के चार दशकों के बाद अब हम विकास के एक ऐसे स्तर पर पहुँच गए हैं, जब हमें उनका न्यायगत करना चाहिए, न कि उसे गंका की दृष्टि से देखा जाए। हमारे उद्यमी किसी से कम नहीं हैं। हमारा उद्योग आधुनिक हो गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से हमें पूँजी, औद्योगिकी और बाजारों की सुविधा उपलब्ध होगी। इसने हमारे औद्योगिक क्षेत्र में क्रमिक ढंग से विदेश में प्रतियोगिता करने में सक्षमता आणगी। लागत, कार्यकुशलता और गुणवत्ता पर भी वांछित ध्यान दिया जाएगा। इसलिए हमने निम्नलिखित ढंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नीति को उदार बनाने का निर्णय लिया है। प्रथमतः, 51 प्रतिशत तक विदेशी शेयर पूँजी की बकी हुई सीमा के साथ विशिष्ट उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को तत्काल अनुमोदन दे दिया जाएगा, बशर्ते कि शेयर पूँजी प्रवाह निवेश के समय पूँजीगत वस्तुओं के आयात के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त हो और कुछ समय के दौरान लाभान्वित निर्यात आय द्वारा संतुलित हो जाएं। दूसरे, निर्यात कार्यकलापों में प्रमुख रूप से लगी व्यापार कंपनियों को 51 प्रतिशत तक की विदेशी पूँजी की अनुमति दे दी जाएगी। तीसरे, चुने हुए क्षेत्रों में अनेक बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों के साथ बातचीत करने और चुने हुए क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमोदित करने के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें पर्याप्त निवेश आकर्षित किया जा सकेगा और उच्च-औद्योगिकी तथा विश्व बाजारों तक पहुँच सुलभ हो सकेगी।

13. हमारे गणराज्य के स्थापना के लिए विकास की नीति में सरकारी क्षेत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग था, जो गतिशील, आधुनिक, प्रतियोगी और पर्याप्त अधिशेषों के सृजन में सक्षम होगा। सरकारी क्षेत्र ने हमारी औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के विविधिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन अनेक कमियाँ भी रही हैं। विशेषकर, सरकारी क्षेत्र व्यापकस्तर पर आंतरिक अधिशेषों का सृजन नहीं कर पाया है। इसलिए, इस कठिन स्थिति में सरकारी क्षेत्र के संबंध में कुछ प्रभावी कदम उठाना आवश्यक हो गया है, ताकि इसे विकास का एक माधन बनाया जा सके, न कि जितने पर्याप्त प्रतिफल के यह राष्ट्रीय बचतों का शोषक बनता रहे। इसे काफी हद तक स्वीकार किया गया है, लेकिन कथनी और करनी में अभी भी अन्तर है। इस अंतर को कम करने के लिए सरकारी क्षेत्र के निवेशों के पोर्टफोलियो की समीक्षा की जाएगी जिससे कि सरकारी क्षेत्र सविष्य में अपना कामकाज, देश के लिए महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उच्च औद्योगिकी वाले व आधारभूत ढाँचे के लिए अनिवार्य क्षेत्रों तक ही सीमित कर सके। संसाधन जुटाने, जलता की व्यापक भागीदारी का प्रोत्साहित करने और उत्तरदायित्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से पारस्परिक निधियों में तथा सरकारी क्षेत्र

की निवेश संस्थाओं तथा इसके साथ ही इन फर्म के कर्मचारियों को, चुने हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी के 20 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी दी जाएगी। वे सरकारी उद्यम, जो निरन्तर रूप से रहते हैं और जिनमें सुधार नहीं लाया जा सकता, उन्हें बुझाया शुरू करने या उनके संबंध में पुनर्वास की योजना बनाने के लिए उन्हें औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड को अवकाश स्थापित किए जाने वाले उच्चाधिकार प्राप्त ऐसे ही किसी निकाय को सौंपा जाएगा। औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड के पुनर्वास संबंधी उपायों में प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के हितों की पूर्ण सुरक्षा करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा तन्त्र की व्यवस्था की जाएगी। प्रबंध में स्वायत्तता और तदनुसारी जिम्मेदारी की व्यवस्था, सरकार और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बीच सहमति जापनों की एक प्रणाली के माध्यम से की जा सकती है।

14. हमारी बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय संस्थान, अर्थ-व्यवस्था में वित्तीय आधारभूत ढाँचे का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारी बचती हुई और फैलती हुई वित्तीय प्रणाली ने संस्थात्मक वित्त के एक विशाल क्षेत्र के प्रसार में मदद दी है। तथा इसने हमारी बचत दर, विशेषरूप से वित्तीय बचतों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह एक अत्यन्त उल्लेखनीय उपलब्धि है, परन्तु हमारी वित्तीय प्रणाली में कुछ कड़ापन और कतिपय कमजोरियाँ आ गई हैं, जिनपर हमें ध्यान देना चाहिए। वित्तीय क्षेत्र में सुधार का हमारा उद्देश्य, इसकी परम्पराओं में सुधार करते हुए, आर्थिक विकास और प्रतियोगितात्मक क्षमता के एक अभिन्न अंग के रूप में इसके बुनियादी योगदान को संरक्षित करना होना चाहिए। इस कार्य में यह जरूरी है कि पूँजी की पर्याप्तता सुनिश्चित की जाए, विवेकपूर्ण गानदण्ड लागू किए जाए और देश के वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की लाभप्रदता में सुधार किए जाएं। कोई जादुई समाधान संभव नहीं है। ये जटिल समस्याएँ हैं, जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्ति करने का प्रस्ताव करता हूँ कि जो वित्तीय प्रणाली की संरचना गठन कामकाज और प्रक्रियाओं के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करेगी। यह समिति सरकार को ऐसे उचित उपायों के संबंध में सुझाव देगी जो हमारे वित्तीय क्षेत्र की स्थिति को सुधारने और व्यवहार्यता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक होंगे, जिससे कि यह एक स्वस्थ वित्तीय प्रणाली के सिद्धान्तों और मानदण्डों को छोड़े बिना अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सके।

15. व्याज दरें वित्तीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। ऋण बाजारों के विकास के निर्माणात्मक स्तर पर व्याज दरों में प्रशासनिक हस्तक्षेप आवश्यक और वांछनीय भी है। तथापि, ऋण विकास के वर्तमान स्तर पर, इस हस्तक्षेप को माता भ्रष्ट नकते हैं और व्याज दरों के ढाँचे में अधिक लचीलापन ला सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने व्याज की

निम्नतम निर्धारित दर निश्चित करके और वाणिज्यिक बैंकों को उनके जंखिम के आधार पर निम्नतम स्तर से अधिक व्याज दर लेने की स्वतंत्रता देकर इस दिशा में पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार भी भावधि ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं को ऐसी ही स्वतंत्रता देने का विचार रखती है, जहाँ न्यूनतम व्याज दर 15 प्रतिशत होगी और ये संस्थाएँ ऋणकर्ता की माँख को ध्यान में रखते हुए व्याज दर लेने के लिए स्वतंत्र होंगी। सरकारी क्षेत्र के लिए कर मुक्त आण्डों को छोड़कर पूँजी बाजार में जारी किए गए परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय दोनों ही प्रकार के ऋण पत्रों के लिए व्याज दरों के संबंध में सभी प्रकार के प्रतिबंधों को दूर करने का भी प्रस्ताव है। इसके बाद ऐसे ऋण मात्रों पर व्याज दर का अधिशासन बाजार प्रणालियों द्वारा होगा और ऐसे ऋण माधनों की ऋण माँख (रेटिंग), पूँजी बाजार प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सरकार व्याज दरों के ढाँचे पर लगातार नजर रखेगी। हाल ही में बैंक जमागणियों पर दिये व्याज दर में वृद्धि की गई है। अब मैं अल्प वचना स्कीमों पर दिए व्याज की दरों के संबंध में इसी प्रकार का प्रभाव करता हूँ। हमारा अंतिम उद्देश्य सामान्य और वास्तविक दोनों ही व्याज दरों में महत्वपूर्ण कमी लाना है। यह सभी संभव हो सकेगा जब अगले तीन वर्षों में मुद्रास्फीति की दर में पर्याप्त रूप से कमी आ जाए।

16. वर्ष 1987-88 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री, स्वर्गीय श्री राजीव गान्धी ने इस सदन को आश्वस्त किया था कि पूँजी बाजारों के स्वस्थ विकास के वास्ते, निवेशकर्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए और व्यापारिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए सरकार स्टॉक एक्सचेंजों और प्रतिभूति उद्योग के नियमन तथा मुचारे कामकाज के लिए एक अलग बोर्ड स्थापित करेगी यद्यपि बोर्ड की स्थापना कर दी गई परन्तु दुर्भाग्यवश बोर्ड को पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान करने के लिए विधान अधिनियमित नहीं किया जा सका है। अब ऐसा तत्काल किया जाएगा और प्रतिभूति निधि (विनियमन) अधिनियम तथा कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक उपबंधों को प्रशामित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड को पूर्ण साविधिक शक्तियाँ प्रदान की जाएँगी। इन शक्तियों को पूँजी निर्माण नियंत्रक और सरकार से एक स्वतंत्र निकाय को सौंपने से इस देश में स्टॉक एक्सचेंजों के कामकाज को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने, प्रोत्साहित करने और सन्तुष्ट करने में मदद मिलेगी। स्टॉक एक्सचेंजों के संबंध में व्यापार पैकेज, जिसमें राष्ट्रीय निकामी और समझौते की एक प्रणाली तथा एक केन्द्रीय गैरह स्थल की संस्थापना करना शामिल है, पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

17. पारस्परिक निधियों के संबंध से एक प्रतियोगी ढाँचा विकसित करने की दिशा में विछले कुछ वर्षों में कुछ प्रगति हुई है और उसके उत्साहजनक परिणाम निकले हैं। बहुत

से निवेशकर्ताओं के लिए, श्रेयों के प्रत्यक्ष स्वामित्व की तुलना में पारस्परिक निधियाँ अधिक उपयुक्त निवेश साधन हैं। सरकार, पारस्परिक निधियों के माध्यम से पेश की जाने वाली इनिश्टी संवद्ध वचना स्कीमों के लिए पहले ही कर रिवायनों प्रदान कर रही है। सरकार ने अब निजी क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र पारस्परिक निधियों के लिए इस क्षेत्र को सुजा छोड़कर पारस्परिक निधियों के विकास को और प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। निवेश करने वाले लोगों के हितों की सुरक्षा करने तथा पूँजी बाजार के स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सभी पारस्परिक निधियों के परिवर्तन के लिए व्यापक मार्गदर्शी रूपरेखाएँ विकसित की जा रही हैं। इस प्रयोजन के लिए एक विधान अधिनियमित करने पर भी विचार किया जाएगा।

18. अनिवासी भारतीय निवेशकर्ताओं से संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं को व्यापक रूप से समीक्षा की जाएगी तथा उनमें और ढील दी जाएगी ताकि अनिवासी भारतीयों द्वारा शीघ्रोगिक व अन्य उद्यमों की स्थापना किए जाने में सभी बाधाओं और सभी प्रक्रियात्मक कठिनाईयों को दूर किया जा सके। अनिवासी भारतीयों के लिए अप्रत्यावर्तन आधार पर निवेश करने के लिए नए क्षेत्र उपलब्ध कराये जाएँगे जिनमें आवास, आधारभूत ढाँचा तथा अचल संपत्ति का विकास शामिल है। उदाहरणार्थ आजकल विदेशी राष्ट्रीयता वाले अनिवासी भारतीयों को रिहाइशी संपत्ति प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (फेरा) की धारा 31 के अंतर्गत विशिष्ट अनुमति प्राप्त करनी होती है। अब प्रस्ताव है कि ऐसे व्यक्तियों को इस उपबंध में सामान्य रूप से छूट दे दी जाए। तथापि, ऐसे आवास की बिक्री से प्राप्त राशि तथा किराये की आमदनी अप्रत्यावर्तनीय होगी। अनिवासी भारतीयों के लिए एक केन्द्रीय विन्धु के रूप में कार्य करने के वास्ते केन्द्रीय सरकार के साथ परस्पर विचार-विमर्श को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सरकार का प्रस्ताव अनिवासी भारतीयों के लिए एक मुख्य आयुक्त नियुक्त करने का है। मैं राज्य सरकारों से भी अनिवासी भारतीयों के लिए आयुक्त का एक कार्यालय स्थापित करने का आग्रह करूँगा।

19. मुझे विश्वास है कि अब समय आ गया है कि ऐसे क्षेत्रों में टैरिफ और घरेलू कीमतें निर्धारित करने के लिए अधिक स्पष्ट संस्थागत साधन अपनाये जाएँ, जहाँ अब भी भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने तथा प्रशासित कीमतों के निर्धारण की आवश्यकता होगी, विशेषकर सार्वजनिक उपयोग के क्षेत्र में इस उद्देश्य के लिए हमें औद्योगिक लागत और मूल्य व्यौरों का पुनर्गठन करने और इसे एक टैरिफ आयोग में परिवर्तित करने पर विचार करना चाहिए।

20. अब जबकि हम 20वीं सदी के अंतिम दशक में प्रवेश कर रहे हैं। भारत एक अजीब स्थिति में आ पहुँचा है। इस स्थिति में हम जो निर्णय लेते हैं और जो निर्णय नहीं लेते हैं, उन्हीं पर आने वाले काफी समय तक भाविष्य

निर्धारित होगा। इसलिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमें किस रास्ते को अपनाना चाहिए, इस विषय पर देश भर में पर्याप्त रूप से चर्चा हो। एक लोकतांत्रिक समाज में यह अन्यथा नहीं हो सकता हम इस चर्चा से क्या प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सामने जो बात स्पष्ट रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वह यह है कि अगर हम अपनी योजना प्रक्रिया को छोड़ दें तो हम एक व्यापारिक समाज की स्थापना करने का अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। परन्तु, भारत का भावी विकास इस बात पर अत्यंत निर्भर करता है कि योजना प्रक्रिया को कितने अच्छे ढंग से, तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाता है। मेरा विश्वास है कि अपने समाज के संसाधनों के अपनी अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग और सुव्यवस्थित समन्वय के बिना, विकास असंतुलित रहेगा इससे न्याय के लम्बे अर्से से संजोए गए मूल्यों का उल्लंघन होगा और इससे भारत अपनी सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक क्षमता से नीचे ही रहेगा। परन्तु हमारी योजना प्रक्रिया एक गतिशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के प्रति संवेदी होनी चाहिए। आर्थिक प्रक्रियाओं के अत्यधिक केन्द्रीयकरण तथा नींकरशाही के कारण इनके परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं। हमें बाजार प्रणालियों के प्रचालन के लिए संभावनाओं और क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता है। मात्रात्मक नियंत्रण की अपेक्षा एक सुधरी हुई मूल्य प्रणाली, साधनों के आवंटन का एक उत्तम साधन हो सकती है। परन्तु, बाजार केवल उनकी सेवा कर सकता है, जो बाजार प्रणाली के अंग हैं हमारे देश में अधिकांश लोग अस्तित्व बनाए रखने की अर्थव्यवस्था में रहते हैं। हमें प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप के विश्वसनीय कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जो इन लोगों की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करे। हम पर उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने योग्य पानी और सब्जों जैसी अच्छी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने की जिम्मेदारी है। इस प्रकार परिवहन संचार और उर्जा जैसे पूंजीगत और गहन प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र के विकास, जो लम्बी अवधि वाले हैं, को पहले से अधिक ध्यानपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होगी। भूमि और जल का अपक्षरण जो इस देश के लाखों गरीब लोगों को जीविका के लिए एक खतरा है, उस पर नियंत्रण करने के लिए भी प्रभावी सरकारी नेतृत्व और कार्यवाई की आवश्यकता होगी।

21. हम जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं, वह अभूतपूर्व है। पश्चिमी विश्व में अपने प्रारंभिक चरण में औद्योगिक क्रान्ति में सामाजिक दुर्दशा एवं अन्याय को ध्यान में रखे बिना, जो इस प्रक्रिया के लक्षण थे, केवल धन-अर्जित करने पर ही अधिक बल दिया गया। शासन-तंत्र का लोकतंत्रीकरण काफी बाद में हुआ। अल्प-विकसित अर्थव्यवस्था के त्वरित औद्योगिक परिवर्तन के लिए नया मार्ग बनाने में समाजवादी प्रयोग और शासन व्यवस्था ने, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ जैसे देशों में प्रौद्योगिकीय और सैनिक क्षमताएँ विकसित करने, त्वरित औद्योगिक विकास और मानव संसाधनों के विकास के लिए पूंजी के संग्रहण में काफी सफलता

प्राप्त की है। परन्तु हाल ही की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि इस दृष्टिकोण में भी, विशेषरूप से तकनीकी परिवर्तन के प्रबन्ध में इसकी विभाजक कार्यकुशलता, परिवर्णात्मक ऋास पर नियंत्रण और व्यक्तियों की विशाल अन्तर्निहित शक्ति और प्रतिभा का उपयोग करने में, अनेक कमियाँ हैं। भारत में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक प्रयोग प्रारंभ किया था—एक ऐसे प्रयोग जिसका उद्देश्य अपनी पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था को तीव्र गति से विकसित करने के लिए विभिन्न प्रणालियों की अच्छाइयों और गुणों को एकीकृत करना था। हमें विकास, आधुनिकीकरण और उन्नत सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिली है। लेकिन, हम इन सभी क्षेत्रों में अभी भी अपनी पूरी क्षमता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हमें, लोकतांत्रिक प्रणाली के मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा पर अडिग रहते हुए, इस अधूरे काम को पूरा करना है।

22. इसके साथ ही, हमें धन अर्जित करने तथा विकास प्रक्रिया में इसके समुचित स्थान को समझना चाहिए। क्योंकि इसके बिना, हम अत्यधिक गरीबी, अज्ञानता तथा बीमारी के कलंक को दूर नहीं कर सकते। लेकिन, हम धन अर्जित करने की प्रक्रिया में सामाजिक दुर्दशा और अन्याय को अपरिहार्य बुराइयों के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। मौजूदा समय की मूल चुनौती, इस बात को सुनिश्चित करना है कि धन अर्जित करने के कार्य को न केवल समानता और न्यायोचित ढंग से किया जाए, बल्कि इसका उपयोग सभी की गरीबी दूर करने और विकास करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाए।

23. धन के सृजन के लिए हमें पूंजी के संचय को बढ़ावा देना चाहिए। इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि मितव्ययता बरती जाए। हमें उन लोगों के रास्ते की बाधाओं को भी दूर करना होगा जो धन का सृजन करने में जुटे हैं। इसके साथ ही, हमें धन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित करना होगा। अंतिम विश्लेषण के तौर पर, सभी धन संपत्ति एक सामाजिक उत्पाद है। जो इसका सृजन करते हैं और इसके स्वामी हैं, उन्हें इसे एक न्याय के रूप में रखना चाहिए तथा इसका उपयोग समाज, विशेष रूप से जो असुविधाप्राप्त और साधनहीन है, के हित में करना चाहिए। वयों पहले, गांधी जी ने न्यासधारिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए। गांधीजी जिस मितव्ययता का व्यवहार करते थे और जिसका उपदेश देते थे, वह लोकतांत्रिक राजनीति के ढाँचे में त्वरित आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है। संपत्ति धारकों के लिए उन्होंने जिस न्यासधारिता का निर्धारण किया था, उसमें सामाजिक जिम्मेदारी का सिद्धांत शामिल था।

24. सुधार की महत्ता पर प्रकाश डालने का मेरा उद्देश्य अविवेकपूर्ण और हृदयहीन उपभोक्तावाद को प्रोत्साहित करना नहीं है, जो हमने पश्चिम की समृद्ध समाज से उधार लिया है। उपभोक्तावाद प्रवृत्ति के संबंध में मुझे दो आपत्तियाँ हैं। पहली तो यह कि हम इसे वहन नहीं कर सकते। एक ऐसे समाज में, जहाँ हमें पीने के पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य बुनियादी आवश्यक वस्तुओं की कमी है, यह दुख की बात होगी कि हमारे उत्पादक संसाधनों का उपयोग मुख्यतः एक छोटे संवर्ग की आवश्यक-

कनाओं को पूरा करने के लिए किया जाए। हमारे देश में गीने और मिवाई के लिए पानी, ग्रामोण सड़कों, गच्छे शहरी डांचे तथा गरीबों के लिए प्राथमिक शिक्षा, और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं हेतु, वड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता इतनी अधिक है कि उन्नत औद्योगिक सोमायदियों की तकल पर, उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना प्रभावी ढंग से बंद किया जाना चाहिए। विकास के प्रति हमारे दृष्टिकोण में कार्यकुशलता और मितव्ययता दोनों पर ही जोर दिया जाना चाहिए। मितव्ययता से हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि जीवन का अभावग्रस्त अथवा शुष्क और नीरम बनाया जाए जो खुशी और हंसी की तरफ पीड़ाभय दृष्टि से देखे। मेरे विचार में, हमारे इस प्राचीन देश में निर्धनता, भुखमरी तथा बीमारी को समाप्त करने के एक उत्तम उद्देश्य के प्रयास में मितव्ययता समाज को एक जुट रखने का एक उपाय है।

25. अब मैं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजकोपीय समायोजन की चर्चा करूंगा। अर्थव्यवस्था में राजकोपीय असंतुलन को दूर करने की शुरुआत व्यय में कटौती और सरकार की आय में वृद्धि करके की जानी चाहिए जिससे कि राजकोपीय घाटे को कम किया जा सके। तथापि, बीच की इस अवधि में, हमारी राजकोपीय व्यवस्था तभी समर्थ बन सकेगी, यदि राजस्व प्राप्तियों से न केवल राजस्व व्यय की पूर्ति हो, बल्कि ऐसे क्षेत्रों के लिए पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए भी पर्याप्त अधिशेष की व्यवस्था हो सके, जिनसे प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिकूल प्राप्त नहीं होते, जैसे कि रक्षा या सामाजिक क्षेत्र। यदि बजट में निवेश संबंधी व्यय से पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती तो इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। हमारी राजकोपीय व्यवस्था के संरचनात्मक असंतुलनों को दूर करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के समानुपात में राजकोपीय घाटे तथा राजस्व घाटे दोनों में ही कमी करने की आवश्यकता होगी। केन्द्रीय सरकार का वर्ष 1991-92 का बजट इस दिशा में एक जरूरी पहला कदम है।

26. इस बात को मानना होगा कि वर्ष 1991-92 के दौरान राजकोपीय घाटे में आवश्यक कटौती करना एक अनि कठिन कार्य है। मार्च, 1991 में संसद में रण किये गये अंतरिम बजट में 38,475 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया गया था। लेकिन यह अनुमान कुछ ऐसे निर्णयों की धारणाओं पर आधारित था जिन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है। नियमित बजट को निलम्बित करने से यह कार्य और भी कठिन हो गया क्योंकि उस वित्तीय वर्ष के लगभग चार महीने किसी भी राजकोपीय सुधार के बिना ही गुजर गए हैं। वास्तव में, राजस्व और व्यय की पिछली प्रवृत्तियों से पता चलता है कि हमारी तरफ से सुधारात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने पर, 1991-92 के दौरान राजकोपीय घाटा 52,000 करोड़ रुपये से भी अधिक के स्तर तक पहुंच सकता है। आंकड़ों के दोनों स्रोतों के बीच के अंतर से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यक राजकोपीय सुधार की वास्तविक मात्रा का पता चलता है।

27. उपलब्ध अंतरिम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1990-91 के लिए अल्पावधिक राजकोपीय हंडियों के माध्यम उधारों द्वारा यथामानि 11,430 करोड़ रुपये का बजटीय घाटा, 10,722 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से काफी अधिक था, जो राजस्व में, विशेष रूप से कंपनी कर, राजस्व में, भारी कमी के कारण था। इससे उस बाधा का पता चलता है, जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं। अब मैं वर्ष 1991-92 की स्थिति का अल्लेख करूंगा।

28. आयोजना-भिन्न व्यय के बढ़ते स्तर के कारण, जिन उधार लेकर वित्तपोषित किया गया है, सरकार द्वारा की जाने वाली व्याज की अदायगियों में घातीय वृद्धि हुई है। वर्ष 1990-91 के दौरान 21,850 करोड़ रुपये की व्याज अदायगी के संशोधित अनुमान केन्द्रीय सरकार की निवल राजस्व प्राप्तियों का 38 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 1991-92 के दौरान 27,450 करोड़ रुपये की अनुमानित व्याज अदायगियां, मौजूदा कर की दरों पर केन्द्रीय सरकार की निवल राजस्व प्राप्तियों का 42 प्रतिशत हिस्सा है। यदि मौजूदा प्रवृत्ति जारी रही और कई सुधार संबंधी उपाय न किए गये तो वर्ष 1994-95 तक व्याज की अदायगियां केन्द्रीय सरकार की निवल राजस्व प्राप्तियों के 50 प्रतिशत हिस्से से भी अधिक हो जाएंगी। इन परिमाण और अनुपातों से स्थिति की गंभीरता और आगामी तीन वर्षों के दौरान आयोजना-भिन्न व्यय में भारी समायोजन किये जाने की अत्यधिक आवश्यकता का पता चलता है।

29. वर्ष 1990-91 के कुल आयोजना-भिन्न व्यय का संशोधित अनुमान 76,761 करोड़ रुपये था। सामान्य तौर पर, अत्यधिक सख्ती में जांच करने के बाद भी, लेकिन व्यय को कम करने के लिए विनिर्दिष्ट उपायों के अभाव में, 1991-92 में यह आयोजना-भिन्न व्यय बढ़कर 89,000 करोड़ रुपये हो गया होता। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजकोपीय सुधार का कोई भी प्रयास तभी सार्थक होगा, यदि आयोजना-भिन्न व्यय में उस स्तर में, कम से कम 10 प्रतिशत की कमी कर दी जाए, जहां यह अथवा पहुंच जाएगा।

30. आयोजना-भिन्न व्यय का अकेला सबसे बड़ा घटक व्याज अदायगियां हैं। अगर इस वर्ष के दौरान सरकार के उधार में आमूल कटौती कर दी जाती है, फिर भी अगले वित्तीय वर्ष में व्याज अदायगियां 35,000 करोड़ रुपये के आस पास होंगी। तीन वर्षों के लिए सरकारी उधार में सख्त अनुशासन के माध्यम से ही 1994-95 तक व्याज अदायगियों की घातीय वृद्धि पर कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है।

31. आयोजना-भिन्न व्यय का दूसरा सबसे बड़ा घटक रक्षा क्षेत्र के लिए आबंटन है, जहां वर्ष 1990-91 के संशोधित अनुमानों में 15,750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। अगर रक्षा पक्ष को छोड़ दिया जाए, तो आयोजना-भिन्न व्यय में कमी करने का प्रयास सफल नहीं हो सकता। इसके साथ-साथ, यह सुनिश्चित करना भी अत्यन्त आवश्यक है कि व्यय में कमी करने के प्रयास से राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव न पड़े। इसलिए, हम रक्षा सेवाओं की कार्यकुशलता और कारगरता को कम किए बिना व्यय को सीमित करना चाहते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, चालू वर्ष में रक्षा के लिए 16,350 करोड़ रुपये के परिचय की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है।

32. माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि 3 जुलाई, 1991 से निर्यात संबंधी आर्थिक सहायता समाप्त कर दी गई है। विनियम दर में समायोजन और प्रतिपूर्ति लाइसेंसिंग प्रणाली के विस्तार द्वारा, जो जुलाई के प्रारंभ में कार्यान्वित की गई थी, निर्यात क्षेत्र की पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति की जा रही है। फलस्वरूप, पहले की गई 4,200 करोड़ रुपये की अनुमानित आवश्यकता को तुलना में वर्ष 1991-92 के बजट अनुमानों में निर्यात संबंधी आर्थिक सहायता के लिए अब केवल 1,224 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, जिससे इस वर्ष की शेष अवधि के दौरान 3,000 करोड़ रुपये तक की राशि की बचत होगी।

33. जहां तक उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता का संबंध है, आज की शाम से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट और पोटाश के सल्फेट जैसे निम्न विश्लेषण उर्वरक, मूल्य और आवागमन संबंधी नियंत्रणों से मुक्त होंगे। अन्य सभी उर्वरकों के मूल्य में औसतन 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, एकल सुपर फास्फेट के मामले में उत्पादकों को प्रति टन देय आर्थिक सहायता की भी सीमा निर्धारित की जाएगी, ताकि अगले कुछ वर्षों में पूर्ण विनियमन की ओर जाया जा सके। यह सभी उच्च लागत वाली इकाइयों की लागत कम करने और क्षमता में सुधार करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा। इस संबंध में आवश्यक अधिमूचनाएं आज कृषि मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जा रही हैं।

34. उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि के लिए आर्थिक तर्क अत्यन्त स्पष्ट है और इसका विस्तार से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, मैं सदन का ध्यान हम नरय की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जुलाई, 1981 से उर्वरकों के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इन वस वर्षों में कृषि क्षेत्र को प्राप्त हुई धान और गेहूं के खरीद मूल्य और अन्य फसलों के बाजार मूल्यों में भी लगातार वृद्धि हुई है। वसूली मूल्यों में उपर्युक्त वृद्धि करके, उर्वरकों की कीमतों में प्रस्तावित वृद्धि के लिए किसानों की क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी।

35. हम यह भी सुनिश्चित करने रहेंगे कि आयोजना संसाधनों का 50 प्रतिशत भाग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में निवेशित किया जाए। छोटे और सीमांत किसानों के लिए कुए खोदने तथा छिछले नलकूपों के लिए सहायता देने की चल रही योजनाओं के लिए व्यवस्था दुगुनी कर दी जाएगी। दुर्गम क्षेत्रों में जहां जन स्तर बहुत नीचा है, सहायता की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, पीने योग्य पानी, खारे पानी, जनवर पालन और तेलहनों व दालों के उत्पादन के लिए सहायता की व्यवस्था में पर्याप्त वृद्धि कर दी जाएगी। छोटे ट्रैक्टरों और इसी प्रकार के उपकरणों, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई और कम पैदावार वाले क्षेत्रों में अच्छे किस्म वाले बीजों को लोकप्रिय बनाने के लिए नई योजनाएं बनाई जा

रही हैं। इस खरीफ मौसम में कार्यान्वित की जाने वाली एक अन्य नई योजना, रापर सकारों गहू पानी विधियों और किसानों के समूह को पाई से मुक्त के भुगतान पर कपास अथवा दालों की फसल के अन्तर्गत पता लगाए गए बड़े क्षेत्रों में मुख्य पीछे संरक्षण प्रदान करने के संबंध में है। इन क्षेत्रों में एकीकृत कीट प्रबंध के जान का प्रदर्शन करना भी संभव होगा। उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के फल-स्वरूप उत्पादन में संभावित किसी गमी, और खपत में कमी से बचने के लिए ऋण संबंधी ऋणों को सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को ऋण की पर्याप्त उपलब्धता विशेष रूप से सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही संपूर्ण देश में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं और कृषि सलाहकार सेवाओं को मजबूत बनाया जाएगा, ताकि उर्वरकों के प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित किया जा सके और जैव-उर्वरकों को लोकप्रिय बनाया जा सके। हम ऐसी कुछ सिंचाई परियोजनाओं का भी पता लगाएंगे जिन्हें इसी वर्ष पूरा किया जा सके और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जाए। अन्य नई योजनाओं को भी धन का अभाव महसूस नहीं होने दिया जाएगा। जहां तक संभव होगा हमारा बल किसानों की अच्छी सेवाएं उपलब्ध करवाने पर होगा, न कि गहूतों और आर्थिक सहायता पर।

36. चीनी में संबंधित आर्थिक सहायता, जिसमें राजकोष पर प्रतिवर्ष 350 करोड़ रुपये का बोझ पड़ रहा है सचमुच एक विपथन है, जो हमारी प्रणाली में जनवरी, 1990 से प्रभावी हुई है, जबकि उत्पादकों को अदा किया जाने वाला वसूली मूल्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उप-भोक्ताओं के लिए निर्गम मूल्य में वृद्धि द्वारा प्रतिसंशुलित नहीं किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत, अधिकांशतः महानगरीय और शहरी क्षेत्रों में 5.25 रु. प्रति किलोग्राम की दर पर चीनी की अंतर मात्रा उपलब्ध कराई जाती है, जबकि बाजार में अधिकांश व्यक्ति 10 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत अदा करते हैं। सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस आर्थिक सहायता को तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप आज शाम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी का निर्गम मूल्य 85 पैसे प्रति कि.ग्रा. बढ़कर 6.10 प्रति किलोग्राम हो जाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है ताकि यह कमजोर वर्गों, विशेषकर ग्रामीण निर्धनों की चावल और गेहूं जैसी खाद्यान्नों की बुनियादी आवश्यकताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए और अधिक कारगर ढंग सेवा कर सके। चारू वर्ष में खाद्यान्न संबंधी आर्थिक सहायता की व्यवस्था बढ़ाकर 2,600 करोड़ रुपये की जा रही है, जबकि अन्तरिम बजट में केवल 1,800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी तथा 1990-91 के संशोधित अनुमानों में 2,450 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

37. विभिन्न वर्गों में समायोजन के फलस्वरूप, जो जुलाई, 1991 के शुरू में किए गए थे, कच्चे तेल और

पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात बिल की मर्यादों में कमी में वृद्धि होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की जाए। इसमें पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि को रोकने में भी सहायता मिलेगी। मोटर स्पिडिट, घरेलू एल.पी.जी. और देश के अन्दर उपयोग के लिए विमानन टरबाइन ईंधन की कीमत में 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। डीजल तथा गैर-औद्योगिक उपयोग के लिए केरोसीन को छोड़कर अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। गैर औद्योगिक उपयोग के लिए केरोसीन की कीमत 10 प्रतिशत कम कर दी जाएगी, जिसका अर्थ यह है कि 15 अक्टूबर, 1990 से लागू कीमत में वृद्धि की दृष्टि से 50 प्रतिशत तक वापस जाना। सर्वाधिक कार्टन वित्तीय स्थिति में भी ऐसा गरीबों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, जिनके लिए केरोसीन, प्रकाश और ईंधन का एक अनिवार्य स्रोत है। यद्यपि डीजल की कीमत में कोई वृद्धि नहीं होगी, मैं किसानों के हितों की रक्षा करने का भी प्रयास करूंगा, जो डीजल का उपयोग करते हैं और इस प्रयोजन के लिए मैं राज्य सरकारों के साथ चर्चा करता हूँ। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में प्रस्तावित वृद्धि इस शाम में प्रभावी हो जाएगी और इस संबंध में आवश्यक अधि-सूचना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जा रही है।

38. व्याज अदायगियों, रक्षा और आर्थिक सहायताओं को छोड़कर आयोजना-भित्त व्यय के संबंध में 1991-92 के बजट अनुमानों में 28,073 करोड़ रुपये को कुल व्यवस्था 1990-91 के संशोधित अनुमानों में की गई व्यवस्था की तुलना में 1,538 करोड़ रुपये की कमी दर्शाती है। यदि हम इस तथ्य को ध्यान में रखें कि चालू वर्ष में मंत्रालयों और विभागों द्वारा मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों के भुगतान के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई है, तो ऐसे अन्य आयोजना-भित्त व्यय में कुल कमी 2,000 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी। हाल के वर्षों में, मंत्रालयों को अनुदेश जारी करने की यह एक सामान्य प्रथा रही है कि इस प्रकार की अतिरिक्त आवश्यकताओं को अनुमोदित बजट अनुमानों में से ही पूरा किया जाना चाहिए। इससे अनिवार्य रूप से योजना पक्ष में संबंधित कुछ कार्यक्रमों को उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं। मेरा इरादा आयोजना-भित्त प्रशासनिक व्यय में अधिकतम संभव मितव्ययिता लागू करने का है। अतः सभी मंत्रालयों में अपने-अपने कार्यक्रमों की प्राथमिकताएं निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है, ताकि जो प्राथमिकताएं सूची में सबसे नीचे हैं, उनके लिए कम व्यवस्था की जाए, जबकि जिनकी उपयोगिता अत्यंत हो चुकी है उनके लिए व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। सभी मंत्रालयों द्वारा इस दिशा में प्रयास पहले ही प्रारंभ किए जा चुके हैं और यह कार्य अगस्त, 1991 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है। इस दृष्टिकोण से, अन्य आयोजना-भित्त व्यय में प्रस्तावित कमी, जिसका मैं सदन के समक्ष वायदा कर रहा हूँ, योजना कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था में कमी किए बिना और अधिक सार्थक तरीके से लागू की जाएगी।

1863 GI/91-2

39. आयोजना-भित्त व्यय का एक बड़ा घटक और है, जो राजकोष पर भार है। मैं ग्रामीण ऋण राहत स्कीम के अन्तर्गत सरकार की बाध्यता का उल्लेख कर रहा हूँ। दुर्भाग्यवश, पिछले वर्ष लागू की गई इस स्कीम के अन्तर्गत कुल राजकोषीय देयता के संबंध में बहुत कम अनुमान लगाया गया था। पिछले वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों में उपलब्ध कराई गई 1,500 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त हमें 1990-91 वर्ष में 1,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी है। लेकिन, इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अगले वर्ष के लिए भी इतनी ही राशि की व्यवस्था करनी होगी।

40. व्यय के क्षेत्र में प्रमुख समायोजनों के परिणाम-स्वरूप, जिनका मैंने अपने भाषण में उल्लेख किया है, वर्ष 1991-92 में कुल आयोजना-भित्त व्यय के लिए बजट अनुमान 79,697 करोड़ रुपये है। व्याज अदायगियों को अन्तर्भाव में कम करना सम्भव नहीं है। व्याज अदायगियों को छोड़कर, चालू वर्ष के लिए आयोजना-भित्त व्यय में की गई व्यवस्था, 1990-91 के संशोधित अनुमानों में की गई व्यवस्था की तुलना में 4.9 प्रतिशत की कमी दर्शाती है, और जो व्यवस्था इस वर्ष के लिए की जानी थी, उसकी तुलना में लगभग 15 प्रतिशत की कमी दर्शाती है, लेकिन ऐसा लागू किए जा रहे विभिन्न उपचारत्मक उपायों के कारण संभव हुआ है। इस प्रकार हमारे आयोजना-भित्त व्यय में 10 प्रतिशत की कमी करने की अपनी वचनबद्धता पूरी कर दी है, जिसका हमारे घोषणापत्र में उल्लेख किया गया था।

41. कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में विकास संबंधी हमारी कार्यनीति में विशेष बल वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इनमें रोजगार कार्यक्रमों में पर्याप्त वृद्धि करना समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवासीय इकाइयों का निर्माण, सिंचाई वाले कुओं के लिए कार्यक्रम का विस्तार आदि शामिल हैं। इसके लिए आयोजना प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने और कुछ मामलों में उनके पुनः निर्धारण करने की आवश्यकता होगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश और गरीबों के लाभ के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के लिए व्यय पर अधिक बल दिया जा सके। निस्सन्देह, हमारी कार्य नीति, पहली अप्रैल, 1992 में शुरू होने वाली आठवीं पंचवर्षीय योजना में परिचालित होगी। इसका यह अर्थ होगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज को इस कैबिनेट वर्ष के अन्त तक अंतिम रूप दे दिया जाए ताकि 1992-93 के लिए वार्षिक योजनाओं के साथ-साथ उस वर्ष के लिए केन्द्रीय और राज्यों के बजटों में बदली हुई प्राथमिकताओं को दर्शाया जा सके।

42. चूंकि पहले जेथानुदान केवल प्रथम चार माह के व्यय को पूरा करने के लिए लिया गया था, इसलिए यह बजट जुलाई, 1991 के अन्त से पहले प्रस्तुत किया जाना था। इसलिए 1991-92 के लिए वार्षिक योजना का पुनः निर्धारण करने के लिए हमारे पास समय नहीं था, जिसमें हमारी विभिन्न प्राथमिकताओं को पूरी तरह से परिलक्षित किया

जा सके। इसके अलावा, इस वर्ष की वार्षिक योजना का भारी राजकोषीय उपचारात्मक उपायों के संदर्भ में समायोजन करना पड़ा है, जिन पर हमें अमल करना है। वस्तुतः पहले यह अनुभव किया गया था कि केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट समर्थन और राज्यों के लिए केन्द्रीय आयोजना सहायता में पर्याप्त कमी करना आवश्यक होगा। तथापि, सदन को यह सूचित करने हुए मुझे खुशी है कि आयोजना-भिन्न व्यय में प्रस्तावित पर्याप्त कटौतियों के फलस्वरूप, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय आयोजना सहायता के प्रवाह को अब 14,710 करोड़ रुपये के स्तर पर बनाए रखना संभव होगा, जैसा कि 1991-92 के अंतिम बजट में दर्शाया गया है। तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र योजना परिव्यय 19,015 करोड़ रुपये के बजट समर्थन सहित 42,969 करोड़ रुपये के स्तर पर मामूली वृद्धि दर्शाता है।

43. मुझे इस बात का अहसास है कि विद्युत, कोयला, संचार और पेट्रोलियम जैसे मूल आधारभूत क्षेत्रों पर हमें और अधिक ध्यान देना होगा। वर्तमान स्थिति में, जबकि विशेषी मुद्रा की अत्यंत कमी है, यह विशेष रूप से आवश्यक है कि कोयले, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और विद्युतीय ऊर्जा के घरेलू उत्पादन में पर्याप्त रूप से वृद्धि की जाए। उद्योग, कृषि, परिवहन और घरेलू क्षेत्रों में और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ऊर्जा के उपयोग में सर्वाधिक किफायत को प्रोत्साहित करने के लिए भी त्वरित आधार पर प्रयास करने होंगे। पारेषण तथा वितरण लाइनों में होने वाली हानियों में भी भारी कटौती करनी होगी, जो इस समय 22 प्रतिशत तक के अत्यधिक स्तर पर हो रही है। एक बार स्थिति का सावधानीपूर्वक जायजा लेने के बाद हम इस काम पर ध्यान लगाएंगे। मुझे पूरी आशा है कि अब किए जा रहे राजकोषीय उपचारात्मक उपायों के फलस्वरूप तब तक साधनों की स्थिति में सुधार होने से हमें आवश्यक नम्यता प्राप्त हो जाएगी। इस समय मेरा प्रयास है कि राजकोष पर बाध्यकारी दबावों के बावजूद केन्द्रीय आयोजना के लिए उचित सहायता के माध्यम से आवश्यक निवेश बनाए रखे जाएं।

44. यह बजट तैयार करते समय, मैंने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है कि राजकोषीय समायोजन का भार राज्य सरकारों पर न पड़े। मेरा यह विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार को राजकोषीय उपचारात्मक उपाय लागू करके एक उदाहरण कथिम करना चाहिए और मुझे आशा है कि राज्य सरकारें भी इस दिशा में जितनी जल्दी संभव हो सकेगा, प्रयास करेगी। विशेषकर, मैं उनमें, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, कोल इंडिया और भारतीय रेलवे को राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा देय राशियों का भुगतान तत्काल किए जाने का अनुरोध करना चाहूँगा। हम राज्य स्तर के उद्यमों को केन्द्र से राज्यों को साधनों के अनियोजित और अनधिकृत अंतरण का माध्यम नहीं बनने दे सकते। यह न तो उचित है और न ही न्याय-संगत। अतः यह प्रथा तत्काल बंद की जानी चाहिए। इसके साथ ही राज्य सरकारों को अपने राजकोषीय निष्पादन को

सुधारने तथा अपने सरकारी उद्यमों की कार्यप्रणाली को कारगर बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्हें मुझसे यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मैं उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक में अनधिकृत ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने की अनुमति देकर राजकोषीय क्लिष्ट को पनपने दूँ। मैं चाहता हूँ कि वे देश की राजकोषीय स्थिति को सुधारने के कठिन कार्य में सक्रिय सहयोगी बनें।

45. वृहत आर्थिक समायोजन की प्रक्रिया, जिसे हम बजट के साथ शुरू किया जा रहा है, को पूरा होने में कम से कम तीन वर्ष लगेंगे। समायोजन का यह कार्य मानवीय ढंग से होना चाहिए। इसलिए परिवर्तन की इस अवधि के दौरान हम हर तरह से यह प्रयास करेंगे कि गरीबों पर इस समायोजन का कम से कम भार पड़े। कुछ सीमा तक गरीब लोगों पर भार कम ही पड़ेगा। जब मुद्रास्फीति की दर कम हो जाएगी। हम मुद्रास्फीति और मूल्यवृद्धि को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ प्रयत्न करेंगे। इस बजट की यह राजकोषीय नीति इस संबंध में मुख्य रूप से योगदान देगी। इसके अतिरिक्त, हमारा यह प्रयास रहेगा कि सामाजिक क्षेत्रों के लिए परिव्यय में वृद्धि करके गरीब लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करना, रोजगार के अवसर पैदा करना जैसे कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना जारी रहेगा। इसके साथ ही सरकार समाज के सर्वाधिक कमजोर और अमरुक्षित वर्गों के उत्थान के लिए वचनबद्ध है।

46. ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए आयोजना परिव्यय, जो पिछले वर्ष 3,115 करोड़ रुपये था, बढ़ाकर इस वर्ष 3,508 करोड़ रुपये किया जा रहा है। इसमें केवल रोजगार कार्यक्रमों के लिए 2,100 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। विभिन्न रोजगार संबंधी कार्यक्रमों में लगभग 90 करोड़ कार्य दिवस का रोजगार सृजित होने की संभावना है। यदि, इस वर्ष हम अपने घोषणापत्र में बताए गए 100 करोड़ कार्यदिवस के लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि वह अवधि, जिसमें ऐसे रोजगार की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, पहले ही समाप्त हो चुकी है। इस समय तैयार की जा रही आठवीं योजना में हमारी पार्टी के घोषणापत्र में उल्लिखित दीर्घावधिक रोजगार लक्ष्यों और सिंचाई कुओं के निर्माण जैसे लक्ष्यों, शहरी रैन-बसेरे और मूलभूत-शौचालयों तथा गांवों में निर्धन पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय इकाइयों का निर्माण करने के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक व्यापक नीति और कार्यक्रमों का उल्लेख होगा।

47. ग्रामीण जनपूर्ति योजना के लिए व्यवस्था को बढ़ाकर 758 करोड़ रुपये किया जा रहा है, जिससे वर्ष 1992-93 के अंत तक "स्त्रोतहीन समस्या वाले गांवों" को पूरी तरह से इसके अंतर्गत शामिल करने को सुनिश्चित करने के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था अलग से

की जा रही है। पहले यह आशा की गई थी कि इन सभी गांवों को आठवी योजनावधि के अंत तक शामिल कर लिया जाएगा। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी थी और इस प्रयोजन के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की थी। अब श्री राजीव गांधी के नाम पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। हम यह मुनिश्चित करेंगे कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों की कमी आड़े न आए।

48. यह बड़ी चिंता की बात है कि योजना प्रक्रिया के चार दशकों के पश्चात् भी मनुष्यों द्वारा मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को हम अभी तक समाप्त नहीं कर पाए हैं। इस कार्यक्रम के लिए विगत में भी अर्थात् राशि आवंटित की गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि न केवल शुष्क गांवों को बदलने संबंधी कार्यक्रम में लाई जाए, बल्कि सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास और उनके पुनः प्रशिक्षण के लिए आवंटन की राशि में भी वृद्धि की जाए। इस प्रयोजन के लिए, इस कार्यक्रम हेतु आवंटन की राशि में 25 करोड़ रुपए की वृद्धि कर दी गई है और आवश्यकता पड़ने पर वर्ष के दौरान और अधिक राशि की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए बड़ी हुई व्यवस्था को मिलाकर कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रमों के वास्ते कुल परिषय, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण से संबंधित है, की राशि 1990-91 की 364 करोड़ रुपए की राशि में बढ़ाकर 1991-92 में 479 करोड़ रुपए कर दी गई है। महिला और बाल विकास विभाग, जो हमारे निर्धन समाज के दो सर्वाधिक सुविधाहीन वर्गों का कार्य देखता है, के लिए पिछले वर्ष के 330 करोड़ रुपए के परिषय को बढ़ाकर इस वर्ष 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए मैं 1991-92 के लिए 1,051 करोड़ रुपए के आयोजन परिषय की व्यवस्था कर रहा हूँ, जबकि 1990-91 में यह राशि 950 करोड़ रुपए थी।

49. सामाजिक क्षेत्रों में निवेश के लिए संसाधनों का आवंटन मानव संसाधनों के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में मेरे लिए शिक्षा, विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर बल देने की आवश्यकता नहीं है। अव्यवस्था को मजबूत बनाने और उसका पुनर्निर्माण करने का हमारा प्रयास केवल तभी सफल हो सकता है, जब हम अपने लोगों के लिए निवेश करें। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक तथा सामाजिक तौर पर अन्य पिछड़ी जातियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रथम पीढ़ी के शिक्षा ग्रहण करने वाले वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि अबसर की समानता की सही अर्थों में महत्व देता है, तो अच्छी शिक्षा अमीर लोगों के बच्चों का ही विशेषाधिकार नहीं रहना चाहिए। सरकार यह मुनि-

श्चित करने के लिए बचनबद्ध है कि हमारे सामने चाहे जो भी बाधाएं हों, वित्तीय समर्थन के अभाव में शिक्षा के कार्यक्रम प्रभावित नहीं हों। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक निर्देश को हमारे 21वीं सदी में पहुँचने से पहले एक वास्तविकता बनाने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किए जाएंगे। उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, आधुनिकीकरण और विशिष्टीकरण के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता है, परंतु इसके साथ ही, इन संस्थाओं में किए गए वर्तमान निवेश में दृष्टान्त परिणाम प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं और हमें संसाधनों का पता लगाने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे। केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया गया बजट समर्थन एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है, परंतु यह एकमात्र स्त्रोत नहीं बने रह सकते। मैं 1990-91 में शिक्षा के लिए किए गए 865 करोड़ रुपए के आवंटन को बढ़ाकर 1991-92 में 977 करोड़ रुपए कर रहा हूँ। यह आवंटन शिक्षा के प्रति मेरी प्रबल बचनबद्धता और शिक्षा क्षेत्र को सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता के अनुरूप नहीं है। मैं इसमें भी अधिक करना चाहता था, परंतु हमें राजकोष पर दबाव के साथ रहना सीखना चाहिए।

50. विश्व में वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों की संख्या की दृष्टि से हमारा देश तीसरे स्थान पर है। फिर भी, हमारे देश में प्रौद्योगिकीय विकास न तो इस संख्या के और न ही उस निवेश के अनुरूप हुआ है, जो हम अपनी निरंतर पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकीय क्षेत्र के लिए करते रहे हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी नीति में उपयुक्त परिवर्तन करके हम अंतर को कम करना होगा और हमारे विकास की अपेक्षाओं के साथ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को अधिक घनिष्ठता से संबद्ध करके नई प्रौद्योगिकियों के बेहतर उन्नयन, उन्हें खपाने, अपनाने तथा अंगीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करना होगा। यह काम और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि हम अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी अर्थव्यवस्था के लिए तैयार कर रहे हैं।

51. सरकार ने पांच नए कदम उठाने का भी निर्णय लिया है। इनमें से पहला कदम पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक निगम स्थापित करना है, जिसे कांग्रेस के घोषणापत्र में पहले 100 दिनों में पूरा करने के लिए शामिल किया गया है। इस निगम के ढाँचे और कार्य को कल्याण मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसकी घोषणा इस सत्र की समाप्ति से पूर्व कर दी जाएगी।

52. सरकार पर्याप्त धनराशि के साथ एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि (नेशनल रीनियल फंड) स्थापित करेगी। इस निधि का मुख्य उद्देश्य यह मुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी परिवर्तन और उताड़क जपकरणों के आधुनिकीकरण की लागत की जिम्मेदारी कामगारों पर नहीं पड़े।

यह निधि सांसाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी, जो कामगारों को प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के प्रांत्कल परिणामों से सुरक्षा प्रदान करेगी। भेरा प्रनुमान है कि इस निधि की सहा से वद्धि होगी और राज्य सरकारें भी यथासमय इस निधि में अपना अंशदान करेगी। यह निधि तकनीकी परिवर्तन के दौरान प्रभावित कामगारों के लिए न केवल सुधारात्मक उपायों की व्यवस्था करेगी, बल्कि इसमें भी प्राधिकृत बात यह होगी कि उन्हें पुनः प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में एक लाभकारी उत्पादक भागीदार बनने की स्थिति में हो सकें।

53. तीसरा कार्यक्रम साम्प्रदायिक दंगा में प्रभावित परिवारों के बच्चों की देखभाल से संबंधित है। ये दंगे हमारे गणराज्य की स्वच्छ छवि पर एक धब्बा है। हमारी सरकार सभी धर्मा और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उन्नति के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। साम्प्रदायिक हिंसा का घटनाओं को बार-बार होने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल, दंगा पीड़ित परिवारों को अलग-अलग राशियों की क्षतिपूर्ति प्रदान करने की व्यवस्था है। परन्तु अनुभव यह दर्शाता है कि ऐसी क्षतिपूर्ति दंगा प्रभावित परिवारों के बच्चों के हितों की हमेशा रक्षा नहीं करती। ये बच्चे बाद में असंतुष्ट और असंगठित बयस्कों के रूप में बड़े होते हैं। वे प्रसामाजिक तत्वों और प्रतिक्रियावादी दकियानूसी, रुढ़िवादी तत्वों के प्रचार का सरलता से शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के हितों की रक्षा करने, उनके कल्याण, विशेषकर उनकी शिक्षा की देखरेख करने के लिए सरकार एक स्वायत्तशासी गैर-सरकारी संगठन के रूप में साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठान (नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्यूनल हार्मोनी) की स्थापना करने का इरादा रखती है। केन्द्रीय सरकार वर्ष 1991-92 में इस फाउंडेशन के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। मैं राज्य सरकारों तथा साथ ही उद्योग और व्यापार को इस अच्छे उद्देश्य के लिए उदारतापूर्वक योगदान देने के लिए आमन्त्रित करता हूँ।

54. चौथा कार्यक्रम, देश के प्रत्येक भाग से युवकों को बड़ी संख्या में देश के अन्य भागों में जाकर अल्पसंख्यक के लिए काम करने के योग्य बनाने और उन्हें विभिन्न धर्मों और भाषाओं के लोगों के साथ परस्पर मिलने का अवसर देने की एक योजना के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए है। इस दिशा में नवीवय विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसा कदम पहले ही उठाया जा चुका है। इसे अब सुदृढ़ किया जाएगा तथा राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तार किया जाएगा।

55. पांचवां कार्यक्रम दक्षिण—दक्षिण सहयोग के संबंध में संबंधित है। एक राष्ट्र के रूप में हम गुट-निरपेक्ष और अन्य विकास-शील देशों के साथ अपने विकास संबंधों अनुभव, ज्ञान और विशेष-ज्ञता को बांटने और निकट सहयोग करने के लिए वचनबद्ध हैं। भारतीय वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, इंजीनियरों, शिक्षकों सामाजिक

कार्यकर्ताओं और किसानों के लिए इस बात की काफी गंजाइश है कि वे तृतीय विश्व में विकास प्रक्रिया में अपना योगदान कर सकें। विभिन्न क्षेत्रों में हमारा अनुभव, विशेषकर एशिया और अफ्रीका में बहुत से विकासशील देशों के लिए अत्याधिक प्रासंगिक और सहायक हो सकता है। हमें उम्मीद है कि प्रांत्कल वार्षिक में हम कम से कम 500 स्वयंसेवकों को चुने हुए देशों में, विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्य में भाग लेने के लिए भेज सकेंगे। इस कार्यक्रम का विस्तृत व्यौरा तैयार किया जाएगा और इस सत्र की समाप्ति से पूर्व इसकी घोषणा कर दी जाएगी।

56. इस सदन को यह जानकारी भी प्रसन्नता होगी कि तंजानिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति डा. जुलियस के न्यरेरे की अध्यक्षता वाले “दक्षिण आयोग” की सिफारिशों स्वीकार करके, दक्षिण-दक्षिण सहयोग के समर्थन में जनमत जुटाने और इस संबंध में ठोस कार्रवाई कार्यक्रम बनाने के लिए हमारी सरकार को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित करने का हमारा प्रस्ताव है। इस समिति में सरकार, व्यापार और उद्योग, श्रमिक संघों और बुद्धिजीवी व्यवसायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

57. अपने महान नेता राजीव गांधी की यादगार को बनाए रखने के वास्ते तथा उन आदर्शों और उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए जिनके लिए वह जीवन रहे तथा अपना जीवन बलिदान कर दिया राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना की गई है। यह फाउंडेशन अन्य बातों के अलावा विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित कार्रवाई कार्यक्रम, साक्षरता के प्रचार-प्रसार, पर्यावरण की सुरक्षा, साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन, कम मुद्रिधा प्राप्त व्यक्तियों, स्त्रियों और विकलांग व्यक्तियों के उत्थान, प्रशासनिक सुधार तथा विश्व-प्रार्थ-व्यवस्था में भारत की भूमिका पर विशेष रूप से जोर देगा। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में तथा फाउंडेशन के सगहनोद्य उद्देश्यों के समर्थन में सरकार ने चालू वर्ष से शुरू करके पांच वर्ष की अवधि के लिए 20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए का अंशदान करने का निर्णय किया है।

58. इन नये कार्यक्रमों में से प्रत्येक आवश्यक ठीक-ठीक राशियों का निर्धारण हो जाने तक, वित्त मंत्रालय के योजना परिषद में 250 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि की व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

59. 1991-92 के लिए कुल 1,13,422 करोड़ रुपये के व्यय की बजट व्यवस्था की गई है, जिसमें से 79,697 करोड़ रुपए योजना-भित्त व्यय तथा 33,725 करोड़ रुपए योजनागत व्यय के लिए है।

60. राजस्व प्राप्तियों के क्षेत्र में, कराधान की मौजूदा दरों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 66,218 करोड़ रुपए का सकल कर-राजस्व प्राप्त होने के अनुमान है जबकि, इसकी तृजना पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों

में यह राशि 58,916 करोड़ रुपये थी। 1991-92 में राज्यों को करों में से उनके हिस्से के रूप में 15,643 करोड़ रुपये की अदायगी की जाएगी जबकि 1990-91 के लिए संशोधित अनुमानों में यह राशि 14,535 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार, केन्द्र की निवल राजस्व प्राप्तियाँ, जिनमें कर भिन्न राजस्व शामिल है, 1991-92 में बढ़कर 65,524 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि 1990-91 में यह राशि 57,381 करोड़ रुपये थी।

61. पंजीगत प्राप्तियों के क्षेत्र में, इस वर्ष बाजार उधार को राशि 7,500 करोड़ रुपये होगी जो कि पिछले वर्ष की 8,000 करोड़ रुपये की राशि से कम है। यह केन्द्रीय सरकार के उधारों को कम करने लिए ठोस प्रयासों का एक भाग है, जो वरना पिछली प्रवृत्तियों के अनुसार लगभग 10 प्रतिशत और अधिक हो गई होती। लघु बचत के निवल संग्रहण से 8,000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों के बराबर ही है। इसके अनिश्चित, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के चुनौती उपक्रमों में से अपनी इक्विटी का 20 प्रतिशत भाग का विनिवेश करके उसे सरकारी क्षेत्र के विभीषीय संस्थानों तथा पारस्परिक निधियों के पक्ष में अंतरित करने का निर्णय लिया है, जिससे जालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोष में 2,500 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। इस विनिवेश में इक्विटी का आधार विस्तृत होगा, प्रबन्ध में सुधार होगा तथा इन उद्यमों के लिए साधनों की उपलब्धता में वृद्धि होगी।

62. विदेशी सहायता से, जिनमें अनुदान को छोड़कर, 3,510 करोड़ रुपये की निवल प्राप्तियाँ होने का अनुमान है, जबकि 1990-91 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 3,984 करोड़ रुपये थी। यद्यपि विनिमय दर में हाल ही के समायोजनों के परिणामस्वरूप, ऋण की वापसी अदायगी और व्याज अदायगी संबंधी देयताओं में हुई वृद्धि को बजट अनुमानों में पूरी तरह से दर्शाया गया है, तथापि विनिमय दर में समायोजनों के कारण विदेशी सहायता के रूप में होने वाली संभावित वृद्धि का अभी अन्दाजा लगाया जा रहा है। इन प्राप्तियों में जिस सीमा तक वृद्धि होगी, उसी के अनुसार व्यय में भी वृद्धि हो जाएगी, जब कि यह सहायता उन संबंधित परियोजनाओं या स्कीमों को प्रदान की जाएगी जिनके लिए यह सहायता प्राप्त हुई है। इस प्रकार, ये परिवर्तन वजटीय घाटे को निष्प्रभावी करने वाले होंगे तथा इन्हें संशोधित अनुमान तैयार करते समय सम्मिलित कर लिया जाएगा।

63. प्राप्तियाँ और व्यय की अन्य भिन्नताओं को हिसाब में लेते हुए, कराधान की वर्तमान दरों के अनुसार कुल 1,03,698 करोड़ रुपये की प्राप्तियाँ होने का अनुमान है तथा कुल व्यय 1,13,422 करोड़ रुपये का अनुमान है। इस प्रकार, अतिरिक्त संसाधन जुटाए, बिना, वजटीय घाटा 9,724 करोड़ रुपये, राजस्व घाटा 15,859 करोड़ रुपये तथा राजकोषीय घाटा 39,732 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

भाग 'ख'

64. माननीय सदस्यों ने यह देखा होगा कि व्यय संबंधी समायोजन, जालू वित्त वर्ष के दौरान प्रस्तावित राजकोषीय समाधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। परन्तु, सरकार की आय बढ़ाने के लिए राजस्व जुटाने के उपायों के द्वारा राजकोषीय समायोजन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। यत्र मैं प्रत्यक्ष करों के संबंध में राहत, प्रोत्साहन तथा लेवी प्रत्युत करने में सदन के सहयोग की अपेक्षा करता हूँ।

65. प्रत्यक्ष करों में राजस्व की राशि में, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात और कुल कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में पिछले समय में लगातार घात दर्ज की गई। हमारी राजकोषीय पद्धति में न्यायसंगति और संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य में इस प्रवृत्ति को बदला जाना चाहिए। विकास के लिए उन लोगों में साधन जुटाए जाने चाहिए जो क्षमता रखते हैं। इस प्रयोजन के लिए हमें प्रत्यक्ष करों पर अधिक बल देना चाहिए। इसके लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो दरों में वृद्धि तथा बेहतर कर अनुपालन की आवश्यकता है। इसके साथ ही प्रणाली को युक्तिमंगत बनाना, जिसमें अधिकतम सीमा तक कर की दर कम होती है, प्रक्रियाएँ सरल बनती हैं, रियायतों की प्रचुरता कम होती है और आय के विभिन्न स्तरों पर आयकर की औसत दरें अधिक उचित स्तर पर आती हैं, आवश्यक है। बजट प्रस्तुत करने से पहले इतना समय उपलब्ध नहीं था कि इसमें कोई आधारभूत मरम्मतत्मक परिवर्तन किए जाते। फिर भी मैंने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ने के लिए सजग प्रयास किया है।

66. इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आय-कर और धनकर दोनों ही के क्षेत्र में बड़े पमाने पर कर अपवंचन होता है। यदि अगले कुछ महीनों में कर अनुपालन में कोई पर्याप्त सुधार नहीं हुआ तो सरकार के पास ऐसा अपराध करने पर कर-बंचक को पर्याप्त ऊँची कीमत अदा कराने के कड़े उपाय अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। कर-बंचकों के खिलाफ सख्त कदम उठावे से पहले मैं उन्हें काले धन को प्रकाश में लाने का एक अंतिम अवसर देना चाहूँगा। इस प्रकार जुटाए जाने वाले काले धन का उपयोग झोपड़पट्टियों का सुधार करने और ग्रामीण निधनों के लिए कम लागत वाले मकानों का निर्माण जैसे सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाएगा।

67. मेरा प्रस्ताव एक स्कीम शुरू करने का है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 30 नवम्बर, 1991 के दिन की कार्य समाप्ति से पहले राष्ट्रीय आवास बैंक के खाते में धन जमा करा सकता है। उसके पश्चात ऐसी जमा राशि में से 40 प्रतिशत को घटाकर एक विशेष लेवी के रूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रीय आवास बैंक में एक निधि की पूर्ति होगी। इस निधि का उपयोग सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग-दर्शी क्लरेखाओं और प्राथमिकताओं के अनुसार झोपड़पट्टियों का सुधार करने और निधनों के लिए कम लागत वाले मकानों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। जमाकर्ता

को शेष राशि, उसके द्वारा चुने गए किसी प्रयोजन के लिए, एकाउंट पेरी चेकों के माध्यम से एक अथवा अधिक किस्तों में निकालने की छूट होगी। इस जमा राशि के लिए अवधि का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसी राशि जमा करने वाले व्यक्तियों को निधियों के उन स्रोतों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जिससे ये राशियां जमा की गई हैं। दूसरे शब्दों में जमा की गई धनराशि के संबंध में, कोई जांच-पड़ताल अथवा अन्वेषण नहीं किया जाएगा। तथापि, प्रत्यक्ष कर कानून के उपबंध विशेष लेवी की कटौती के बाद, जमा करने की तारीख में, निवल जमा राशि पर लागू होंगे। संबंधित व्यक्ति की आय के आकलन में लेवी की रकम के संबंध में कटौती की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में आवश्यक विधान, संसद के इसी सत्र में शीघ्र ही पेश किया जाएगा। स्कीम के अंतर्गत तथा इसके लागू होने की तारीख भी शीघ्र ही घोषित की जाएगी।

68. आयकर अधिनियम में एक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत, करदाता जीवन में एक बार घोषित की गई राशि पर दण्ड और ब्याज की छूट पाने की सुविधा का लाभ उठा सकता है। जिन व्यक्तियों ने इस सुविधा का लाभ उठा लिया है, मेरा प्रस्ताव उन्हें अपनी बेहिजाबी आय बताने का एक और अवसर देने का है। इस प्रयोजन के लिए वित्त विधेयक में आयकर अधिनियम की धारा 273क में उपयुक्त संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव सम्मिलित है।

69. समझौता आयोग की स्थापना निर्धारित की उसकी अधोषित आय और धन की घोषणा करने का अवसर देने के लिए की गई थी। विद्यमान प्रक्रियाओं के अंतर्गत आयकर आयुक्त, कुछ आधारों पर, समझौता आयोग द्वारा कोई आवेदन स्वीकार करने पर आपत्ति कर सकता है। इससे अनावश्यक देरी होती है। इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है। तथापि, समझौता आयोग, आयुक्त की रिपोर्ट मांगता रहेगा और उस पर ध्यान देगा, बशर्त कि यह रिपोर्ट छः महीने की अवधि के अंदर प्रस्तुत कर दी जाए।

70. हमारे चुनाव घोषणापत्र में यह वायदा किया गया है कि हम उपयुक्त कर छूटों द्वारा लाभों के पुनर्निवेश को उन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करेंगे, जहां बड़े पैमाने पर निवेश की अत्यन्त आवश्यकता है, जैसे कि कम और मध्यम आय वर्ग के सामूहिक आवास, राजमार्ग, सड़कें और पुल, गैर-परम्परागत ऊर्जा, स्कूली इमारतें और पेयजल आपूर्ति। इसलिए, कोई व्यापार अथवा व्यवसाय चलाने वाले किसी भी करदाता के कर-योग्य लाभ का आकलन करने में, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने वाली स्कीमों अथवा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अदा की गई पूरी राशि की कटौती की व्यवस्था करने के लिए मेरा प्रस्ताव आयकर अधिनियम में एक प्रावधान करने का है। दुर्लभ संसाधनों के दृष्टान्त उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मेरा प्रस्ताव प्रमुख व्यक्तियों की एक राष्ट्रीय समिति गठित करने का है जो ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएगी, जिनके लिए सहायता की आवश्यकता है, तथा यह समिति विशिष्ट

परियोजनाओं और स्कीमों की सिफारिश करेगी। कोई भी व्यापार अथवा व्यवसाय न करने वाले करदाताओं के मामले में भी इसी प्रकार की कटौती की अनुमति होगी।

71. शिक्षा और अनुसंधान के लिए मेरी वचनबद्धता को देखते हुए तथा हमारी विकास प्रक्रिया में इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसे ध्यान में रखते हुए मेरा प्रस्ताव कुछ कर रियायतें देने का है, जिनसे सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के वित्तपोषण में मदद मिलेगी तथा जिनसे लेखकों और प्रकाशकों को कुछ प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

72. इस समय कोई व्यापार या व्यवसाय करने वाले करदाताओं को ही उनके द्वारा किए जाने वाले व्यापार की श्रेणी से संबंधित सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए किसी अनुमोदित विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्थाओं को अदा की गई राशि के संबंध में कटौती की छूट प्राप्त है। मेरा विचार है कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में शोध कार्य करने के लिए और अधिक कर प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा प्रस्ताव इन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिये, चाहे उस व्यापार से संबंधित हो अथवा नहीं, अदा की गई राशि के संबंध में इसी प्रकार की शत प्रतिशत कटौती की छूट देने का है। मेरा प्रस्ताव, कोई व्यापार अथवा व्यवसाय न करने वाले करदाताओं को भी इस कटौती की छूट देने का है।

73. हमारे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में, पुस्तकों की भूमिका के महत्व को दोहराना आवश्यक नहीं है। अच्छी और कम कीमत की पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने तथा प्रकाशन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव वर्तमान लेखावधि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए पुस्तकों के प्रकाशन से होने वाले लाभों में से 20 प्रतिशत को कटौती की छूट फिर से शुरू करने का है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में अच्छी पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने के लिए मेरा प्रस्ताव भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के लेखकों की व्यावसायिक आय में से भी 25 प्रतिशत को कटौती फिर से शुरू करने का है। यह भी चालू आय वर्जन अधि से शुरू होकर पांच वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

74. विदेशी संस्थात्मक निवेश आकर्षित करने के लिए आफशोर कंट्री फंड विशेषतः अनिवासी भारतीयों से, महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर रहा है। भारत ने इस दिशा में 1989 में शुर्भारत की थी। तथापि, हाल में आफशोर कंट्री फंड में विदेशी संस्थात्मक निवेशकों की रुचि में कमी के लक्षण देखने में आए हैं। तुलनात्मक राष्ट्रीय कर प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह की दिशा को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। इसलिए मेरा प्रस्ताव यू. टी. आई. के यूनियटों अथवा अन्य पारस्परिक निधियों से आफशोर निधियों द्वारा प्राप्त लाभों पर आय वैसे यूनियटों से दीर्घवधिक पूंजीगत लाभों पर कर की दर को पर्याप्त रूप से कम करने का है। लाभों पर कर की दर को प्रस्तावित दर 10 प्रतिशत होगी,

जबकि इस समय यह दर 25 प्रतिशत है। दीर्घावधिक पूंजीगत लाभों के संबंध में मेरा प्रस्ताव 10 प्रतिशत की इसी दर का है, जबकि इस समय लगभग 45 प्रतिशत की दर प्रभावी है।

75. दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत बहुसंख्यकों के संघर्ष में हमारी गहरी भावात्मक रुचि को ध्यान में रखते हुए तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति हमारी वचनबद्धता की पुष्टि के रूप में मेरा प्रस्ताव है कि अफ्रीका निधि के लिए दान, आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अन्तर्गत 100 प्रतिशत कटौती के पात्र होंगे।

76. सरकार अपने अभागे विकलांग नागरिकों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। उनकी कठिनाई को कुछ सीमा तक कम करने के प्रयास के रूप में मेरा प्रस्ताव, पूर्णतः नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अन्तर्गत उपलब्ध कटौती की राशि 15,000 रुपये के बहाकर 20,000 रुपये करने का है। इस कर रियायत का लाभ आंशिक रूप से नेत्रहीन व्यक्तियों को भी देने का प्रस्ताव है।

77. आवास संबंधी कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना सरकार की सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में मेरा प्रस्ताव आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूट का लाभ, राष्ट्रीय आवास बैंक की गृह ऋण खाता स्कीम जैसी ही हुडको और राज्य आवास बोर्ड जैसे सार्वजनिक आवास निगमों द्वारा शुरु की गई संविदात्मक स्कीमों पर भी लागू करने का है। इसके अतिरिक्त, धारा 88 के अन्तर्गत कर संबंधी छूट, भूमि की लागत के लिये गए ऋणों की किस्तों वापसी अदायगी तथा उन स्थितियों, जिनमें भूकान पहली अप्रैल, 1987 से पहले खरीदा अथवा निर्मित कराया गया था, में भी उपलब्ध होगी।

78. हमारे साफ्टवेयर उद्योग ने हाल ही के वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। तथापि, वृद्धि के लिए अभी भी बहुत बड़ी अप्रयुक्त क्षमता बिद्यमान है। यही समय है जब हम समुद्रपारीय साफ्टवेयर बाजार पर अधिकार करने का प्रयास कर सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ मैं साफ्टवेयर के निर्यात के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 जजग के अधीन कर संबंधी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। इस छूट से इस उद्योग को निर्यात में तेजी से वृद्धि दर्ज करनी चाहिए।

79. मैं, संसाधन खनिजों के निर्यात के लिए भी धारा 80जजग के अन्तर्गत छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

80. मेरा विचार है कि वास्तुकला, लेखा पद्धति आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हमारे व्यावसायिकों के पास जो वैज्ञानिक तकनीकी और व्यवसायिक कार्यकुशलता, ज्ञान तथा अनुभव है, उसमें देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने की अत्यधिक क्षमता है। उनमें से अनेक अपने व्यवसाय को व्यक्तिगत तौर पर अथवा भागीदारी वाली फर्मों के रूप में चलाते हैं। उन्हें

धारा 80ण के अन्तर्गत उपलब्ध कर छूट से लाभ प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए मैं कर रियायत को, जिसमें अभी केवल निगमित क्षेत्र को लाभ प्राप्त होता है, निगमित भिन्न निर्धारितियों को भी देने का प्रस्ताव करता हूं।

81. ऐसे क्षेत्रों में जहां आजकल ऐसी सुविधाएं लगभग उपलब्ध नहीं हैं, पर्यटन के आधारभूत ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं पर्वतीय तथा अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थापित नए स्वीकृत होटलों में किए गए व्यय को दस वर्ष की अवधि के लिए व्यय कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं ऐसे होटलों को धारा 80स के अन्तर्गत उनके लाभों के सामान्य 30 प्रतिशत कटौती के स्थान पर 50 प्रतिशत कटौती देने का भी प्रस्ताव करता हूं बशर्ते कि वे कुछ शर्तें पूरी करें।

82. हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में स्वस्थ पूंजी बाजार की भूमिका की मरहना के संकेत के रूप में, मैं दीर्घावधिक पूंजी प्राप्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अभी उपलब्ध 10,000 रुपये की मूल कटौती को 15,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

83. जैसा कि, पहले बताया गया है, मैं कुल राजस्व प्राप्तियों में प्रत्यक्ष कर राजस्व के अनुपात में ह्रास की प्रवृत्ति को बदलने के लिए कुछ ठोस कदम उठाना चाहता हूं। इसलिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भरता के माध्यम से इस वर्ष अतिरिक्त संसाधन जुटाने का मेरा प्रस्ताव है। मैं अब बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा राजस्व जुटाने के लिए अनिर्गुण कर लगाने के अपने प्रस्तावों की ओर आता हूं।

84. ऐसे आय अर्जकों का पता लगाने के लिए, जिनमें से अधिकांश अन्यथा अपनी आय घोषित नहीं करेंगे अथवा अपनी पूरी आय घोषित नहीं करेंगे, सरकार की सक्षम बनाने के वास्ते मेरा प्रस्ताव, कमीशन, बैंकों द्वारा सावधि जमाओं पर अदा किए गए ब्याज और राष्ट्रीय बचन योजना से आहरणों जैसे भुगतान के नए क्षेत्रों को स्रोत पर कर की कटौती की योजना में शामिल करने का है। छोटे जमाकर्ताओं के लिए अनुविधा को न्यूनतम करने के लिए केवल प्रतिवर्ष 2,500 रुपये से अधिक के ही भुगतान के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो सीमा से अधिक भुगतान प्राप्त करेंगे, परन्तु जिसकी आय कर योग्य नहीं है, उन्हें निर्धारित तरीके से घोषणापत्र प्रस्तुत करके कर की कटौती के बिना भुगतान प्राप्त करने की सुविधा होगी।

85. आय में से अल्पावधिक पूंजी हानियों को प्रतिसंतुलित करने की वर्तमान व्यवस्था से कर वंचित होना है। इसलिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पूंजीगत परिसंपत्ति के अन्तरण से होने वाली हानि का केवल अन्य पूंजीगत परिसंपत्ति के अन्तरण से होने वाली प्राप्ति में से ही समजंन किया जाना चाहिए। यह ही तार्किक

है। कुछ वंशमान करदाताओं द्वारा खरीदी जाने वाली अल्प-वर्षिक पूंजीगत हानियों की प्रथा भी इसमें समाप्त हो जानी चाहिए।

86. कई वर्षों से, जुआ खेले को प्रवृत्ति रखने वाले लोगों ने दीड़ों की अधिकाधिक संरक्षण प्रदान किया है। मैं बुद्धाष्ट सहित दीड़ों से होने वाला आय के संबंध में 5,000 रुपए की आयकर छूट का वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति जो शर्त लगाते हैं, अब दीड़ों से होने वाली अपनी आय को सरकार के साथ बांटने में आनन्द का अनुभव करेंगे।

87. प्रोफेसर कल्डोर ने एक बार कहा था कि किसी भी मनुष्य समाज में 45 प्रतिशत से अधिक आयकर की अधिकतम सीमात्मक दर नहीं होनी चाहिए। हम एक ऐसी कर प्रणाली के प्रति दृढ़ प्रतिबद्ध हैं जो सरल, विश्वसनीय और साथ ही पारदर्शितापूर्ण हो, जिसमें लोग यह महसूस करें कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। वर्तमान राजकोषीय कठिनाइयों पर जैसे ही हम आगे पायेंगे, वैसे ही हम इस दिशा में शुद्ध-आप करने की उम्मीद करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह प्रक्रिया हमारी सरकार की पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले पूरी कर ली जाएगी। यदि सभी करदाता अपना आयकर पूर्णतः और तुरन्त अदा करने का निश्चय कर लें तो वे स्वयं कर सुधार कर की प्रक्रिया को तेज करने में मदद दे सकते हैं। परन्तु राजकोषीय संकट के बीच में ऐसा परिवर्तन संभव नहीं है। हमें अच्छे समय का इंतजार करना होगा। इन परिस्थितियों में, मैं जो कुछ कर सकता हूँ, वह यही है जो मैं इस वर्ष के लिए प्रस्ताव कर रहा हूँ : अधिभार सहित वैयक्तिक आयकर दर के ढांचे को अपरि-वर्तित रखना। मैंने करदाता पर और बोझ नहीं डाला है, यही अपने आप में एक राहत है।

88. मुझे धनकर की दरों को युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता हेतु बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मुझे इन अभ्यावेदनों में काफी बल दिखता है। तथापि राजस्व की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही समयाभाव के कारण मैं धनकर की दरों में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूँ।

89. धनकर लगाने के प्रयोजन के लिए, परिसम्पत्तियों का नियमानुसार मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को उनके बाजार मूल्य अथवा उसके लगभग मूल्य पर निर्धारण किया जाता है। मेरे विचार से इन नियमों में कुछ विमर्गति पैदा हो गई है। यदि किसी व्यक्ति के पास उसके नाम से कोई परिसम्पत्ति है तो उसका मूल्यांकन बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। लेकिन, यदि व्यक्तियों के किसी समूह के पास कोई परिसम्पत्ति किसी निवेश कंपनी के माध्यम से है तो इन परिसम्पत्तियों का करयोग्य मूल्य काफी कम हो जाता है, क्योंकि यह बाजार मूल्य पर नहीं बल्कि खाता मूल्य पर आधारित होता है। इसलिए, मैं इस विमर्गति को हटाने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसके लिए यह

व्यवस्था होगी कि निवेश कंपनियों के समूहों के मूल्य का मूल्यांकन करने समय, परिसम्पत्तियों का विघटन मूल्य उनके बाजार मूल्य के अनुसार किए गए पुनर्मूल्यांकन पर आधारित होगा।

90. मैं इस बात से निराश हूँ कि हाल के वर्षों में निगमित क्षेत्र के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि मूल्यवर्धित और लाभ उचित रूप से निगम पर प्राप्तियों में परिलक्षित नहीं हुए है। विशेषकर पिछले वित्तीय वर्षों का अनुभव गंभीर चिन्ता की बात है। इसलिए, मैं बहु-जनधारित कंपनियों के लिए निगम कर की दर 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर रहा हूँ। अल्प-जनधारित कंपनियों के लिए भी निगम कर की दर में 5 प्रतिशत की समानुक्त वृद्धि करके 45 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की जा रही है। मैं 15 प्रतिशत के अधिभार को भी जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

91. व्यापारिक कंपनियों और औद्योगिक कंपनियों के बीच निगम कर की दरों में पारस्परिक भिन्नता का उपयोगिता की दृष्टि से काफी पुरानी हो गई है। इसलिए, मेरा प्रस्ताव इस भिन्नता को समाप्त करने का है।

92. मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि सध्यावधि में निगम कर की दरें और प्रणाली, अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य अन्तर्गोष्ठीय रूप से प्रतियोगी बनना है। मैं वर्तमान राजकोषीय संकट पर काबू पाने के बाद शीघ्र ही इस कार्य पर ध्यान दूंगा।

93. हमारी अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जबकि पूंजी दुर्लभ है। इन आर्थिक वास्तविकताओं को हमारे राजकोषीय नीति में परिलक्षित होना चाहिए। फिर भी, पिछले कई वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन में अधिक पूंजी सघनता के प्रति चिन्ताजनक बदलाव देखा गया है। इससे उन मामलों में भी विकृति और परिहार्य कठिनाई उत्पन्न हो गई है, जिनमें श्रमिकों को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है अथवा उत्पादन के पूंजी घनत्व वाले उपायों को अपना कर रोजगार की संभावनाओं को कम कर दिया जाता है। यहां तक कि उन मामलों में भी जहां अन्य आर्थिक और तकनीकी विचारों के अनुसार ऐसा बदलाव व्यापारिक नहीं है, राजकोषीय प्रोत्साहनों से ऐसे बदलाव को मजबूत मिली है। यद्यपि, औद्योगिकीय उन्नयन और सतत आधुनिकीकरण की अनिवार्यताओं को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे उद्योग क्षेत्र में अत्यधिक पूंजी सघनता को रोका जाना चाहिए।

94. संयंत्र और मशीनरी के बारे में, 1987 में निर्धारित की गई मूल्य ह्रास की दरें काफी उदार हैं तथा इनके अन्तर्गत टूट-फूट के लिए आवश्यक क्षतिपूर्ति में कहीं अधिक क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। मूल्यह्रास की इन दरों से व्यापारिक परिसम्पत्तियों की वास्तविक आर्थिक अवधि का पता नहीं चलता है। अधिकांश संयंत्र और मशीनरी के मामलों

में लागू 33.33 प्रतिशत की वर्तमान दर के अनुसार कोई भी परिमर्पति छः वर्षों में पूरी तरह से अवनिष्ठित होगी। मेरे विचार में, भारत में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन की गति, व्यापारिक परिसम्पत्तियों की वास्तविक आर्थिक अवधि तथा कर प्रेरित परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन को हतोत्साहित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आठ वर्ष की अवधि अधिक युक्तिसंगत होगी। इसलिए, मैं मशीनरी और संयंत्रों के लिए मूल्यहास की सामान्य दर 33.33 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं हवाई जहाजों, मोटर बसों, मोटर टैक्सियों तथा कुछ अन्य उपकरणों के मूल्यहास की दर को 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी करता हूँ, जिससे लागत की पूरी वापसी पांच वर्षों की बजाय छः वर्षों में होगी। लेकिन, ऊर्जा बचाने वाले यंत्रों तथा पुनर्जीवीय-ऊर्जा यंत्र के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव है कि ऐसे कुछ अन्य संयंत्रों और मशीनरी तथा उनकी भवों के मामले में 100 प्रतिशत मूल्यहास की दर को जारी रखा जाए। इसके अतिरिक्त, जिस परिसम्पत्ति का प्रयोग वर्ष में 6 महीने से कम अवधि के लिए किया जाता है, उन मामलों में मैं मूल्यहास की दर को सामान्य दरों के 50 प्रतिशत तक सीमित रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

95. विशेष संस्थाओं को उनकी प्रारंभिक अवस्था में कर-सहायता देना आवश्यक है। लेकिन इसे निरन्तर जारी नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसी संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं से अलग, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इसकी स्थापना के पश्चात् से ही अपनी आय पर संपूर्ण कर छूट मिली हुई है। मैं इस छूट को वापिस लेने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसकी अब कोई जरूरत नहीं है।

96. 1987 में, सरकार ने आडम्बरपूर्ण व्यय पर कर लागू किया था। यह कर उन हॉटलों, जिनमें कमरे का किराया 400 रुपये प्रतिदिन से अधिक है, में किए गए व्यय के 20 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है। मेरा इस कर को उन रेस्तरांओं में किये जाने वाले व्यय पर भी लगाने का प्रस्ताव है, जिनमें वानानुकूलन जैसी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह कर ऐसे व्यय पर 15 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

97. बाध्यकारी राजकोषीय दवावों तथा संसाधन जुटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मैं ब्याज-कर को फिर से लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसे सर्वप्रथम 1974 में शुरू किया गया था और 1978 में उठा लिया गया था तथा जिसे 1980 में संशोधित रूप में फिर से शुरू किया गया था और अंततः 1985 में उठा लिया गया था। मैं इस कर के क्षेत्र को थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ। यह नया कर सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा निगमित क्षेत्र की गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारत में दिये गये 1865GI/91—3

ऋणों और अग्रिमों पर मिलने वाली ब्याज की सकल राशि पर लगाया जाएगा। ये संस्थाएं उधारकर्ताओं से ली जाने वाली ब्याज दरों में आवश्यक समायोजन करके अपनी प्रतिपूर्ति कर लेगी। इस प्रस्तावित कर से उधार की लागत में वृद्धि होने तथा सरकार को राजस्व प्राप्त होने की आशा है। इसलिए, इसका मीट्रिक तथा राजकोषीय दोनों प्रकार का प्रभाव होगा।

98. यह प्रस्तावित कर, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा वित्तीय कंपनियों द्वारा भारत में दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर अर्जित सकल ब्याज की राशि पर 3 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। विभिन्न ऋण संस्थाओं के बीच हुए लेनदेनों पर प्राप्त ब्याज को इस प्रस्तावित कर से मुक्त रखा जाएगा। प्रस्तावित कर भविष्य में लागू होगा तथा 1 अक्टूबर, 1991 से पहले अर्जित होने वाले ब्याज पर कर नहीं लगाया जाएगा। आय कर अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य आय का परिकलन करते समय यह कर कतौती के रूप में अनुमत्य होगा।

99. प्रत्यक्ष कर कानूनों में किए गए अन्य छोटे-छोटे परिवर्तनों के संबंध में, मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता।

100. प्रत्यक्ष करों पर मेरे प्रस्तावों से 2,139 करोड़ रुपये के निवल राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है, जिसमें से 97 करोड़ रुपये राज्यों को प्राप्त होंगे।

101. सदन के माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि भुगतान संतुलन की स्थिति अत्यंत कठिन है। विदेशी मुद्रा को बड़ी मात्रा में आकर्षित करने के उद्देश्य से मैं दो स्कीमों शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

102. पहली स्कीम के अंतर्गत मेरा प्रस्ताव यह है कि विदेशी मुद्रा में प्रेषणाएं भारत में किसी भी व्यक्ति को की जा सकती हैं। चाहे भारत में दान प्राप्तकर्ता द्वारा ऐसी प्रेषण उपहार के रूप में प्राप्त हुई हों, फिर भी उस पर उपहार कर नहीं लगेगा। प्रत्यक्ष कर कानून और विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रेषणाओं की निधियों के स्रोतों की जांच-पड़ताल नहीं की जाएगी। दूसरे शब्दों में मेरा प्रस्ताव इन कानूनों के अंतर्गत ऐसी प्रेषणाओं को मुक्त करने का है। इन प्रेषणाओं की दफ्तरी प्राप्तियों पर प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधान सामान्य तरीके से लागू होंगे। यह स्कीम तत्काल लागू हो जाएगी और 30 नवम्बर, 1991 को कार्य समाप्ति तक खुली रहेगी। इस स्कीम के ब्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किए जाएंगे। मेरा प्रस्ताव इस संबंध में सदन के समक्ष यथाशीघ्र आवश्यक विधान पेश करने का भी है।

103. दूसरी स्कीम के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक भारत विकास बाण्ड जारी करेगा, जिनका मूल्य अमरीकी डालर में होगा। ये बाण्ड अनिवासी भारतीयों द्वारा और उनकी समुद्रपारीय निगमित निकायों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध होंगे। इन बाण्डों में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी, जिनकी परिपक्वता अवधि पांच वर्ष होगी। ये बाण्ड अनिवासी भारतीयों के बीच पूर्णतः हस्तान्तरणीय होंगे।

बाण्डों से ब्याज पर आयकर से छूट होगी। परिपक्वता की अवधि तक बाण्ड धनकर से भी मुक्त होंगे। अनिवार्य धारक के लिए बाण्ड का अंकित मूल्य और उस पर ब्याज को विनिमय दर संरक्षण के साथ प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा। इन बाण्डों को निवासियों को उपहार रूप में भी दिया जा सकता है, जिन्हें देश में प्रेषणाओं के लिए पहली स्कीम की तरह उन्मुक्ति और क्षमा प्रदान की जाएगी। ऐसी क्षमा और उन्मुक्ति केवल प्रथम निवासी दान प्राप्तकर्ता को ही उपलब्ध होगी। इस उपहार पर उपहार-कर से छूट होगी। निवासी दान प्राप्तकर्ता बाण्ड धारक को भी विनिमय दर संरक्षण और आयकर तथा धनकर से परिपक्वता तक उम्मी छूट का अधिकार होगा, किन्तु राशि केवल भारत में रुपयों में प्रदा की जाएगी और उसे विदेश नहीं भेजा जा सकेगा। ये बाण्ड देश में भारतीय स्टेट बैंक की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में 30 नवम्बर, 1991 को कार्य समाप्ति तक बिस्की के लिए उपलब्ध होंगे। स्कीम के न्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किए जाएंगे। मैं सदन के सम्मुख आवश्यक विधान शीघ्र ही प्रस्तुत करूँगा।

104. अप्रत्यक्ष करों के संबंध में अपने प्रस्ताव तैयार करते समय मैंने विस्तृत संदर्भ को ध्यान में रखा है। हमारी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायवों के अनुसार, हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि आम लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली जरूरी वस्तुओं और सामान की कीमतें नियंत्रण में रखी जाए। आइसक्रीमपूर्ण उपयोग रोक जाना चाहिए और करों का बोझ समाज के अधिक समृद्ध वर्गों द्वारा उठाया जाना चाहिए। इन अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए, मैंने सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क संबंधी प्रस्ताव की इस प्रकार से संरचना करने का प्रयास किया है कि देशज उद्योगों को बढ़ावा मिले तथा साथ ही निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक मदों के आयात में कोई बाधा न हो। दीर्घावधि में, यदि राजस्व में वृद्धि होती है और कर अनुपालन में सुधार होता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की दरें कम हो जाएंगी। अब भी, आयात शुल्क में कुछ आशोधन का प्रयास किया जा रहा है तथा अगले बजट में प्रणाली को सुचारु बनाने तथा दरों को कम करने के लिए और अधिक व्यापक आधारित प्रयास किए जाएंगे। मैंने यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया है कि प्रस्तावित परिवर्तनों से औद्योगिक क्षेत्र को, विशेष रूप से निर्यात प्रधान उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो।

105. मेरा हरादा, अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों को युक्तिसंगत व सरल बनाने का है, ताकि प्रणाली में होने वाली देरियां दूर हो सकें तथा साथ ही कर समाहर्ता व करदाता के बीच अन्योन्यक्रिया को कम से कम किया जा सके। समवाभाव को देखते हुए इस बजट में ऐसा करना संभव नहीं हो सका है, परन्तु शीघ्र ही हम कर प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों के एक भाग के रूप में ठोस उपाय तैयार कर सकेंगे।

106. हाल ही के वर्षों में, अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए अप्रत्यक्ष करों पर अप्रत्यक्ष निर्भरता देखने में आई है। इससे लागतों में वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है और इसका प्रभाव प्रतिगामी होता है। इसलिए मैं साधन जुटाने के प्रमुख स्रोत के रूप में अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर नहीं रहा हूँ। वस्तुतः सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संबंधी मेरे प्रस्तावों का समग्र प्रभाव, जहाँ तक केन्द्र सरकार का संबंध है, राजस्व वकारात्मक है।

107. सीमाशुल्क के क्षेत्र में, पिछले समय में, नवोदित उद्योगों के संरक्षण और राजस्व जुटाने की आवश्यकता के उद्देश्य से ऐसी स्थिति हो गई है कि कतिपय मदों के लिए निर्धारित आयात शुल्क की दरें असाधारण रूप से अधिक हैं और अनेक मामलों में ये 300 प्रतिशत से भी अधिक हैं। सुधार के उपाय के रूप में, मेरा प्रस्ताव टैरिफ शिखरों को समाप्त करना तथा जहाँ अभी सीमा-शुल्क की अनियमादी व सहायक दरों का योग 150 प्रतिशत से अधिक है, उसे कम कर के 150 प्रतिशत के स्तर पर लाने का प्रस्ताव है, जिससे 150 प्रतिशत से अधिक की टैरिफ सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद केवल आयातित अलकोहल वाले पेय पदार्थ तथा यात्री सामान इसका अपवाद होंगे। पूरे वर्ष में इस सब से 132 करोड़ रुपए की हानि होगी।

108. पिछले वर्ष राजकोषीय स्थिति में गिरावट को देखते हुए, सीमा शुल्क की सहायक शराब दरों को 15 दिसम्बर 1990 से सभी मदों पर बढ़ा दिया गया था, ताकि अतिरिक्त साधन जुटाए जा सकें। यह वृद्धि युक्तिसंगत नहीं थी और भार की दृष्टि से असमरूप थी। कुछ मामलों में सहायक शुल्क दर 20 प्रतिशतता बिन्दु बढ़कर 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई, जबकि कुछ अन्य मामलों में मात्र 5 प्रतिशतता बिन्दु बढ़ा अर्थात् 45 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो गई। इस अत्यंत व असमान वृद्धि ने कुछ मदों पर शुल्कों का भार अत्यधिक बढ़ गया और इससे समग्र कर ढांचे में विकृतियां भी पैदा हो गई। जो विकृतियां उत्पन्न हो गई थीं, उन्हें दूर करने तथा शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए मेरा प्रस्ताव लगभग उन सभी मदों पर 10 प्रतिशत बिन्दु की शुल्क राहत प्रदान करने का है, जिनपर 20 प्रतिशत बिन्दु की वृद्धि कर दी गई थी। तथापि, कुछ मदों पर, जो पर्यावरणात्मक संरक्षण, निर्यात प्रोत्साहन, विदेशी मूद्रा बनाने आदि की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, मेरा प्रस्ताव 15 दिसम्बर 1990 से पहले लागू दरों के स्तर को वापस लाने का है। इन मदों में, अवशिष्ट कागज, कच्चा काष्ठ, अगन्तवित्तियों के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाला जिगट, एथीलीन, ईथन इंजेक्शन उपकरण के लिए मशीनरी तथा मुद्रण व समाचार पत्र उद्योग के लिए मशीनरी को कुछ मदें शामिल हैं। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप पूरे वर्ष में 472 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

109. सामान्य परियोजनाओं तथा मशीनरी के लिए पूंजीगत सामान पर आयात शुल्क की प्रचलित दरें सामान्यतः अधिक हैं। यद्यपि इस समय राजस्व निहितार्थी की वजह से, जो इस समय बहुत अधिक हैं, में पर्याप्त कटौती नहीं कर सकता, मेरा प्रस्ताव शुल्क दरों को 85 प्रतिशत से कम करके 80 प्रतिशत करने का है। इसके साथ ही उनके कल-पुर्जों पर शुल्क की दरों को भी 65 अथवा 70 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से 5 प्रतिशत कम किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप पूरे वर्ष में 167 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी।

110. स्वर्णीय श्री राजीव गांधी ने सन् 1987 में एक प्रौद्योगिकीय उन्नयन स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के अंतर्गत ऊर्जा उत्पादन उपकरणों के विनिर्माण, पेपर मशीनरी, वस्त्र मशीनरी तथा ऐसी मशीनों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत उपकरणों के आयात पर राजकोषीय राहत प्रदान की गई थी। भारत में विनिर्मित मशीनों की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में यह स्कीम बहुत उपयोगी रही है। इस स्कीम को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मेरा प्रस्ताव रियायती शुल्क वाली मशीनरी मर्चों की सूची का विस्तार करने का है, जिन पर 50 प्रतिशत की दर से रियायती शुल्क लगेगा। इसके फलस्वरूप पूरे वर्ष में 5 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी।

111. हमने अपने निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में अनेक नए कदम उठाए हैं। अब मैं उन कुछ राजकोषीय उपायों का जिक्र करूंगा, जिनसे निर्यात प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा।

112. इस समय मुक्त व्यापार क्षेत्र में लगी इकाइयों अथवा 100 प्रतिशत निर्यात प्रधान उपक्रमों को अपने उत्पादन का कुछ अनुपात घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति है। तथापि, विद्यमान यह शर्त कि देय उत्पाद शुल्क, आयात शुल्क के बराबर होना चाहिए, बाधक सिद्ध हुई है। इन इकाइयों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए; इस प्रयोजन के लिए उन्हें घरेलू बाजार में एक आधार का निर्माण करने से नहीं रोका जाना चाहिए। तदनुसार, मेरा प्रस्ताव उस सामान पर जिसे इस स्कीम के अंतर्गत घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति है, उत्पाद शुल्क एक ऐसे स्तर तक कम करने का है, जो ऐसी वस्तुओं पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के आधे के बराबर हो बशर्ते कि, अन्य बातों के साथ-साथ, शुल्क, देशज टेरिफ क्षेत्र में निर्मित की जाने वाली ऐसी ही मर्चों पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क से कम नहीं होगा।

113. समुद्रीय उत्पाद उद्योग के विकास के लिए, इस उद्योग द्वारा अपेक्षित विनिर्दिष्ट मशीनों पर शुल्क रियायत के रूप में राजकोषीय राहत प्रदान की गई है। मेरा प्रस्ताव इस शुल्क राहत को ऐसी मशीनरी की कुछ और मर्चों पर भी लागू करने का है। हमारे मछुआरों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, मेरा प्रस्ताव, मछलियों का जाल बनाने के लिए

सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले विनिर्दिष्ट धागों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट देने का है।

114. संसाधित चमड़े के उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने तथा निर्यात प्रोत्साहन के एक उपाय के रूप में मेरा प्रस्ताव पोलिग्रेफीन फिल्म तथा फोइल तथा साथ ही पोलि-ओल्स पर सीमाशुल्क की बुनियादी और सहायक शुल्क को 150 प्रतिशत से 40 प्रतिशत करने का है। आईसोसायनेट्स पर शुल्क को 120 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया जा रहा है। दो महत्वपूर्ण चर्म परिरक्षकों, यथा टी.सी.एम.टी.बी. और पी.सी.एम.सी. पर आयात शुल्क, जो अभी 150 प्रतिशत से अधिक है, कम करके 50 प्रतिशत किया जा रहा है। ये परिरक्षक कुछ अन्य रसायनों का स्थान लेंगे, जिनके बारे में सन्देह है कि उनका कर्करोगजनन प्रभाव होता है। मेरा प्रस्ताव, इस समय चर्म उद्योग द्वारा विनिर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर उपलब्ध रियायती शुल्क ऐसी मशीनरी की कुछ और मर्चों पर भी लागू करने का है।

115. सिंथेटिक क्यूबिक जिरकोनियम, जो प्राकृतिक हीरों के काफी हद तक समान होता है, बड़ी संख्या में शिल्पकारों को रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता रखता है। इससे बनाए गए जेवरों में बड़ी मात्रा में निर्यात किए जा सकते थे। क्यूबिक जिरकोनियम के देशज विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, मेरा प्रस्ताव कच्ची सामग्री अर्थात्, जिरकोनियम आक्साइड तथा इट्रियम आक्साइड पर आयात शुल्क को 150 प्रतिशत से अधिक के वर्तमान स्तर से कम करके 40 प्रतिशत करने का है।

116. हमारी सरकार, कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में एक वायदा यह किया गया था कि किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में विविधता लाने तथा ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खाद्य संसाधन तथा अन्य कृषि-आधारित उद्योगों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, मेरा प्रस्ताव कृषि-आधारित उत्पादों, जैसे कि चटनी, अचार, मक्खन, पनीर, मखनिया दूध, वनस्पति तेल, जाम, जैली और जूस, बिस्का-बन्द फल तथा सुखाई गई सब्जियां, कतिपय सोया उत्पाद, स्टार्च और मांस व मछलियों के उत्पादों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने का है। मैं ऐसा अपनी कृषि अर्थव्यवस्था के विविधीकरण को प्रोत्साहित करने, संसाधित कृषि उत्पादों पर खर्च हुई उपभोक्ता की आय में किसानों का हिस्सा बढ़ाने, कृषि उत्पाद पर आधारित ग्रामीण औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने तथा आधुनिक कटाई-पशुचार् प्रौद्योगिकीयों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि जिन उपायों का मैंने प्रस्ताव किया है, उनसे ऐसे उत्पादों की उपभोक्ता कीमतों में कुछ कमी आएगी जिससे बढ़ती हुई कीमतों के युग में दृष्टी उपभोक्ता को राहत मिलेगी। लगभग 84 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी,

किन्तु मुझे विश्वास है कि अर्थव्यवस्था में समग्र लाभ से राज-कोष को होने वाली यह हानि प्रतिसंतुलित हो जाएगी।

117. कृषि-आधारित जूट उद्योग को राहत के रूप में, जो घिरकाशीन समस्याओं से ग्रस्त है, मेरा प्रस्ताव उन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को 660 रुपये प्रति मी. टन से कम करके 330 रुपये प्रति मी. टन करने का है, जिनमें कम से कम 35 प्रतिशत जूट रेशा हो।

118. इस समय अनेक विनिर्दिष्ट थोक कीटनाशक तथा कीटनाशक मध्यवर्ती मर्चों पर रियायती आयात और निर्यात शुल्क लगता है। मेरा प्रस्ताव कुछ और थोक कीटनाशकों तथा कीटनाशक मध्यवर्ती मर्चों पर रियायती शुल्क लागू करने का है। इन प्रस्तावों के फलस्वरूप पूरे वर्ष में लगभग 11 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी।

119. साबुन बनाने के लिए गौण तेलों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की एक धन क्रेडिट स्कीम प्रचलन में है। मेरा प्रस्ताव, साबुन बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले चावल की भूसी के तेल के संबंध में इस समय उपलब्ध 640 रुपये प्रति मी. टन के धन क्रेडिट को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति मी. टन करने का है। इसके अतिरिक्त मेरा प्रस्ताव इस स्कीम के अंतर्गत कुछ और गैर-परम्परागत तेलों व विलायक निस्सारित तेलों को शामिल करने का है। इससे वन क्षेत्रों में हमारी जनजातीय स्त्रियों के लिए कुछ और रोजगार के अवसर प्राप्त होने में मदद मिलेगी। इन प्रस्तावों के फलस्वरूप पूरे वर्ष में लगभग 10 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी।

120. अप्रत्यक्ष करों के प्रपाती प्रभाव को कम करने के लिए सन् 1986 में मोडवाट स्कैम शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्योग द्वारा काफी स्वागत किया गया था और इसे अन्य क्षेत्रों में बढ़ाने की काफी मांग रही है। मेरा प्रस्ताव बातिज जल के संबंध में इस स्कीम को फिर से लागू करने का है तथा इसका विस्तार करने का भी प्रस्ताव है, ताकि इसके अन्तर्गत मानव निर्मित रेशों व फिलामेंट यार्न को भी उनको निविष्टियों के संबंध में शामिल किया जा सके इस स्कीम को रेशों और यार्न पर लागू करते समय मेरा प्रस्ताव उन रेशों तथा यार्न पर शुल्क बढ़ाने का नहीं है, जिनपर हाल ही में विसम्बर 1990 में शुल्क बढ़ाया गया था। अन्य रेशों तथा यार्न पर शुल्क दरों को समायोजित किया गया है ताकि उत्पाद शुल्कों से संप्रहों को पिछले स्तर पर बनाए रखा जा सके। लेकिन पोलीप्रोपलीन, मोनोफिलामेंट तथा मल्टीफिलामेंट यार्न पर शुल्क की दरें बढ़ाई जा रही हैं ताकि अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सके। बातिज जल के संबंध में भी मेरा प्रस्ताव कोई शुल्क बढ़ाने का नहीं है। इन प्रस्तावों

के फलस्वरूप पूरे वर्ष में लगभग 230 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी। मुझे उम्मीद है कि इस लाभ को कीमतों कम करके उपभोक्ता तक पहुंचा दिया जाएगा।

121. मेरा प्रस्ताव पोलिएस्टर मिश्रित यार्न पर विद्यमान उत्पाद शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाने का है। अपवर्धन-रोधी उपाय के रूप में मेरा प्रस्ताव, 40 प्रतिशत अथवा उससे कम पोलिएस्टर वाले सूती फेब्रिक्स पर उसी दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का है जो 40 प्रतिशत से अधिक पोलिएस्टर वाले सूती फेब्रिक्स पर लागू है। इन प्रस्तावों के फलस्वरूप पूरे वर्ष में लगभग 23 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होगा।

122. लोगों को जरूरी औषधियां वहनीय कीमतों पर उपलब्ध कराने के हमारे प्रयास में, मेरा प्रस्ताव पांच विनिर्दिष्ट मिरगी-रोधी सूत्रों (फार्मूला) को पूर्ण रूप से उत्पाद-शुल्क से मुक्त करने का है। इस समय कुछ औषध मध्यवर्तियों तथा थोक औषधियों पर रियायती दर पर आयात शुल्क लगता है। मेरा इस रियायत को कुछ और औषध मध्यवर्तियों तथा थोक औषधियों पर भी लागू करने तथा कुछ और औषध मध्यवर्तियों पर उत्पाद शुल्क में रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव है।

123. लघु, खादी और ग्रामोद्योगों को विशेष प्राथमिकता प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रस्ताव इस क्षेत्र में उत्पाद शुल्क में कुछ और रियायतें प्रदान करने का है। इस समय, पंजीकृत तरकारी समितियों, महिला समितियों अथवा खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्य संस्थाओं द्वारा ग्रामोद्योग क्षेत्रों में विनिर्मित 100 रुपये प्रति जोड़े से अधिक कीमत के जूते पूर्णतः मुक्त हैं। मेरा प्रस्ताव छूट को सोमा 150 रुपये प्रति जोड़े को कीमत तक बढ़ाने का है। इसके अलावा, मेरा प्रस्ताव, पंजीकृत समितियों, महिला समितियों और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं आदि द्वारा ग्रामोद्योग क्षेत्रों में विनिर्मित विनिर्दिष्ट उत्पादों को उत्पाद-उत्पाद-शुल्क को पूरा छूट का लाभ सिन्थेटिक डिटरजेंटों पर भी लागू करने का है।

124. अब मैं उन कुछ उपायों का जिक्र करना चाहूंगा जिन्हें मैं हमारे पर्यावरण को सुरक्षा व पारिस्थितिकी के परिरक्षण के लिए प्रस्ताव करना चाहता हूं। घटती हुई वन सम्पदा को ध्यान में रखते हुए हमें अपने दुर्लभ साधनों का परिरक्षण करना चाहिए। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा है, अपशिष्ट कागज तथा कच्चे काष्ठ पर आयात शुल्क को बहो दरें लागू करने का प्रस्ताव है जो 15 दिसम्बर 1990 से पहले प्रचलित था। मेरा प्रस्ताव, एल्गुमिनियम के दरवाजों, खिड़कियों तथा उनके फ्रेमों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने की भी है ताकि निर्माण कार्यकलापों में काष्ठ के स्थान पर एल्गुमिनियम के उपयोग को बढ़ावा मिले। फलाई ऐश,

जो एक प्रदूषक पदार्थ है के उत्पादक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मेरा प्रस्ताव 25 प्रतिशत से अधिक प्लाई ऐश अथवा फोसफोर्जिप्सम वाले विभिन्न निर्माण संघटकों को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने का है। मेरा प्रस्ताव, फोसफोर्जिप्सम को सी, जो उर्वरक उद्योग का एक उप-उत्पाद है, उत्पाद-शुल्क से मुक्त करने का है, ताकि किसानों द्वारा इसके प्रयोग को प्रोत्साहन मिले।

125. इस बात से शायद ही कोई असहमति व्यक्त कर कि हाल ही के समय में मैं सबसे ज्यादा परेशान वित्त मंत्रियों में से एक हूँ। मेरे सम्मुख जो दूसरे कार्य हैं उसके निष्पादन के लिए मुझे समाचार-पत्रों के सहयोग की जरूरत है। सद्भावना के तौर पर मेरा प्रस्ताव मानक न्यूजप्रिंट को आयात शुल्क से मुक्त करने का है, जिस पर इस समय 450 रुपये प्रति मी. टन का शुल्क लगता है। मैंने मुद्रण तथा समाचार-पत्र उद्योग द्वारा अपेक्षित कतिपय विनिर्दिष्ट मशीनरी और उपस्कर पर आयात शुल्क को वही दरें लागू करने का प्रस्ताव किया है जो 15 दिसम्बर, 1990 से पहले लागू थी। समाचार-पत्रों के मान्यताप्राप्त कैमरामैनों द्वारा फोटोग्राफिक सामान के निःशुल्क आयात की सीमा वर्तमान 30,000 रुपये के स्तर से बढ़कर 60,000 रुपये की जा रही है। इन प्रस्तावों के फलस्वरूप पूरे वर्ष में 9 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व की हानि होगी।

126. वित्त मंत्री के रूप में मेरी नियुक्ति होने के बाद मुझे अपना काफी समय कार्यालय में ही बिताना पड़ा है। यह स्वाभाविक है कि इससे मेरी पत्नी बहुत नाखुश हैं। यह सदन इस बात से सहमत होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए यह अच्छा नहीं है, यदि देश के वित्त मंत्री के संबंध उसके अपने घर के वित्त मंत्री के साथ कटु हो जाएं। मेरा प्रस्ताव है कि एग्जुमीनियम, तांबे और स्टेनलेस स्टील से बने बतनों के लिए फिलहाल उपलब्ध उत्पाद शुल्क से अदायगी की पूर्ण छूट को कुछ अन्य घरेलू मर्चों, विशेषरूप से टिफिन बक्सों पर लागू कर दिया जाए।

127. इसी बात ने मुझे यह प्रस्ताव करने के लिए प्रेरित किया है कि अर्द्ध-स्वचालित क्रिया द्वारा निर्मित विनिर्दिष्ट टेबलवेयर पर उत्पाद-शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाए। घर में शांति बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए और साथ ही माउथ ब्लोन प्रक्रिया द्वारा ग्लासवेयर के विनिर्माण में श्रम की गहन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रस्ताव ऐसे ग्लासवेयर पर उत्पाद शुल्क को कम करके 15 प्रतिशत समान रूप से करने का है। कुछ लोग मेरे इस काम को पसंद नहीं करेंगे, परंतु मुझे विश्वास है कि अधिकांश गृहिणियां जो कीमतों के बढ़ते हुए स्तर से दुखी हैं मेरी इस कार्यवाही की सराहना करेंगी।

128. अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुसार, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास करूंगा कि अप्रत्यक्ष करों का जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर अत्यधिक

बोझ न पड़े। घोषणापत्र में सूचीबद्ध मर्चों में से इस समय तक साइकिलों, न्यूजप्रिंट, पोस्टकार्डों, अन्तर्देशीय पत्रों तथा लिफाफों व स्टोय की कतिपय किस्मों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं है। सूती साड़ियों और धोतियों पर विक्री कर के एवज में केवल अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगता है, जो सारा का सारा राज्यों को मिलता है। मैंने पहले ही खाद्य तेलों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने का प्रस्ताव किया है। 60 वाट तक के बिजली के बल्ब पहले ही उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं। अब मेरा प्रस्ताव अधिक वाट वाले बल्बों को भी उत्पाद शुल्क की अदायगी से मुक्त करने का है, जिन पर इस समय एक रुपये प्रति बल्ब के हिसाब से शुल्क लगता है। ऊर्जा बचन वाले चूल्हे भी उत्पाद शुल्क से मुक्त होंगे। मैं, 50 सी. सी. से अधिक किन्तु 75 सी. सी. से अतिरिक्त इंजिन क्षमता वाले दुर्घटिया वाहनों पर उत्पाद शुल्क को 20 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

129. मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि मैंने जो कर राहत दी हैं वे स्वयं आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के संबंध में हमारे घोषणापत्र में उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक बहुत छोटा कदम है। इस उद्देश्य के अनुसरण में, मैं उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता हूँ कि वे हमारी सरकार के साथ मिलकर बैठें ताकि, वे प्रक्रियाएं तय की जा सकें जिनके अनुसार हमारे चुनाव घोषणापत्र में दिए गए कीमत संबंधी लक्ष्यों को आम आदमी की भलाई के लिए किस प्रकार अच्छे ढंग से प्राप्त किया जा सके।

130. पर्यटन, जो विदेशी मुद्रा के अर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, को बढ़ावा देने के लिए मैं साहसिक खेलकूद से संबंधित उपस्कर पर आयात शुल्क की दरों को, जो लगभग 100 से 300 प्रतिशत तक हैं, कम करके 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

131. रुपये के विनिमय दर संबंधी हाल ही के समायोजन को देखते हुए, मैं सामान भत्ते एवं वास्तविक उपहारों की शुल्क-रहित सीमाएं उपयुक्त रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ; उदाहरण के लिए व्यक्तिगत सामान के लिए सामान्य शुल्क रहित भत्ते को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,400 रुपये किया जा रहा है।

132. अब मैं, अतिरिक्त राजस्व जुटाने से संबंधित मुख्य प्रस्तावों की चर्चा करूंगा।

133. इस समय, मूल उत्पाद शुल्क के 5 प्रतिशत की दर से विशेष उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। मैं इसे बढ़ाकर मूल उत्पाद शुल्क का 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि विशेष उत्पाद शुल्क, मूल उत्पाद शुल्क का केवल एक प्रतिशतांक है, जिसका मूल्यों पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी वस्तु पर मूल उत्पाद शुल्क, मान लीजिए 20 प्रतिशत है, तो केवल 1 प्रतिशत की ही वृद्धि होगी। चाय, काफी,

चीनी, क्लोरोसिन, माचिस तथा वनस्पति, जो सर्वसाधारण के उपभोग की वस्तुएं हैं, इस विशेष उत्पाद शुल्क से मुक्त रहेंगी। इसके अतिरिक्त, मैं इस बात को सुनिश्चित कर रहा हूँ कि विशेष उत्पाद शुल्क में कोई भी वृद्धि डीजल तथा दु-पहिया वाहनों पर लागू नहीं होंगी इस प्रस्ताव से पूरे वर्ष में 1,010 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा, जिसका एक बड़ा हिस्सा राज्यों को मिलेगा।

134. हमारे चुनाव घोषणापत्र में एक यह वायदा किया गया था कि विशिष्ट उपभोग पर नियंत्रण रखने के लिए नौतियां और उमाय तैयार की जाएंगे। इसके अनुसरण में, मेरा प्रस्ताव रेफीजरेटों, एयर कंडीशनरों, जिनमें कम्प्रेसर भी सम्मिलित हैं, मोटर कारों, आडियो और वीडियो कैसेट टेपों, वीडियो कैसेटों, पिक्चर ट्यूबों, रंगीन टेलीविजन सेटों, बीसी आर तथा बीसीपी पर उत्पाद शुल्क दरों में वृद्धि करने का है।

135. मैं रेफीजरेटों पर, उनकी क्षमता के अनुसार, 200 रुपये से लेकर 800 रुपये तक तथा एयरकंडीशनरों पर 2,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक के उत्पाद शुल्क की बढ़ोतरी का प्रस्ताव करता हूँ। मैं 7.5 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले एयर कंडीशनरों के कम्प्रेसरों पर उत्पाद शुल्क में 1,800 रुपये की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इन प्रस्तावों से पूरे वर्ष में लगभग 91 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

136. मोटर कारों पर इस समय 50 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगता है। मैं इस उत्पाद शुल्क को बढ़ा कर 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। लेकिन टैक्सियों पर 30 प्रतिशत की दर से लगने वाले शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रस्ताव से प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

137. मैं आडियो कैसेट टेपों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा वीडियो कैसेट टेपों पर 10.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव से पूरे वर्ष में 29 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा।

138. टेलीविजन सेटों के संबंध में, मैं इनके स्क्रीन के आकार के अनुसार उत्पाद शुल्क में 500 रुपये तथा 700 रुपये प्रति सेट की वृद्धि का प्रस्ताव करता हूँ। मैं रंगीन पिक्चर ट्यूबों पर भी उत्पाद शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं श्याम-श्वेत टेलीविजनों को उत्पाद-शुल्क से मुक्त रख रहा हूँ। तथा यह बोझ अब पिक्चर ट्यूबों पर पड़ेगा। मैं वा एच एस टाइप के बी सी आर तथा बी सी पी पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 400 रुपये तथा 250 रुपये और अन्य प्रकार के बी सी आर तथा बी सी पी पर 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव करता हूँ। इससे पूरे वर्ष में 66 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होगी।

139. धूम्रपान, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर रोक लगाने के लिए प्रत्येक वित्त मंत्री को कुछ न कुछ प्रयास करना पड़ता है। मैं भी इस परम्परा का पालन करते हुए सिगरेट पर कर में वृद्धि करूंगा। मैं, फिल्टर-रहित सिगरेट के संबंध में इनकी लम्बाई के अनुसार प्रति हजार सिगरेटों पर 10 रुपये से लेकर 25 रुपये तक के शुल्क की वृद्धि का प्रस्ताव करता हूँ। फिल्टर वाली सिगरेट पर 35 रुपये से लेकर 125 रुपये प्रति हजार सिगरेट की दर से शुल्क में वृद्धि होगी। लेकिन, 85 मि.मी. से अधिक आकार की फिल्टर वाली सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क टैरिफ में निर्धारित अधिकतम सीमा दर लागू होगी। इससे हमें पूरे वर्ष में 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

140. ब्रांड वाली हस्त-निर्मित बीड़ियों पर 3.75 रुपये प्रति हजार की दर से उत्पाद शुल्क लगता है। यद्यपि सिगरेटों पर शुल्क में लगभग हर वर्ष वृद्धि की गई है, परन्तु बीड़ियों पर 1986 से उत्पाद शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मेरे विचार से देश के राजकोष में अपने अंशदान में वृद्धि करने के अवसर से बीड़ी पीने वालों को वंचित नहीं रखा जाना चाहिए इसलिए, मैं पेपर-रोलड बीड़ियों को छोड़कर, ब्रांड वाली हस्तनिर्मित किस्म की बीड़ियों पर शुल्क को बढ़ाकर 4.50 रुपये प्रति हजार करने का प्रस्ताव करता हूँ। पेपर-रोलड बीड़ियों पर 10 रुपये प्रति हजार की दर से शुल्क लगेगा लेकिन अन्य हस्त निर्मित बीड़ियों की वर्तमान कर मुक्ति व्यवस्था जारी रहेगी। इससे पूरे वर्ष में 33 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

141. तम्बाकू रहित पान मसालों पर उत्पाद-शुल्क विशिष्ट दर से लागू होता है। मैं इस पर उत्पाद शुल्क 5 रुपये और 10 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूँ, जो इसके मूल्य पर आधारित होगा। इससे पूरे वर्ष में 4 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होगा।

142. चीनी पर उत्पाद शुल्क, जिसे विशिष्ट आधार पर लगाया जाता है, में 1983 से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यानुसार भार में कमी आई है, क्योंकि पिछली अवधि के दौरान चीनी की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। मूल्यानुसार, लेवी वाली चीनी पर उत्पाद शुल्क का वर्तमान भार, खुली बिक्री वाली चीनी पर भार को तुलना में अधिक है। इस स्थिति में सुधार करने के लिए, मैं खुली बिक्री वाली चीनी पर उत्पाद शुल्क को 50 रुपये प्रति किबटल के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 71 रुपये प्रति किबटल करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे खुली बिक्री वाली चीनी, जिसका मूल्य बाजार में लगभग 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, पर 21 पैसे प्रति किलोग्राम का अतिरिक्त कर भार पड़ेगा। इस प्रस्ताव से पूरे वर्ष में 122 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली लेवी वाली चीनी पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी करने का मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है।

143. मैं खांडसारी चीनी को, वस्तुओं की उस सूची में से, जिन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगता है, बाहर रखने का प्रस्ताव करता हूँ। राज्य सरकारें, यदि चाहें तो, खांडसारी चीनी पर बिक्री कर लगा सकती हैं।

144. शीरा, जो कि चीनी उद्योग का एक उप-उत्पाद है, पर अभी 120 रुपए प्रति टन की दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। शीरे के एक बड़े भाग का उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है। इन परिस्थितियों में हम पर अधिक दर से उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। तदनुसार, मैं शीरे पर उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 150 रुपए प्रति टन करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इसने वर्ष में 13 करोड़ रुपए का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा।

145. सरकार द्वारा घोषित किये गये उपायों से होने वाले राजस्व परिणामों का विवरण वित्त विधेयक के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

146. मैंने, सीमा शुल्क अधिनियम और उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क संबंधी टैरिफों में परिवर्तन करने के उद्देश्य से वित्त विधेयक में कुछ संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया है। इनमें, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन टो हारमोनाइज्ड सिस्टम की शर्तों के अनुरूप हमारे देश में अपनाये गये हारमोनाइज्ड कोमोडिटी डिस्क्रिप्शन एण्ड कोडिंग सिस्टम के संशोधनों पर आधारित सीमा शुल्क टैरिफ में कुछ परिणामतः संशोधन सम्मिलित हैं। ये संशोधन केवल समर्थनकारी प्रायधान हैं तथा इनमें राजस्व संबंधी परिणामों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, मौजूदा अधिसूचनाओं में से कुछेक में संशोधन करने के प्रस्ताव हैं। सदन का समय बचाने की दृष्टि से मेरा उनके बारे में बताने का प्रस्ताव नहीं है।

147. उत्पाद शुल्कों में की गई बड़ोतरियों से पूरे वर्ष के दौरान 1,799.00 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा, जबकि राहत की राशि 358.06 करोड़ रुपये होगी। इस प्रकार एक पूरे वर्ष में उत्पाद शुल्कों से 1,440.94 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होगी। जिसमें से राज्यों का हिस्सा 750.04 करोड़ रुपये होगा तथा शेष 690.90 करोड़ रुपये केन्द्र को प्राप्त होंगे। सीमा शुल्कों में परिवर्तन करने संबंधी प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में 822.52 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि तथा 78.00 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ प्राप्त होगा। सीमा शुल्कों से संबंधित प्रस्तावों के परिणामस्वरूप, एक पूरे वर्ष में 744.52 करोड़ रुपये की निवल हानि होगी। इस प्रकार, सीमा शुल्कों और उत्पाद शुल्कों से प्राप्त होने वाले 696.42 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवल राजस्व की तुलना में, एक पूरे वर्ष में, राज्यों को 750.04 करोड़ रुपये का लाभ होगा, जबकि केन्द्र को 53.62 करोड़ रुपये की हानि होगी।

148. सीमा शुल्कों और उत्पाद शुल्कों में परिवर्तनों को 25 जुलाई, 1991 से प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियां यथामय सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

149. प्रत्यक्ष करों के संबंध में मैंने जो प्रस्ताव किए थे, उनमें 2,139 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी, जिनमें से 97 करोड़ रुपए राज्यों को और 2,042 करोड़ रुपए केन्द्र को प्राप्त होंगे। सीमा-शुल्क के संबंध में मेरे प्रस्तावों से चालू वर्ष में 510 करोड़ रुपए के निवल राजस्व की हानि होगी तथा संघ उत्पाद-शुल्क में संबंधित प्रस्तावों के फल-स्वरूप चालू वर्ष के শেষ भाग में 988 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें से राज्यों के हिस्से 515 करोड़ रुपए आगें तथा केन्द्र हिस्से में 473 करोड़ रुपए आगें। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, दोनों की ही ध्यान में रखते हुए, चालू वर्ष में केन्द्र को 2,005 करोड़ रुपए का निवल लाभ होने का अनुमान है और इसके साथ केन्द्र का बजटीय घाटा वर्तमान वर्ष के दौरान 7,719 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, राजस्व घाटा 13,854 करोड़ रुपए और राजकोषीय घाटा 37,727 करोड़ रुपए होगा।

150. महोदय, अब मैं अपने भाषण को लगभग समाप्त करता हूँ। समाप्त करने के पूर्व मैं एक व्यक्तिगत बात कहना चाहूँगा। वर्षों पूर्व, एक पत्र में जिसे जवाहरलाल नेहरू ने युवा इंदिरा गांधी को लिखा था, उन्हें मलाइ दी थी कि देश के कामकाज में तिपटने समय एक व्यक्ति को भावनाओं से ओतप्रोत होना चाहिए, परन्तु कभी भी भावुक नहीं होना चाहिये। परन्तु, अगर मैं ऐसे अवसर पर कुछ भावुक होने में बच नहीं सकूँ तो सदन मुझे क्षमा करेगा।

151. मेरा जन्म एक निर्धन परिवार में एक सतत रूप से सुखा ग्रस्त गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का एक हिस्सा है। विध्वंसितालय की छात्रवृत्तियों और अनुदानों के फलस्वरूप मेरे लिये भारत तथा साथ ही इंग्लैंड में कालिज में शिक्षा प्राप्त करना संभव हो सका इस देश ने अपने प्रभुसत्ता सम्पन्न गणराज्य के कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करके मुझे सम्मानित किया है। यह एक ऐसा ऋण है, जिसे मैं कभी भी पूरी तरह से अदा नहीं कर सकता। मैं सबसे अधिक यही कर सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने देश की सेवा करने का वचन दूँ। मैं ऐसा करने के लिये सदन को वचन देता हूँ। एक वित्त मंत्री को सख्त होना पड़ता है। मैं ऐसा बनने का प्रयास करूँगा। जब राष्ट्र के हितों की रक्षा करने की बात आयेंगी तो मैं दृढ़ रहूँगा। परन्तु मैं वायदा करता हूँ कि भारत को जनता के बारे में सोचते समय मैं विनम्र रहूँगा। मैं किसी भी तरह अपने समानता और सामाजिक न्याय को खोज में राष्ट्र की दृढ़ और अटल वचनबद्धता से मुंह नहीं

BUDGET 1991-92

SPEECH OF

SHRI MANMOHAN SINGH,

MINISTER OF FINANCE

24th July, 1991

PART A

Sir,

I rise to present the budget for 1991-92. As I rise, I am overpowered by a strange feeling of loneliness. I miss a handsome, smiling, face listening intently to the Budget Speech. Shri Rajiv Gandhi is no more. But his dream lives on: his dream of ushering India into the twenty-first century; his dream of a strong united, technologically sophisticated but humane India. I dedicate this budget to his inspiring memory.

2. The new Government, which assumed office barely a month ago, inherited an economy in deep crisis. The balance of payments situation is precarious. International confidence in our economy was strong until November, 1989 when our Party was in office. However, due to the combined impact of political instability witnessed thereafter, the accentuation of fiscal imbalances and the Gulf crisis, there was a great weakening of international confidence. There has been a sharp decline in capital inflows through commercial borrowing and non-resident deposits. As a result, despite large borrowings from the International Monetary Fund in July, 1990 and January, 1991, there was a sharp reduction in our foreign exchange reserves. We have been at the edge of a precipice since December, 1990 and more so since April, 1991. The foreign exchange crisis constitutes a serious threat to the sustainability of growth processes and orderly implementation of our development programmes. Due to the combination of unfavourable internal and external factors, the inflationary pressures on the price level have increased very substantially since mid-1990. The people of India have to face double digit inflation which hurts most the poorer sections of our society. In sum, the crisis in the economy is both acute and deep. We have not experienced anything similar in the history of independent India.

3. The origins of the problem are directly traceable to large and persistent macro-economic imbalances and the low productivity of investment, in particular the poor rates of return on past investments. There has been an unsustainable increase in Government expenditure. Budgetary subsidies, with questionable social and economic impact, have been allowed to grow to an alarming extent. The tax system still has many loopholes. It lacks transparency so that it is not easy to assess the social and economic impact of various concessions built into its structure. The public sector has not been managed in a manner so as to generate large investible surpluses. The excessive and often indiscriminate protection provided to industry has weakened the incentive to develop a vibrant export sector. It has also accentuated disparities in income and wealth. It has worked to the disadvantage of the rural economy. The increasing difference between the income and expenditure of the Government has led to a widening of the gap between the income and expenditure of the economy as a whole. This is reflected in growing current account deficits in the balance of payments.

4. The crisis of the fiscal system is a cause for serious concern. The fiscal deficit of the Central Government, which measures the difference between revenue receipts and total expenditure, is estimated at more than 8 per cent of GDP in 1990-91, as compared with 6 per cent at the beginning of the 1980s and 4 per cent in the mid 1970s. This fiscal deficit had to be met by borrowing. As a result, internal public debt of the Central Government has accumulated to about 55 per cent of Gross Domestic Product (GDP). The burden of servicing this debt has now become onerous. Interest payments alone are about 4 per cent of GDP and constitute almost 20 per cent of the total expenditure of the Central Government. Without decisive action now, the situation will move beyond the possibility of corrective action.

मोड़ंगा । मैं यह कभी नहीं भूलूंगा कि अंततः सभी आर्थिक प्रक्रियाएँ हमारी जनता के हितों की सेवा करने के लिये हैं। सामाजिक न्याय और उत्कृष्टता की खोज के लिये वचनबद्धता के माध्यम से ही हम अपने लोगों से संप्रति राशि का, विकास के लिये अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं, उसे एक ऊँचा नैतिक उद्देश्य प्रदान कर सकते हैं और राष्ट्रीय एकता की भावना को जोड़ित रख सकते हैं। मैं यह कभी नहीं भूलूंगा कि गरीबी, अज्ञानता और बीमारी के संकट को दूर करने के लिये आवश्यक बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक सुधार केवल तभी सफल हो सकते हैं, जब इनके पीछे उच्च आदर्शवादिता, आत्म-व्याप और निष्ठा की भावना निहित हो।

152. हमारा देश इस समय जिस गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, उसके संबंध में सरकार की ओर से दृढ़ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हम इस भूमिका को निभाने के लिये पूरी तरह तैयार हैं। हमारी पार्टी देश को एक प्रभावी सरकार उपलब्ध कराएगी। हमारी जनता, हमारी मालिक है। हम महसूस करते हैं कि हमारी सरकार की भूमिका हमारी जनता को शक्ति प्रदान करने की होगी कि वे अपनी पूरी क्षमता का ग्रहण कर सकें। यह बजट, एक व्यापक दृष्टिकोण, हमारी एक सुविचारित कार्यनीति और भारत को एक बार फिर गतिशील बनाने के लिये प्रभावशाली कार्रवाई कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण चटक है।

153. महोदय, हम उस लम्बे और कठिन मार्ग की कठिनाइयों को कम करने नहीं बता रहे हैं, जिस पर हमने चलने का निश्चय किया है। परन्तु जैसा कि, विक्टर ह्यूगो ने एक बार कहा था, "विश्व में कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है"। मैं इस महान सदन को सुझाव देता हूँ कि विश्व में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उभरना एक ऐसा ही विचार है। पूरे विश्व के सामने मैं जोर देकर और स्पष्टतः कहता हूँ: अब भारत सजग है, हम विजयी होंगे, हम कामयाब होंगे।

154. इन शब्दों के साथ अपना बजट इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

श्रीमती जयन्ती कश्यपलिया,

अवर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

(Budget Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 1991

No. F. 8(1)-13(D)/91.—The following Budget speech 1991-92 by the Hon. Finance Minister is published for general information:—

5. The balance of payments situation is most difficult. The current account deficit, which was about 2 per cent of GDP for several years, is estimated to be more than 2.5 per cent of GDP in 1990-91. These persistent deficits, which were inevitably financed by borrowings from abroad, have led to a continuous increase in external debt which, including non-resident Indian (NRI) deposits, is estimated at 23 per cent of GDP at the end of 1990-91. Consequently, the debt service burden is estimated at about 21 per cent of account receipts in 1990-91. These strains were stretched to a breaking point on account of the Gulf crisis last year. The balance of payments has lurched from one liquidity crisis to another since December, 1990. The current level of foreign exchange reserves, in the range of Rs. 2500 crores, would suffice to finance imports for a mere fortnight.

6. The price situation, which is of immediate concern to the vast mass of our people, poses a serious problem as inflation has reached a double digit level. During the fiscal year ending 31st March, 1991 the wholesale price index registered an increase of 12.1 per cent, while the consumer price index registered an increase of 13.6 per cent. The major worrisome feature of the inflation in 1990-91 was that it was concentrated in essential commodities. The prices of these commodities rose in spite of the three good monsoons in a row and hence the three successive bumper harvests. Inflation hurts everybody, more so the poorer segments of our population whose incomes are not indexed.

7. There is no time to lose. Neither the Government nor the economy can live beyond its means year after year. The room for manoeuvre, to live on borrowed money or time, does not exist any more. Any further postponement of macro-economic adjustments, long overdue, would mean that the balance of payments situation, now exceedingly difficult, would become unmanageable and inflation, already high, would exceed limits of tolerance. For improving the management of the economy, the starting point, and indeed the centre-piece of our strategy, should be a credible fiscal adjustment and macro-economic stabilisation during the current financial year, to be followed by continued fiscal consolidation thereafter. This process would, inevitably, need at least three years, if not longer, to complete. But there can be no adjustment without pain. The people must be prepared to make necessary sacrifices to preserve our economic independence and restore the health of our economy.

8. In the macro-management of the economy, over the medium-term, it should be our objective to progressively reduce the fiscal deficit of the Central Government, to move towards a significant reduction of the revenue deficit, and to reduce the current account deficit in the balance of payments. It is only such prudent management that would enable us to curb the exponential growth in internal and external debt and limit the burden on debt servicing, for the Government and the country, to manageable levels. Indeed, we must make a conscious effort to reduce the internal debt of the Government and the external debt of the nation, so that we rely more and more on our own resources to finance the process of development. During the period of transition, it shall be our endeavour to minimise the burden of adjustment on the poor. We are committed to adjustment with a human face. It will also be our endeavour that the adjustment process does not adversely affect the underlying growth impulses in our economy. We do not have time to postpone adjustment and stabilisation. We must act fast and act boldly. If we do not introduce the needed correctives, the existing situation can only retard growth, induce recession and fuel inflation, which would hurt the economy further and impose a far greater burden on the poor.

9. Macro-economic stabilisation and fiscal adjustment alone cannot suffice. They must be supported by essential reforms in economic policy and economic management, as an integral part of the adjustment process, reforms which would help to eliminate waste and inefficiency and impart a new element of dynamism to growth processes in our economy. The thrust of the reform process would be to increase the efficiency

and international competitiveness of industrial production, to utilise for this purpose foreign investment and foreign technology to a much greater degree than we have done in the past, to increase the productivity of investment to ensure that India's financial sector is rapidly modernised, and to improve the performance of the public sector, so that the key sectors of our economy are enabled to attain an adequate technological and competitive edge in a fast changing global economy. I am confident that, after a successful implementation of stabilisation measures and the essential structural and policy reforms, our economy would return to a path of a high sustained growth with reasonable price stability and greater social equity.

10. Thanks to the efforts of Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi, we have developed a well diversified industrial structure. This constitutes a great asset as we begin to implement various structural reforms. However, barriers to entry and limits on growth in the size of firms, have often led to a proliferation of licensing and an increase in the degree of monopoly. This has put shackles on segments of Indian industry and made them serve the interests of producers but not pay adequate attention to the interests of consumers. There has been inadequate emphasis on reduction of costs, upgradation of technology and improvement of quality standards. It is essential to increase the degree of competition between firms in the domestic market so that there are adequate incentives for raising productivity, improving efficiency and reducing costs. In the pursuit of this objective, we have announced important changes in industrial policy which will bring about a significant measure of deregulation in the domestic sector, consistent with our social objectives and the binding constraints on the balance of payments.

11. The policies for industrial development are intimately related to policies for trade. There can be no doubt that protection was essential in the initial phase of our industrial development, so that we could go through the learning period without disruption. The past four decades have witnessed import substitution which has not always been efficient and has some times been indiscriminate. The time has come to expose Indian industry to competition from abroad in a phased manner. As a first step in this direction, the Government has introduced changes in import-export policy aimed at a reduction of import licensing, vigorous export promotion and optimal import compression. The exchange rate adjustments on 1st and 3rd July, 1991 and the enlargement and liberalisation of the replenishment licence system constitute the two major initial steps in the direction of trade policy reform. They represent the beginning of a transition from a regime of quantitative restrictions to a price based mechanism.

12. After four decades of planning for industrialisation, we have now reached a stage of development where we should welcome, rather than fear, foreign investment. Our entrepreneurs are second to none. Our industry has come of age. Direct foreign investment would provide access to capital, technology and markets. It would expose our industrial sector to competition from abroad in a phased manner. Cost, efficiency, and quality would begin to receive the attention they deserve. We have, therefore, decided to liberalise the policy regime for direct foreign investment in the following manner. First, direct foreign investment in specified high priority industries, with a raised limit for foreign equity at 51 per cent, would be given prompt approval, if equity inflows are sufficient to finance the import of capital goods at the stage of investment and if dividends are balanced by export earnings over a period of time. Second, foreign equity upto 41 per cent would be allowed for trading companies primarily engaged in export activities. Third, a special board would be constituted to negotiate with a number of large international firms and approve direct foreign investment in selected areas; this would be a special regime to attract substantial investment that would provide access to high technology and to world markets.

13. For the founding fathers of our Republic, a public sector that would be vibrant, modern, competitive and capable of generating large surplus was a vital element in the

strategy of development. The public sector has made an important contribution to the diversification of our industrial economy. But there have been a number of shortcomings. In particular, the public sector has not been able to generate internal surpluses on a large enough scale. At this critical juncture, it has therefore become necessary to take effective measures so as to make the public sector an engine of growth rather than an absorber of national savings without adequate return. This has been widely accepted, but thought and action in this regard are still far apart. To bridge this gap, the portfolio of public sector investments would be reviewed so as to concentrate the future operations of the public sector in areas that are strategic for the nation, require high technology for the economy, and are essential for the infrastructure. In order to raise resources, encourage wider public participation and promote greater accountability, upto 20 per cent of government equity in selected public sector undertakings would be offered to mutual funds and investment institutions in the public sector, as also to workers in these firms. Public enterprises which are chronically sick and which cannot be turned around, will be referred to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), or to a similar high-powered body to be set up, for the formulation of revival or rehabilitation schemes; a social security mechanism will be created to fully protect the interests of the workers likely to be affected by the rehabilitation packages of the BIFR. Autonomy in management, and corresponding accountability, would be provided through a system of memorandums of understanding between the Government and public sector enterprises.

14. Our banking system and financial institutions are at the very core of the financial infrastructure in the economy. The widening and deepening of our financial system have helped the spread of institutional finance over a vast area and have contributed significantly to the augmentation of our savings rate, particularly financial savings. This has been a most commendable achievement, but our financial system has developed certain rigidities and some weaknesses which we must address now. The objective of reform in the financial sector would be to preserve its basic role as an essential adjunct to economic growth and competitive efficiency, while improving the health of its institutions. In this task, it is essential to ensure capital adequacy, introduce prudential norms and improve profitability of our commercial banks and financial institutions. There are no magic solutions. These are complex issues which need careful consideration. Therefore, I propose to appoint a high level committee to consider all relevant aspects of structure, organisation, functions and procedures of the financial system. This committee would advise the Government on appropriate measures that would be needed to enhance the viability and health of our financial sector so that it can better serve the needs of the economy without any sacrifice of the canons and principles of a sound financial system.

15. Interest rates are a crucial dimension of the financial sector. In the formative stages of the development of credit markets, administrative intervention in interest rates is both necessary and desirable. At the present stage of our development, however, we can begin to relax the degree of intervention and impart a greater flexibility to the structure of interest rates. The Reserve Bank of India has already taken an important step in this direction, by stipulating a floor rate of interest and providing freedom to commercial banks to charge interest rates above the floor level based on their perceptions of risk. The Government proposes to extend a similar freedom to term-lending financial institutions, where the minimum interest rate would be 15 per cent, and these institutions would be free to charge an interest rate in accordance with their perception of the creditworthiness of borrowers. With the exception for tax free bonds for the public sector, it is also proposed to remove all restrictions on interest rates for debentures, both convertible and non-convertible, floated in the capital market. The interest rate on such debt instruments will hereafter be governed by market forces, and the credit rating of such debt instruments will become an integral part of the capital market process. In consultation with the Reserve

Bank of India, the Government would continue to watch the structure of interest rates. Recently, interest rates payable on bank deposits have been increased. I now propose to do a similar thing with regard to interest rates payable under the small saving schemes. Our ultimate objective is to achieve a significant reduction both in the nominal and the real interest rates. This would be possible if the rate of inflation is reduced significantly over the next three years.

16. While presenting the budget for 1987-88, our former Prime Minister the late Shri Rajiv Gandhi had assured this House that for a healthy growth of capital markets, for protecting the rights of investors and for preventing trading malpractices the Government would set up a separate Board for the regulation and orderly functioning of the Stock Exchanges and the securities industry. Although the Board was set up, legislation to give the Board adequate powers was unfortunately not enacted. This shall now be done forthwith and full statutory powers will be given to the Securities and Exchange Board of India for administering the relevant provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act and the Companies Act. Transferring these powers from the Controller of Capital Issues and the Government to an independent body would enable it to effectively regulate, promote and monitor the working of the Stock Exchanges in the country. A comprehensive package of reforms relating to trading on the Stock Exchanges, including a system of national clearing and settlement and setting up of a central depository, is also under active consideration.

17. In regard to Mutual Funds, some progress towards evolving a competitive structure has been made in the last few years with encouraging results. For many investors, mutual funds are a more suitable investment vehicle than direct ownership of shares. The Government is already giving tax incentives for equity-linked savings schemes offered through mutual funds. The Government has now decided to further promote the development of mutual funds by throwing the field open to the private sector and joint sector mutual funds. In order to safeguard the interests of the investing public, and to encourage a healthy growth of the capital markets a comprehensive set of guidelines is being evolved for the operation of all mutual funds. Consideration will also be given to enactment of legislation for this purpose.

18. A comprehensive review of policies and procedures bearing on Non-resident Indian investments shall be carried out and further relaxations made in order to remove all procedural difficulties and impediments to the setting up of industrial and other ventures by Non-resident Indians. New sectors shall be made available to NRIs for investment on a non-repatriation basis, including housing, infrastructure and real estate development. For example, at present, NRIs of foreign nationality are required to obtain specific permission under section 31 of the Foreign Exchange Regulation Act (FERA) to acquire residential property. It is now proposed to provide general exemption from this provision to such persons. However, rental income and proceeds from the sale of such housing will be non-repatriable. For facilitating interaction with the Central Government, to serve as a focal point for NRIs, Government proposes to establish a Chief Commissioner for Non-resident Indians. I would urge State Governments, also, to establish an office of a Commissioner for Non-Resident Indians.

19. I believe that the time has come to evolve a more transparent institutional mechanism for fixing tariffs and domestic prices in sectors where there might still be need for protecting Indian industry against foreign competition and for the determination of administered prices, particularly in the area of public utilities. For this purpose, we propose to restructure the Bureau of Industrial Costs and Prices and to transform it into a Tariff Commission.

20. As we enter the last decade of the twentieth century, India stands at the cross-roads. The decisions we take and do not take, at this juncture, will determine the shape of things to come for quite some time. It should come as no surprise, therefore, that an intense debate rages throughout the coun-

try as to the path we should adopt. In a democratic society it could not be otherwise. What can we learn from this debate? The most important thing that comes out clearly is that we cannot realise our goal of establishing a just society, if we abandon the planning process. But India's future development depends crucially on how well the planning process is adapted to the needs of a fast changing situation. I believe that without an intelligent and systematic coordinated resource use in some major sectors of our economy, development will be lopsided. It will violate deeply cherished values of equity and it will keep India well below its social, intellectual and moral potential. But our planning processes must be sensitive to the needs of a dynamic economy. Over centralisation and excessive bureaucratisation of economic processes have proved to be counter productive. We need to expand the scope and the area for the operation of market forces. A reformed price system can be a superior instrument of resource allocation than quantitative controls. But markets can only serve those who are part of the market system. A vast number of people in our country live on the edges of a subsistence economy. We need credible programmes of direct government intervention focussing on the needs of these people. We have the responsibility to provide them with quality social services such as education, health, safe drinking water and roads. In the same way, the development of capital and technology intensive sectors, characterised by long gestation periods, such as transport and communications and energy will need to be planned with much greater care than ever before. The control of land and water degradation, which threatens the livelihood of millions of poor people in this country, will also require effective Government leadership and action.

21. The challenge that we are facing is without precedent. In its initial stages, the Industrial Revolution in the western world concentrated on the creation of wealth, unmindful of the social misery and inequity which characterised this process. The democratisation of the polity came much later. The socialist experiment in charting a new path for accelerated industrial transformation of an underdeveloped economy and polity did achieve considerable success in developing technological and military capabilities, accumulation of capital for rapid industrial growth and human resources development, in countries such as the USSR. But recent developments have shown that this approach too suffered from major weaknesses, particularly in its allocative efficiency, in the management of technical change, control of environmental degradation and in harnessing the vast latent energy and talents of individuals. In India, we launched an experiment under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru, an experiment which sought to unite the strengths and merits of different approaches to accelerated development of our backward economy. We have achieved considerable success in the field of development, modernisation and greater social equity. However, we are yet far from realising our full potential in all these areas. We have to accomplish the unfinished task, while remaining steadfast in our allegiance to the values of a democratic system.

22. At the same time, we must restore to the creation of wealth its proper place in the development process. For, without it, we cannot remove the stigma of abject poverty, ignorance and disease. But we cannot accept social misery and inequity as unavoidable in the process of creation of wealth. The basic challenge of our times is to ensure that wealth creation is not only tempered by equity and justice but is harnessed to the goal of removal of poverty and development for all.

23. For the creation of wealth, we must encourage accumulation of capital. This will inevitably mean a regime of austerity. We have also to remove the stumbling blocks from the path of those who are creating wealth. At the same time, we have to develop a new attitude towards wealth. In the ultimate analysis, all wealth is a social product. Those who create it and own it, have to hold it as a trust and use it in the interest of the society, and particularly of those who are underprivileged and without means. Years ago, Gandhiji expounded the philosophy of trusteeship. This philosophy should be our guiding star. The austerity that Gandhiji practised and preached is a necessary condition for accelerated economic development in the framework of a democratic polity. The trusteeship that he prescribed for the owners of wealth captured the idea of social responsibility.

24. In highlighting the significance of reform, my purpose is not to give a fill up to mindless and heartless consumerism we have borrowed from the affluent societies of the West. My objection to the consumerist phenomenon is two-fold. First, we cannot afford it. In a society where we lack drinking water, education, health, shelter and other basic necessities, it would be tragic if our productive resources were to be devoted largely to the satisfaction of the needs of a small minority. The country's needs for water, for drinking and for irrigation, rural roads, good urban infrastructure, and massive investments in primary education and basic health services for the poor are so great as to effectively preclude encouragement to consumerist behaviour imitative of advanced industrial societies. Our approach to development as to combine efficiency with austerity. Austerity not in the sense of negation of life or a dry, acid creed that casts a baleful eye on joy and laughter. To my mind, austerity is a way of holding our society together in pursuit of the noble goal of banishing poverty, hunger and disease from this ancient land of ours.

25. Let me now turn to fiscal adjustment during the current financial year. The beginning of any attempt to correct the fiscal imbalance in the economy must be directed at a reduction in expenditure and an increase in income of the Government, so as to reduce the fiscal deficit. In the medium-term, however, our fiscal regime would be sustainable only if revenue receipts not only meet revenue expenditure but also provide a sufficient surplus to finance capital expenditure that does not yield direct economic returns as such, as in defence or in social sectors. Even this would not suffice if investment expenditures in the budget do not earn an adequate return. The elimination of structural imbalances in our fiscal system would require a reduction both in the fiscal deficit and in the revenue deficit as a proportion of GDP. The Union Budget for 1991-92 is an essential first step in this direction.

26. It must be recognised that the necessary reduction in the fiscal deficit, during 1991-92, is a stupendous task. The interim budget presented to Parliament in March 1991 estimated the fiscal deficit at Rs. 38475 crores. But this estimate was based on assumptions about certain decisions that have not been implemented. The postponement of the regular budget has made a formidable task even more difficult because almost four months of the financial year have now elapsed without any effort at fiscal correction. Indeed, past trends in revenue and expenditure suggest that, without any corrective action on our part, the fiscal deficit during 1991-92 could well reach a level of more than Rs. 52000 crores. The difference between the two sets of figures provides the real measure of the fiscal correction needed during the current financial year.

27. According to provisional data available, the more narrowly defined budget deficit, as measured by borrowing through short term Treasury bills, for 1990-91 at Rs. 11430 crores was significantly higher than the revised estimate of Rs. 10722 crores, largely due to a substantial revenue shortfall, particularly in corporation tax revenues. This highlights the handicap with which we begin. Let me now present the scenario for 1991-92.

28. The increasing levels of non-plan expenditure, financed through borrowing, have led to an exponential increase in interest payments by the Government. The revised estimates for interest payments during 1990-91, at Rs. 21850 crores, accounted for as much as 38 per cent of the net revenue receipts of the Central Government. Interest payments during 1991-92, estimated at Rs. 27450 crores, constitute 42 per cent of the net revenue receipts of the Central Government at existing rates of taxation. If the present trends continue without any correction, then interest payments could well account for more than 50 per cent of the net revenue receipts of the Central Government by 1994-95. These magnitudes and proportions only serve to highlight the gravity of the situation and the acute need for a substantial adjustment in non-plan expenditure over the next three years.

29. The revised estimate for total non-plan expenditure in 1990-91 was Rs. 76761 crores. In the normal course, even with the strictest scrutiny but in the absence of specific measures for reducing expenditure, this non-plan expenditure would have increased to a level of Rs. 89000 crores in 1991-92. Any attempt at fiscal correction during the current financial year can be meaningful only if non-plan expenditure is

reduced by at least 10 per cent from the level it would otherwise reach.

30. The single largest component of non-plan expenditure is interest payments. Even if there is a drastic reduction in Government borrowing during this year, interest payments would still be in the range of Rs. 35000 crores in the next financial year. The exponential increase in interest payments can be brought under some measure of control, by 1994-95, only through a strict discipline on government borrowing for a period of three years.

31. The second largest component of non-plan expenditure is the allocation for the defence sector, where the provision in the revised estimates for 1990-91 was Rs. 15750 crores. No attempt at containing non-plan expenditure can succeed if defence is to be excluded. At the same time, it is absolutely essential to ensure that a quest for economy in expenditure does not in any way compromise national security. We must, therefore, seek to limit expenditure without diluting the efficiency and effectiveness of our defence services. Keeping in view all these considerations, it has been decided to provide an outlay of Rs. 16350 crores for defence in the current year.

32. Honourable Members are aware that export subsidies have been abolished with effect from 3rd July, 1991. The export sector is being adequately compensated through the adjustments in the exchange rate and the expansion of the Replenishment Licensing System which were implemented at the beginning of July. Consequently, it is now necessary to provide only Rs. 1224 crores for export subsidies in the budget estimates for 1991-92, as compared with the earlier estimated requirement of Rs. 4200 crores, yielding a saving of as much as Rs. 3000 crores during the remainder of this year.

33. In so far as fertiliser subsidies are concerned, with effect from this evening, low analysis fertilisers such as calcium ammonium nitrate, ammonium chloride, ammonium sulphate and sulphate of potash will be free from price and movement controls. There will be an increase of 40 per cent, on an average, in the price of all other fertilisers. In addition, in respect of single super phosphate, there shall also be a ceiling on the subsidy per tonne payable to producers so as to move towards total deregulation in the next few years; this should act as an incentive for all high cost units to reduce costs and improve efficiency. The necessary notifications in this regard are being issued separately, today, by the Ministry of Agriculture.

34. The economic rationale for an increase in the price of fertilisers is so obvious that it does not need to be stated. Nevertheless, I would like to draw the attention of the House to the fact that there has been no increase in fertiliser prices since July 1981. In these ten years, there has been a continuous increase in the procurement prices of paddy and wheat, as also in the market prices of other crops, received by the agricultural sector. Farmers will be compensated for the proposed increase in the price of fertilisers through suitable increases in procurement prices.

35. We would continue to ensure that 50 per cent of the plan resources are invested in the agricultural and rural sector. The provision for the continuing schemes for assistance to small and marginal farmers for dug wells and shallow tube-wells would be doubled. The ceilings on assistance in difficult areas, where the water table is very low, would be removed. Similarly, the provision for assistance for fresh water and brackish water aquaculture and for oilseeds and pulses production would be substantially stepped up. New schemes are being drawn up to popularise small tractors and matching implements, drip and sprinkler irrigation in areas where water is scarce, and quality seeds in low yield areas. Another new scheme that would be implemented from this kharif season is for providing assistance to State Governments, cooperative societies, and farmers' groups to provide blanket plant protection cover on payment of a small fee in large identified areas under cotton or pulses. It would also be possible to demonstrate the advantages of integrated pest management in

these areas. In order to safeguard any possible loss in production because of increase in fertiliser prices, and any decline in consumption, the credit structure would be strengthened to ensure adequate availability of credit particularly to the small and marginal farmers. Simultaneously, soil testing laboratories and farm advisory services all over the country would be strengthened to ensure efficient use of fertilisers and popularise the use of bio-fertilisers. We would also identify a few irrigation projects that can be completed in this very year and ensure that these are provided the necessary funds. The other new initiatives, also, would not be starved of funds. As far as possible our emphasis will be on provision of quality services to our farmers and not on hand outs and subsidies.

36. The sugar subsidy which is costing the exchequer about Rs. 550 crores per annum is indeed an aberration, which crept into the system from January 1990, when the increase in the levy price paid to producers was not matched by a simultaneous increase in the issue price for consumers in the public distribution system. Small quantities of sugar are made available, mostly in metropolitan and urban areas, under the public distribution system at Rs. 5.25 per kg. whereas the price that most people pay in the market is around Rs. 10 per kg. Government has decided that this subsidy should be abolished forthwith. Consequently, the issue price of sugar under the public distribution system will be increased by 85 paise per kg. to Rs. 6.10 per kg. with effect from this evening. At the same time, the public distribution system is being strengthened to serve more effectively the weaker sections of our population, particularly the rural poor, having special regard to their basic needs for foodgrains such as rice and wheat. The provision for food subsidies in the current year is being stepped up to Rs. 2600 crores, as compared with only Rs. 1800 crores provided in the interim budget and Rs. 2450 crores provided in the revised estimates for 1990-91.

37. As a result of the exchange rate adjustments, at the beginning of July 1991, there would be an increase in the rupee value of the import bill for crude oil and petroleum products. It is, therefore, necessary to raise the prices of petroleum products for domestic consumers. This would also help to restrain the growth in consumption of petroleum products. The price of motor spirit, domestic LPG and aviation turbine fuel for domestic use would be raised by 20 per cent. The prices of other petroleum products, excluding diesel and kerosene for non-industrial use, would be raised by 10 per cent. The price of kerosene, for non-industrial use, would be reduced by 10 per cent which means a 50 per cent roll-back in relation to the increase in the price that came into effect on 15th October, 1990. Even in a most difficult financial situation, this is being done to protect the poor for whom kerosene is an essential source of light and fuel. While there will be no increase in the price of diesel, I would endeavour to protect the interests of the farmers who use diesel. For this purpose, I shall hold discussions with State Governments. The proposed increases in the prices of petroleum products will come into effect from this evening, and the necessary notification in this regard is being separately issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

38. For non-plan expenditure, excluding interest payments, defence and major subsidies, the total provision in the budget estimates for 1991-92 is Rs. 28,073 crores, reflecting a reduction of Rs. 1538 crores compared with the provision in the revised estimates for 1990-91. If we take into account the fact that no separate provision has been made for the payment of additional instalments of dearness allowance by Ministries and Departments in the current year, the total reduction in such other non-plan expenditure will exceed Rs. 2000 crores. In recent years, it has been the usual practice to issue instructions to Ministries that such additional requirements should be accommodated within the approved budget estimates. This has invariably resulted in some programmes on the plan side being deprived of adequate resources. It is my intention to effect maximum possible economies in the non-plan administrative expenditure. Therefore, all Ministries have been requested to prioritise their activities so that those which figure at the bottom of the list can be abridged, while those which have outlived their utility can be abandoned altogether. This exercise has already been initiated by all Ministries and is expected to be completed by the end of August, 1991. With

this approach, the proposed reduction in other non-plan expenditure, which I am promising to the House, would be brought about in a more meaningful manner without leading to a reduction in the provision for plan programmes.

39. There is one large component of non-plan expenditure that is a burden on the exchequer. I refer to the Government's obligation under the Rural Debt Relief Scheme. Unfortunately, there was a gross under-estimation of the total fiscal liability under this scheme which was introduced last year. In addition to the sum of Rs. 1500 crores provided in the revised estimates for last year, we have to provide Rs. 1500 crores in the current year. But this is not all. We may need a similar provision in the next year.

40. As a result of the major adjustments in the sphere of expenditure, which I have outlined in my speech, the budget estimate for total non-plan expenditure in 1991-92 stands at Rs. 79,697 crores. It is simply not possible to reduce interest payments in the short term. The provision for non-plan expenditure, excluding interest payments, in the current year represents a reduction of 4.9 per cent compared with the provisions in the revised estimates for 1990-91, and a reduction of almost 15 per cent in relation to what we would have had to provide this year, but for the specific correctives that are being introduced. We have, thus, more than fulfilled our commitment to reduce non-plan expenditure by 10 per cent, which was stated in our Party's election manifesto.

41. The election manifesto of the Congress Party identifies areas for special emphasis in our strategy of development. These include a substantial augmentation of employment programmes, the construction of dwelling units for the weaker sections of our society, an expansion of the programme for irrigation wells and so on. This would need a change in, and some reorientation of, plan priorities, with a shift towards investment in rural areas and expenditure on programmes designed for the benefit of the poor. Our strategy would, of course, be reflected in the Eighth Five Year Plan, which would now commence on 1 April, 1992. It shall be our endeavour to finalise the Eighth Plan document by the end of this calendar year, so that the annual plans for 1992-93, as well as the budgets of the Centre and the States for that year, reflect the changed priorities.

42. As the Vote on Account had earlier been taken only to cover the expenditure in the first four months, this budget has had to be presented before the end of July, 1991. We have, thus, not had the time to re-orient the Annual Plan for 1991-92 to reflect fully our various concerns. Moreover, this year's annual plan has had to be situated in the context of the massive fiscal correction that we have to put through. In fact, it was first felt that it would be necessary to effect a substantial reduction in budget support for the Central Plan and Central Plan assistance for the States. I am, however, happy to inform the House that with the substantial cuts proposed in non-plan expenditure, it is now possible to protect the flow of Central Plan assistance to States and Union Territories at the level of Rs. 14710 crores, as reflected in the interim budget for 1991-92. The Central plan outlay would, however, show a modest increase at Rs. 42969 crores with a budget support of Rs. 19015 crores.

43. I am aware that in basic infrastructure areas such as power, coal, communications and petroleum, we will have to set our sights much higher. In the present situation, characterised by an acute shortage of foreign exchange, it is, in particular, imperative to augment substantially the domestic production of coal, crude oil, natural gas and electrical energy. Efforts will also have to be made on a crash basis for promoting utmost economy in use of energy through more efficient technologies in industry, agriculture, transport and domestic sectors. The transmission and distribution line losses would also have to be brought down drastically from the present high level of 22 per cent. We shall address ourselves to all these tasks once we are through with taking stock of the situation. It is my earnest hope that, by then, thanks to the fiscal corrections now being put through, the resources position would improve, giving us the necessary flexibility. For the present, it has been my endeavour to maintain essential investment through appropriate support for the Central Plan despite binding constraints on the exchequer.

44. In preparing this budget, I have sought to ensure that the burden of fiscal adjustment does not fall on State Governments. It is my belief that the Central Government must set an example by introducing fiscal correctives, and it is my hope that the State Governments would move in this direction as soon as possible. In particular, I would urge them to ensure prompt payment of dues owed by the State Electricity Boards to the National Thermal Power Corporation, Coal India and the Indian Railways. We cannot allow State level enterprises to become an instrument of unplanned and unauthorised transfer of resources from the Centre to the States. That is neither fair nor equitable. This practice must, therefore, stop forthwith. Simultaneously, State Governments must take effective steps to improve their fiscal performance and streamline the working of their public enterprises. They should not expect me to reward fiscal laxity by permitting them to have recourse to unauthorised overdrafts from the Reserve Bank of India. I want them to be an active partner in the accomplishment of the difficult task of restoring the fiscal health of the country.

45. The process of macro-economic adjustment, which is being initiated with this budget, would take at least three years to complete. This adjustment must have a human face. Therefore, during the period of transition, we shall do everything that is possible to minimise the burden of adjustment on the poor. To some extent, the poor would be protected as the rate of inflation comes down. We shall make determined efforts to control inflation and the price rise. The fiscal strategy of this budget will make a major contribution in this regard. In addition, it will be our endeavour to provide protection to the poor in the form of enhanced outlays in the social sectors. Employment creation and poverty eradication in rural India will continue to receive the highest priority. At the same time, Government is committed to the uplift of the weakest and the most vulnerable sections of our society.

46. The plan outlay for the Ministry of Rural Development is being stepped up from Rs. 3115 crores last year to Rs. 3508 crores this year. Within this the outlay for employment programmes alone is Rs. 2100 crores. The various employment oriented programmes should make it possible to provide nearly 900 million man days of employment. If, this year, we are not aiming at the target of 1000 million man-days mentioned in our manifesto it is because the season when there is maximum need for such employment is already over. The Eighth Plan now under formulation will spell out a comprehensive strategy and programmes to achieve the long term employment objectives, and targets such as those relating to the construction of irrigation wells, urban night shelters and Sulabh Shauchalayas, dwelling units for poor backward classes, scheduled castes and scheduled tribes in the villages, mentioned in our Party's election manifesto.

47. The provision for the rural water supply scheme is being stepped up to Rs. 758 crores, so as to make it possible to set aside Rs. 250 crores for ensuring complete coverage of 'no-source problem villages' by the end of 1992-93. The earlier expectation was that these villages would be covered only by the end of the Eighth Plan period. The late Shri Rajiv Gandhi had attached great priority to this programme and had set up a Technology Mission for this purpose. The programme, which is now being named after Shri Rajiv Gandhi, will be accelerated. We will ensure that resource constraints do not stand in the way of achieving the target.

48. It is a matter of deep concern that we have still not been able to put an end to the dehumanising practice of manual removal of night-soil. The allocation for this programme has in the past been less than adequate. It has now been decided not only to accelerate the programme for the conversion of dry-latrines but also to set up the allocation for the rehabilitation and retraining of scavengers. Towards this end, the allocation for the programme has been increased by Rs. 25 crores and more funds, to the extent necessary, would be provided during the course of the year. Inclusive of the increased provision for this programme, the total outlay for the programmes of the Ministry of Welfare, which is concerned with the welfare of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections of our society, is being stepped up from Rs. 364 crores in 1990-91 to Rs. 479 crores in 1991-92. The outlay for the Department of Women and

Child Development, dealing with perhaps the two most disadvantaged segments of our population among the poor, is being enhanced from Rs. 330 crores last year to Rs. 400 crores this year. For Health and Family Welfare, I am providing a plan outlay of Rs. 1031 crores in 1991-92 as compared with Rs. 950 crores in 1990-91.

49. The allocation of resources for investment in social sectors is of utmost importance for the development of human resources. In this context, there is no need for me to emphasise the importance of education, in particular, elementary education. Our efforts to restructure and revitalise the economy can succeed only if we invest in our people. Particular attention has to be paid to the provision of quality education to children belonging to the scheduled castes, the scheduled tribes and other economically and socially backward classes. Children who belong to the category of first generation learners need special care and attention. If the equality of opportunity is to acquire its true significance, quality education must not remain the exclusive privilege of the children of the rich. The Government is committed to ensure that, whatever be our constraints, the programmes of education will not be allowed to suffer for want of financial support. Every effort will be made to ensure that the constitutional directive of providing free and compulsory education upto the age of 14 years becomes a reality before we enter the twenty first century. In the sphere of higher education and technical education, more resources are needed for modernisation and diversification, but, at the same time, an effort must be made to secure optimum results from the existing investments in these institutions. The requirements of education are vast and we shall have to seek innovative ways of finding resources. Budget support provided by the Central Government and the State Governments are an important source, but cannot continue to remain the only source. I am raising the allocation for education from Rs. 865 crores in 1990-91 to Rs. 977 crores in 1991-92. This allocation is not commensurate with my deep commitment to education and the priority that is attached by the Government to the education sector. I would have liked to do more but we must learn to live with the constraints on the exchequer.

50. We have the third largest number of scientists and technologists in the world. Yet, technology development in our country has not been commensurate either with this number or the investments that we have been making in the science and technology sectors in our successive Five Year Plan. This gap would have to be bridged through a suitable reorientation of the Science and Technology Policy and the way paved for relating science and technology more intimately to the requirements of our development, as well as for better upgradation, absorption, adaptation and assimilation of new technologies. This task has become imperative as we prepare ourselves to be an internationally competitive economy.

51. Government has also decided on five new initiatives. The first of these is the establishment of a Corporation for the welfare of the backward classes, a task that the Congress manifesto has included for completion within the first 100 days. The details of the structure and duties of this Corporation are being finalised by the Ministry of Welfare and will be announced before the end of this session.

52. Government will establish a National Renewal Fund, with a substantial corpus. The main objective of this fund will be to ensure that the cost of technical change and modernisation of the productive apparatus does not devolve on the workers. This fund will provide a social safety net which will protect the workers from the adverse consequences of the technological transformation. I visualise that this fund will grow in size and State governments will also contribute to its corpus in due course. The fund will not merely provide ameliorative measures for the workers affected in the course of technical change but, more importantly, provide retraining to them, so that they are in a position to remain active productive partners in the process of modernisation.

53. The third programme relates to the care of children of families affected by communal riots. These riots are a blot on the fair name of our Republic. Our Government is deeply committed to the protection and advancement of all religious and cultural minorities. Effective steps will be taken to prevent recurrence of communal violence. At present there are

arrangements to provide compensation of varying amounts to the riot affected families. But experience shows that such compensation does not always protect the interests of children of the riot affected families. These children then grow up into disgruntled and disorganised adulthood. They become an easy prey to the propaganda of anti-social elements and the obscurantist, fundamentalist forces of reaction. To protect the interests of such children, look after their welfare and in particular their education, the Government proposes to set up a National Foundation for Communal Harmony as an autonomous non-government organisation. The Central Government will make a significant contribution to this Foundation in 1991-92. I invite State Governments as well as industry and trade to make liberal contributions for this noble cause.

54. The fourth programme is to promote national integration through a scheme for enabling the youth of each part of the country to go in large numbers and work for short periods in other parts of the country, giving them an opportunity to mingle with people of different regions and languages. A similar step in this direction has already been taken in the Navodaya Vidyalaya Programme. This will now be strengthened and extended on a national basis.

55. The fifth programme relates to promotion of South-South cooperation. We as a nation are committed to close cooperation and sharing our development experience, knowledge and expertise with non-aligned and other developing countries. There is immense scope for Indian scientists, technicians, engineers, teachers, social workers and farmers to contribute to the development process in the third world. Our experience in various fields can be of great relevance and assistance to many developing countries particularly in Asia and Africa. It is our hope to arrange for participation of at least 500 volunteers in different nation building tasks, in selected developing countries, in the coming year. The details of the programmes will be worked out and announced before the end of the session.

56. The House will also be pleased to learn that in acceptance of a recommendation of the South Commission presided over by Dr. Julius K. Nyerere, the former President of Tanzania, we propose to set up a National Committee under the chairmanship of the Prime Minister for mobilising public opinion in support of South-South cooperation and for advising our Government for devising concrete action programmes in this regard. This committee will consist of representatives of Government, trade and industry, trade unions and members of learned professions.

57. The Rajiv Gandhi Foundation has been established to perpetuate the memory of the great leader and to promote the ideals and objectives for which he lived and laid down his life. This Foundation, among other things, will lay particular emphasis on research and action programmes relating to the application of science and technology for development, propagation of literacy, the protection of the environment, the promotion of communal harmony and national integration, the uplift of the under-privileged, women and handicapped persons, administrative reforms and India's role in the global economy. As a homage to the late Shri Rajiv Gandhi and in support of the laudable objectives of the Foundation, Government has decided to contribute Rs. 100 crores to the Foundation at the rate of Rs 20 crores per annum for a period of five years beginning from the current year.

58. Pending determination of the exact amounts that will be necessary for each of these new initiatives, a lump sum provision of Rs. 250 crores has been included in the plan outlay of the Ministry of Finance.

59. The budget provision for total expenditure in 1991-92 is Rs. 113422 crores, of which Rs. 79697 crores is non-plan expenditure and Rs. 33725 crores is plan expenditure.

60. In the sphere of revenue receipts, at the existing rates of taxation, gross tax revenues are estimated at Rs. 66218 crores during the current financial year, compared to Rs. 58916 crores in the revised estimates of last year. The payment to States of their share of taxes is placed at Rs. 15643 crores in 1991-92 as against Rs. 14535 crores in the revised estimates for 1990-91. Thus, the net revenue receipts of the Centre, including non-tax revenue, are estimated to increase from Rs. 57381 crores in 1990-91 to Rs. 65524 crores in 1991-92.

61. In the sphere of capital receipts, market borrowings are placed at Rs. 7500 crores this year, which is lower than Rs. 8000 crores last year; this is part of a conscious effort to reduce the borrowing of the Central Government which would, in keeping with the past trends, have gone up by about 10 per cent. The net collections on account of small savings are estimated at Rs. 8000 crores, which are at the same level as the revised estimates for last year. In addition, the Government has decided to disinvest upto 20 per cent of its equity in selected public sector undertakings in favour of mutual funds and investment institutions in the public sector, which is expected to yield Rs. 2500 crores to the exchequer during the current financial year. This disinvestment would broad-base the equity, improve the management and enhance the availability of resources in these enterprises.

62. The net receipts of account of external assistance, excluding grants, are placed at Rs. 3510 crores compared to Rs. 3984 crores in the revised estimates of 1990-91. While the increase in the loan repayment and interest payment liabilities, as a consequence of the recent exchange rate adjustments, is fully reflected in the budget estimates, the likely increase in the rupee value of external assistance following the exchange rate adjustments is still under assessment. To the extent that these receipts increase, there will also be a corresponding increase in expenditure when the assistance is passed on to the concerned projects or schemes for which such assistance is received. These changes, which will thus be budget deficit neutral, will be incorporated at the stage of revised estimates.

63. Taking into account other changes in receipts and expenditure, total receipts at the existing rates of taxation are estimated at Rs. 103698 crores, while total expenditure is estimated at Rs. 113422 crores. Therefore, without additional resource mobilisation, the budget deficit is estimated at Rs. 9724 crores, the revenue deficit at Rs. 15859 crores, and the fiscal deficit at Rs. 39732 crores.

PART B

64. Honourable Members would have observed that expenditure adjustment constitutes the core of the proposed fiscal correction during the current financial year. But the process of fiscal adjustment cannot be complete without revenue measures to increase the income of the Government. I now seek the indulgence of the House to present the reliefs, the incentives and the levies in the sphere of direct taxes.

65. The revenue from direct taxes, both as a proportion of GDP and as a percentage of total tax revenues, has registered a steady decline over time. This trend has to be reversed, so as to restore equity in, and balance to our fiscal system. Resources for development must be raised from those who have the capacity to pay. For this purpose, we must place greater emphasis on direct taxes. This calls for increased rates wherever necessary and a better tax compliance. At the same time, rationalisation of the system, which reduces the maximum marginal rate of tax, simplifies the procedures, reduces the plethora of concessions, and brings the average rates of income-tax at various levels of income to more appropriate levels, is necessary. The time available before presenting the budget was simply not enough to formulate basic structural changes. Yet, I have made a conscious effort to move one step forward in this direction.

66. Nobody can deny the existence of large scale tax evasion both in terms of income and in terms of wealth. Unless I find substantial improvement in tax compliance in the next few months, Government will have no choice but to take strong measures to make the tax evader pay a sufficiently high price for such delinquency. Before coming down heavily on tax evaders, I would like to give them a last opportunity to come clean. The black money so mobilised will be utilised for the achievement of social objectives such as slum clearance and low cost housing for the rural poor.

*67 I propose to institute a scheme, under which any person would be allowed to make a deposit with the National Housing Bank on or before close of business on 30th

November, 1991. Thereupon, forty per cent of such deposit would be deducted and set apart as a special levy, which would form the corpus of a fund in the National Housing Bank. This fund will be utilised for financing slum clearance and low cost housing for the poor, in accordance with guidelines and priorities laid down by the Government. The depositor would be allowed to draw the balance amount in one or more instalments through account payee cheques for any stated purpose of his choice. There will be no lock-in period for this deposit. Persons making such deposits will not be required to disclose the source of funds from which the deposits are made. In other words, the monies deposited would be provided complete immunity from enquiry and investigation. The provisions of Direct Tax Laws would, however, apply to the net deposits after deduction of the special levy, from the date of the deposit. The levy itself would not be an allowable deduction in the computation of income of the person concerned. Necessary legislation in this regard will be introduced shortly, in this session of Parliament. The details of the scheme and its date of commencement will also be announced soon.

68. The Income-tax Act contains a provision under which tax payers can avail of the facility of waiver of penalty and interest on the amount disclosed once in a life-time. To those who have already availed of this facility, I propose to give just one more opportunity to disclose their unaccounted incomes. The Finance Bill contains a proposal for making suitable amendments to section 273A of the Income-tax Act for this purpose.

69. The Settlement Commission was set up to provide an opportunity to assesses to declare their undisclosed income and wealth. Under the existing procedures, the Commissioner of Income Tax can, on certain grounds, object to admission of an application by the Settlement Commission. This results in unnecessary delay. This provision is, therefore, being deleted. The Settlement Commission will, however, continue to call for and take into account the Commissioner's report, provided it is furnished within a period of six months.

70. Our election manifesto has promised that we will promote reinvestment of profits, by suitable tax exemptions, in areas where there is crying need for massive investment such as low and middle income group housing, highways, roads and bridges, non-conventional energy, school buildings and supply of drinking water. I, therefore, propose to make a provision in the Income-tax Act to provide deduction, in computing taxable profits of a taxpayer carrying on a business or profession, of the entire amount paid for financing projects or schemes promoting social and economic welfare. To ensure optimum use of scarce resources, I propose to set up a National Committee of eminent persons to identify areas requiring support and for recommending specific projects and schemes. A similar deduction will be allowed also in the case of taxpayers not carrying on any business or profession.

71. As a token of my commitment to education and research and in recognition of the significant role they have to play in our development process, I propose to extend certain tax concessions that will help in the funding of social science research and provide some incentive to authors and publishers.

72. At present, only taxpayers carrying on a business or profession get deduction for sums paid to any approved university, college or other institutions for research in social sciences related to the class of business carried on by them. I consider that there is a case for providing more tax incentives for social science research. I, therefore, propose to allow the same 100 per cent deduction in respect of sums paid for research in these areas whether related to business or not. I also propose to allow this deduction to taxpayers not carrying on any business or profession.

73. The role of books, particularly in the context of our National Literacy Mission as well as the National Education Policy cannot be over-emphasized. To encourage publication of better and less expensive books and to give a fillip to the publishing industry, I propose to revive with effect from the current accounting period, the deduction of twenty per

cent of profits from publication of books for a period of 5 years. To encourage the publication of quality text books, in various Indian languages I also propose to revive the 25 per cent deduction from professional income of authors of text books in Indian languages. This will also be available for a period of five years, beginning with the current income-earning period.

74. Offshore country funds are emerging as important channels for attracting foreign institutional investment particularly from non-resident Indians. India made a beginning in this direction in 1989. Of late, however, there are signs of diminishing interest of foreign institutional investors in off-shore India country funds. The comparative national tax structure is one of the key factors affecting the direction of international financial flow. I, therefore, propose to substantially reduce the rate of tax on dividend income received by the off-shore funds from the units of UTI or other mutual funds and on long-term capital gains from such units. On dividend income the proposed rate of tax will be 10 per cent as against the existing rate of 25 per cent. On long-term capital gains, I propose to have the same rate of 10 per cent as against the effective rate of about 45 per cent at present.

75. In the light of our deep emotional involvement with the struggle of the Black majority in South Africa and as a further affirmation of our commitment to South-South Cooperation, I propose that donations to the AFRICA FUND be entitled to 100 per cent deduction under section 80G of the Income-tax Act.

76. The Government is committed to the welfare of our unfortunate handicapped citizens. In an effort to mitigate in some small measure their hardship, I propose to increase the deduction available under Section 80U of the Income-tax Act in respect of totally blind physically handicapped persons, from fifteen thousand rupees to twenty thousand rupees. The benefit of this tax concession is also proposed to be extended to partially blind persons.

77. Promotion of housing activity ranks high in Government's socio-economic priorities. Towards this objective, I propose to extend the benefit of tax rebate under section 88 of the Income-tax Act also to contractual schemes floated by public housing corporations like HUDCO and State Housing Boards along the lines of the Home Loan Account Scheme of the National Housing Bank. Further, the tax rebate under section 88 will also be available in relation to instalments/repayment of loans towards cost of land and also in cases where the house was purchased or constructed before 1st April, 1987.

78. Our software industry has made considerable progress in recent years. However, there is still a vast unexploited potential for growth. It is time we make all-out efforts to capture the overseas software market. With this objective, I propose to extend the tax concession under section 80HHC of the Income-tax Act to export of software. With this concession, the exports of this industry should register rapid growth.

79. I also propose to extend the concession under section 80HHC to the export of processed minerals.

80. I consider that scientific, technical and professional skills, knowledge and experience possessed by our professionals in various fields like architecture, accounting etc. have an increasing capacity to earn foreign exchange for the country. Many of them carry on their professions as individuals or partnership firms. To enable them to benefit from the tax concession available under section 80-O, I propose to extend, to the non-corporate assessee, the concession presently available only to the corporate sector.

81. In order to encourage development of tourist infrastructure in regions where such facilities are almost non-existent today, I propose to exempt from Expenditure Tax for a period of ten years expenditure incurred in new approved hotels set up in hilly and other remote areas. I also propose to allow to such hotels a deduction of 50 per cent from their profits instead of the normal 30 per cent under section 80-I, subject to certain conditions.

82. As a token of my appreciation of the role of a healthy capital market in the development of our economy, I propose to raise the basic deduction of Rs. 10,000 now available under section 48 of the Income-tax Act in respect of long-term capital gains to Rs. 15,000.

83. As indicated earlier, I wish to take some positive steps to reverse the trend of decline in the proportion of direct tax revenues to total revenues. I therefore propose to raise additional resources this year through a greater reliance on direct taxes. I now turn to my proposals for ensuring better tax compliance and mobilising revenues through the imposition of additional taxes.

84. To enable the Government to identify income earners, most of whom would not otherwise declare their income or would not declare their full income, I propose to extend the scheme of tax deduction at source to cover new areas of payments in the nature of commissions, interest paid by banks on time deposits and withdrawals from the National Savings Scheme. To minimise the inconvenience for small depositors, tax will be deducted at source only in respect of payments in excess of Rs. 2500 per year. Those receiving payments in excess of the limit but not having taxable income will have the facility of collecting payment with no tax deduction by filing a declaration in the prescribed manner.

85. The present provision for offsetting short-term capital losses against income leads to tax avoidance. I, therefore, propose that any loss on transfer of a capital asset will be set off only against gain from transfer of another capital asset. This is only logical. It should also stop the practice of buying short-term capital losses being resorted to by some unscrupulous tax payers.

86. Over the years, those with an instinct for gambling have increasingly patronised the races. I propose to withdraw the income-tax exemption of Rs. 5000 in respect of earnings from races, including horse races. I am sure that persons who place bets will now also have the added pleasure of sharing their earnings from races with the Government.

87. Professor Kaldor once observed that no civilised society should have a maximum marginal rate of income-tax higher than 45 per cent. We are firmly committed to a tax system which is simple, credible, yet progressive, in which people realise that honesty is the best policy. I expect to make a beginning in this direction as soon as we can overcome the present fiscal difficulties. I am confident that this process can be completed before the end of the five year term of our Government. Tax payers can help to accelerate the process of tax reform if all of them resolve to pay their income-tax dues fully and promptly. In the midst of a fiscal crisis however, such a change is not feasible. We must wait for better times. The best I can do under the circumstances, is what I propose to do this year: Keep the personal income-tax rate structure including the surcharge unchanged. That I have not added to the burden of the taxpayer is, in itself a relief.

88. I have received several representations that wealth-tax rates need to be rationalised. I see considerable merit in these representations. However, taking into account the needs of revenue and also for want of time, I propose to make no change in the rates of wealth-tax.

89. For the purposes of levy of wealth-tax, the rules of valuation of assets aim at capturing their market value, or near about, as on the valuation date. I find that a distortion has crept into these rules. When an individual holds any asset in his name its valuation is at the market value. However, if a group of persons holds its assets through an investment company the taxable value of these assets gets reduced considerably because it is based on the book value and not on the market value. I, therefore, propose to remove this anomaly by providing that in valuing unquoted shares of an investment company, the break-up value of the share will be determined after revaluing the assets of the company at their market value.

90. I feel disappointed that the phenomenal growth in the output, value added and profits of the corporate sector,

in recent years, has not been appropriately reflected in corporate tax collections. The experience of the preceding financial year, in particular, is a matter of serious concern. I am, therefore, raising the corporate tax rate for widely held companies, from 40 to 45 per cent. A corresponding increase of 5 percentage points from 45 to 50 per cent is being made in the corporate tax rate for closely held companies. I also propose to continue the existing surcharge of 15 per cent.

91. The traditional distinction in corporate tax rates between trading companies and industrial companies has outlived its utility. I therefore propose to remove this distinction.

92. I recognise that in the medium term the rates and structure of corporate taxation have to be consistent with the needs of an economy aiming to become internationally competitive. I shall attend to this task as soon as we have overcome the present fiscal crisis.

93. In our economy, labour is abundant and capital is scarce. These economic realities have to be reflected in our fiscal policy. Yet, over the years, the Indian economy has witnessed a disturbing shift towards greater capital intensity in production. This has led to distortion and avoidable hardship in cases where labour is replaced, or employment potential reduced, by resort to capital intensive methods of production, even in cases where such a shift is not justified on other economic and technical considerations. Fiscal incentives have been conducive to such a shift. While there can be no compromise with the imperatives of technological upgradation and continuous modernisation, the tendency towards excessive capital intensity in our industry must be checked.

94. The rates for depreciation prescribed in 1987, in relation to plant and machinery, are far too generous and provide much more than is needed to compensate for wear and tear. These rates of depreciation do not reflect the true economic life of business assets. An asset would be almost fully written off in six years at the present rate of 33.33 per cent applicable to the bulk of plant and machinery. I think an eight year period would be more reasonable taking into account the pace of technological change in India, the true economic life of the business assets, and the need to discourage tax induced replacement of assets. Therefore, I propose to reduce the general rate of depreciation for machinery and plant from 33.33 per cent to 25 per cent. I also propose to reduce the rate of depreciation for aeroplanes, motor buses, motor taxis and some other equipments from 50 per cent to 40 per cent, which would mean almost complete recoupment of cost in six, instead of five years. However, to encourage use of energy saving devices and renewable energy devices, I propose to continue to provide 100 per cent depreciation on such items of plant and machinery as also some others. Further, I also propose to restrict the rates of depreciation to 50 per cent of the normal rates of depreciation in cases where the asset is used for less than 6 months in a year.

95. Tax support to special institutions may be necessary in their nascent stage. However, it should not be extended in perpetuity. Such institutions must strive to become self-reliant. The Industrial Development Bank of India (IDBI) has been enjoying complete tax exemption in respect of its income since its inception, unlike other public financial institutions. I propose to withdraw this tax exemption, which is no longer necessary.

96. In 1987, the Government had introduced a tax on ostentatious expenditure. It is in the form of a tax of 20 per cent of expenditure incurred in hotels where the room rent exceeds Rs. 400 per day. I propose to extend the coverage of this tax to the expenditure incurred in restaurants providing superior facilities like air-conditioning. This tax will be levied at the rate of 15 per cent of such expenditure.

97. In view of the binding fiscal constraints and the need to mobilise resources, I propose to revive the interest-tax which was first introduced in 1974 and withdrawn in 1978, re-introduced in a modified form in 1980 and finally withdrawn in 1985. I am enlarging, slightly, the coverage of

this tax. The new tax will be levied on the gross amount of interest received by all banks, financial institutions and non-banking financial companies in the corporate sector on loans and advances made in India. These institutions would reimburse themselves by making necessary adjustments in the interest rates charged from borrowers. The proposed tax is expected to raise the cost of borrowing and yield revenue to the Government. It should, therefore, have both monetary and fiscal impact.

98. The proposed tax will be levied at the rate of 3 per cent of the gross amount of interest earned by banks, financial institutions and financial companies on loans and advances made in India. Interest received on transactions between the various credit institutions will be exempted from the proposed tax. The proposed tax will operate prospectively and interest accruing before 1st October, 1991 will not be taxed. The proposed tax will be allowed as a deduction in computing taxable income under the Income-tax Act.

99. I do not propose to take up the time of the House with other minor changes in the Direct Tax Laws.

100. My proposals on direct taxes are estimated to yield a net revenue gain of Rs. 2139 crores. Of this amount, Rs. 97 crores will accrue to the States.

101. Honourable Members of the House are aware that the balance of payments situation is exceedingly difficult. In order to attract larger inflows of foreign exchange, I propose to introduce two schemes.

102. Under the first scheme, I propose that remittances in foreign exchange can be made to any person in India. Even if the remittance is received as a gift by the donee in India, it would not be subjected to gift tax. The source of funds out of which the remittances are made would not be subject to scrutiny under the Direct Tax Laws and Exchange Control Regulations. In other words, I propose to provide immunity for such remittances under these laws. The provisions of Direct Tax Laws will apply in the normal manner to the rupee proceeds of these remittances. The scheme will come into immediate effect and will be open until close of business on 30th November, 1991. The details of the scheme will be announced by the Reserve Bank of India. I also propose to introduce the necessary legislation in this regard as early as possible before this House.

103. Under the second scheme, the State Bank of India would issue India Development Bonds to be denominated in US. dollars. These bonds will be available for purchase by non-resident Indian and their overseas corporate bodies. There will be no ceiling for investment in these bonds which will have a maturity period of five years. The bonds will be fully transferable among non-resident Indians. Interest from the bonds will be exempted from income-tax. The bond itself would also be exempt from wealth tax until maturity. For the non-resident holder, the face value of the bond and the interest thereon would be repatriable with exchange rate protection. The bonds can also be gifted to residents, who would be provided with amnesty and immunity, as in the first scheme for inward remittances. Such amnesty and immunity will be available only to the first resident donee. The gift would be exempt from gift tax. The resident donee bond-holder would also be entitled to exchange rate protection, and the same exemption from income-tax and wealth tax, until maturity, but the proceeds will be paid only in rupees in India and would not be remittable abroad. The bonds will be available for sale at all important branches of the State Bank of India abroad until close of business on 30th November, 1991. The details of the scheme will be announced by the Reserve Bank of India. I would also bring before this House the necessary legislation at the earliest.

104. In formulating my proposals on indirect taxes, I have kept in mind the wider context. In keeping with the promise made in the election manifesto of our party, we have also to ensure that prices of essential commodities and goods used by the common man are kept well under check. Conspicuous consumption must be curbed and the burden of taxation should be borne by the more affluent sections of

the society. In the light of these imperatives, I have attempted to structure the proposals for customs and excise levies in a manner that indigenous industries are encouraged, and, at the same time, imports of items required for export production are not thwarted. In the long term, if revenues are buoyant and tax compliance improves, I expect to bring down the rates of customs and excise levies. Even now, some moderation in import duties is being attempted and a more broad based effort may be attempted to streamline the structure and reduce the rates in the next budget. I have also tried to ensure that the proposed changes improve competitiveness of the industrial sector, particularly the export oriented industries.

105. It is my intention to rationalise and simplify the procedures, rules and regulations pertaining to indirect taxes, so that the delays in the system are eliminated, and the interface between the tax collector and the tax payer is reduced to the minimum. Given the paucity of time, it has not been possible to undertake such an exercise in this budget, but we should be able to formulate concrete measures soon as a part of structural reforms in the tax system.

106. Recent years have witnessed an excessive reliance on indirect taxes for additional resource mobilisation. This escalates costs, fuels inflation and is regressive in its impact. Therefore, I have not relied on indirect taxes as the major source of resource mobilisation. Indeed, the overall impact of my proposals for customs and excise levies is revenue negative in so far as the Central Government is concerned.

107. In the sphere of customs duties, over time, the objective of protection for infant industries and the need to raise revenues have led to a situation where import duties prescribed for certain items are inordinately high and, in several cases, more than 300 per cent. As a measure of reform, I propose to reduce the ad valorem rate of basic plus auxiliary duties of customs to a maximum of 150 per cent where it is more than that at present, thereby eliminating the tariff peaks above 150 per cent. The only exceptions that would remain hereafter are imported alcoholic beverages and passenger baggage. The revenue loss on this account would be Rs. 132 crores in a full year.

108. In view of the deterioration in the fiscal situation last year, auxiliary duty of customs was increased across-the-board, with effect from 15th December, 1990, so as to mobilise additional resources. The increase was not quite rational and was asymmetric in its incidence. In some cases, the auxiliary duty went up by 20 percentage points—from 5 per cent to 25 per cent and from 30 per cent to 50 per cent, while in some others, by just 5 percentage points i.e., from 45 per cent to 50 per cent. This steep and uneven increase imposed a very high burden of duties on certain items, and also led to distortions in the overall rate structure. In order to remove the anomalies which had been created and rationalise rates of duties, I propose to give a duty relief of 10 percentage points to almost every item which suffered an increase of 20 percentage points. Moreover, on certain items, which are important from the point of view of environmental protection, export promotion, saving of foreign exchange and so on, I propose to roll back the rates to levels prevailing before 15th December, 1990. These items include waste paper, would in the rough, jilat used in the manufacture of Agarbattis, ethylene, machinery for fuel injection equipment and certain items of machinery for printing and the newspaper industry. These proposals will result in a revenue loss of Rs. 472 crores in a full year.

109. The prevailing rates of import duty on capital goods for general projects and machinery are, in general, high. While I cannot make a substantial reduction at this stage because of the revenue implications, which are considerable, I propose to reduce the level of duties from 85 per cent to 80 per cent. In tandem, the rate of duty on their components is also being reduced by 5 percentage points from the existing levels of 65 or 70 per cent. This proposal would mean a revenue loss of Rs. 167 crores in a full year.

110. A technology upgradation scheme was launched in 1987 by the late Shri Rajiv Gandhi. Under this scheme, fiscal relief was provided on import of capital equipment for

the manufacture of power generation equipment, paper machinery, textile machinery and many others to promote domestic production of such machinery. The scheme has been instrumental in bringing about considerable improvement in the quality of machines produced in India. In order to give a further thrust to the scheme, I propose to expand the list of machinery items which will now attract a concessional duty of 50 per cent. The revenue loss on this account is estimated at Rs. 5 crores in a full year.

111. We have recently taken several innovative steps to give an impetus to our exports. I would now like to outline some fiscal measures which will give a further boost to the export effort.

112. At present 100 per cent export oriented undertakings or units in a free trade zone are allowed to divert a certain proportion of their production to the domestic market. However, the present stipulation, that excise duty payable must be equal to the import duty, has proved to be a deterrent. These units have to be fostered if they are to compete effectively in the international market; for this purpose they should not be prevented from creating a niche in the domestic market. Accordingly, I propose to reduce the excise duty on the goods, permitted to be sold in the domestic market under the scheme, to a level which would be equivalent to half the import duty leviable on such goods subject, inter alia, to the condition that the duty would not be less than the excise duty levied on similar items produced in the domestic tariff area.

113. To promote the growth of the marine products industry, fiscal relief has been given by way of customs duty concession on specified machinery items required by this industry. I propose to extend the duty concession to a few more items of such machinery. Out of my concern for the welfare of our fishermen, I also propose to fully exempt from excise duty specified yarn which are generally used for making fish-nets.

114. In order to encourage the growth of the finished leather industry and also as a measure of export promotion, I propose to reduce the basic and auxiliary duties of customs on polyurethane film and foil, as well as polyols from 150 per cent to 40 per cent. The duty on isocyanates is being reduced from 120 per cent to 40 per cent. The import duty on two important leather preservatives, namely TCMTB and PCMC, is being reduced from over 150 per cent to 50 per cent. These preservatives will replace certain other chemicals which are suspected to have carcinogenic effects. I also propose to extend the concessional duty, available at present to specified capital goods required by the leather industry to a few more items of such machinery.

115. Synthetic cubic zirconium, which is the closest imitation of natural diamonds, has the potential to provide job opportunities for a large number of artisans. The jewellery made therefrom also has a significant export potential. In order to encourage indigenous manufacture of cubic zirconium, I propose to reduce the import duty on the raw materials viz. zirconium oxide and yttrium oxide to the level of 40 per cent from the present level of over 150 per cent.

116. Our Government attaches the highest priority to agriculture. One of the promises made in our election manifesto is to provide a massive thrust to food processing and other agro-based industries, in an endeavour to increase the income of farmers, create employment opportunities, diversify the rural economy and foster rural industrialisation. As an important step in this direction, I propose to exempt agro-based products such as sauces, ketchup, butter, cheese, skimmed milk powder, vegetable oils, jams, jellies and juices, canned fruits and dried vegetables, certain soya products, starches and preparations of meat and fish from excise duties altogether. I am doing so to promote the diversification of our agricultural economy, to increase the farmers' share of the consumer's income spent on processed agricultural products, to promote rural industrialisation based on agricultural produce and to encourage the adoption of modern post-harvest technologies. The measures I have proposed, I expect, will also lead to some reduction in consumer prices of such products, providing relief to the harassed consumers in

a period of rising prices. The revenue loss will be Rs. 84 crores, but I am convinced that the overall gain to the economy will more than offset the loss to the exchequer.

117. As a relief to the agro-based jute industry, which has been beset with chronic problems, I propose to reduce the excise duty on products which contain a minimum of 35 per cent of jute fibre from Rs. 660 to Rs. 330 per metric ton.

118. At present a number of specified bulk pesticides and pesticide intermediates enjoy concessional import and excise duties. I propose to extend the duty concession to a few more bulk pesticides and pesticide intermediates. The proposals involve a revenue loss of about Rs. 11 crores in a full year.

119. There is a money credit scheme in vogue to encourage the use of minor oils for the manufacture of soaps. I propose to increase the money credit of Rs. 640 per metric ton that is currently available in respect of rice bran oil used in the manufacture of soap to Rs. 1000 per metric ton. In addition, I propose to include some more non-conventional oils and solvent extracted oils in the scheme. This would also help in generating more employment for our tribal women. These proposals involve a revenue sacrifice of about Rs. 19 crores in a full year.

120. The MODVAT scheme was introduced in 1986 to minimise the cascading effect of indirect taxes. The scheme has been well received by the industry, and there have been persistent demands for its extension to other areas. I propose to reintroduce the scheme in respect of aerated waters, and also to extend it to cover man-made fibres and filament yarns in respect of their inputs. While extending the scheme to fibres and yarns, I do not propose to raise the duty on those fibres and yarns on which the duty was increased as recently as December, 1990. On other fibres and yarns, the duty rates have been adjusted with a view to retaining the collection of excise duties at the earlier level. But duties on polypropylene monofilament and multifilament yarns are being increased to raise additional revenue. In respect of aerated waters also, I do not propose any increase in duty. The proposals involve a revenue loss of about Rs. 230 crores in a full year. I expect that the benefit would be passed on to the consumers in the form of reduced prices.

121. I propose to rationalise the existing excise duty rates on polyester blended yarns. As an anti-evasion measure, I also propose to charge additional excise duty on cotton fabrics containing 40 per cent or less of polyester at the same rates as applicable to cotton fabrics containing more than 40 per cent of polyester. The proposals involve a revenue gain of about Rs. 23 crores in a full year.

122. In our effort to make essential drugs available to the people at affordable prices, I propose to fully exempt five specified anti-epileptic formulations from excise duty. At present, some drug intermediates and bulk drugs carry a concessional rate of import duty. I wish to extend the concession to a few more drug intermediates and bulk drugs, and grant concessions in excise duties to a few more drug intermediates.

123. In keeping with our commitment to give special priority to cottage, khadi and village industries, I propose to give some excise duty concessions to this sector. At present, footwear of value not exceeding Rs. 100 per pair manufactured in rural areas by registered co-operative societies, women's societies or by institutions recognised by KVIC, are fully exempted. I propose to raise the value limit of exemption to Rs. 150 per pair. Further, I propose to extend to synthetic detergents the benefit of full exemption from excise duty that is presently available to specified products when manufactured in rural areas by registered co-operative societies, women's societies, institutions recognised by KVIC etc.

124. I would now like to outline some of the steps that I propose for the protection of our environment and for ecological security. In view of our dwindling forest cover, we must conserve our scarce resources. Therefore, as I have stated earlier, the import duty on waste paper and wood in

the rough is proposed to be rolled back to the rates that were prevailing before 15th December, 1990. I also propose to fully exempt from excise duty aluminium doors, windows and their frames so as to encourage the use of aluminium in the place of wood in construction activities. Fly ash is a pollutant. It can, however, be put to productive use in the manufacture of bricks and other construction materials. In order to encourage such use, I propose to fully exempt from excise duty various building components containing more than 25 per cent of fly ash or phosphogypsum. I also propose to exempt phosphogypsum which is one of the by-products of the fertilizer industry from excise duty to encourage its use by farmers.

125. Few would disagree that I am one of the most harassed Finance Ministers in recent times. To perform the onerous task before me, I need support from the Press. As a gesture of goodwill, I propose to exempt standard newsprint from import duty which is, at present, Rs. 450 per metric ton. I have already proposed to bring down the rates of import duty on certain specified machinery and equipment required by the printing and newspaper industry to the levels that were obtaining before 15th December, 1990. The monetary limit of duty free import of photographic goods by accredited cameramen of the Press is being raised from the present level of Rs. 30,000 to Rs. 60,000. These proposals involve a revenue loss of over Rs. 9 crores in a full year.

126. Ever since my appointment as Finance Minister, I have had to spend long hours in office. This has quite naturally made my wife very unhappy. The House will agree that it is not good for the health of our economy if the Finance Minister of the country has strained relations with his own finance minister at home. I propose that the total exemption from payment of excise duty currently available to utensils made of aluminium, copper and stainless steel be extended to certain other household items particularly tiffin boxes.

127. The same consideration has induced me to propose a reduction in the excise duty on specified tableware produced by semi-automatic process from the present level of 20 per cent to 15 per cent. Motivated by the need for peace at home and also taking into account the labour intensive nature of the manufacture of glassware by the mouth blown process, I propose to reduce the excise duty on such glassware to 15 per cent uniformly. Some people may not applaud my action. But I am sure most housewives harassed by the ever rising price level will appreciate my action.

128. In keeping with the commitment in our election manifesto, I shall make every effort to ensure that indirect taxes do not unduly add to the prices of essential commodities. Of the items listed in the manifesto, at present, there is no excise duty on salt, cycles, newsprint, post cards, inland letters and envelopes, and certain varieties of stoves. Cotton sarees and dhoties attract only additional excise duty in lieu of sales tax which accrues wholly to the State Governments. I have earlier proposed to fully exempt edible oils from excise duty. Electric bulbs of upto 60 watts, are already exempt from excise duty. I now propose to fully exempt electric bulbs, of higher wattage, which presently attract a duty of Re. 1 per bulb, from the payment of excise duty. Energy efficient chulhas, too, would be exempted from excise duty. I also propose to reduce the excise duty on two wheelers of engine capacity exceeding 50 cc but not exceeding 75 cc from 20 per cent to 15 per cent.

129. I recognise that the tax reliefs I have given, by themselves, constitute only a small step towards the realisation of the objective mentioned in our manifesto in regard to prices of essential commodities. In pursuit of this objective, I propose to invite the representatives of industry and trade to sit together with our Government to work out modalities as to how best we can contribute to the realisation of the price objectives listed in our election manifesto, for the benefit of the common man.

130. In order to promote tourism which is an important means of earning foreign exchange, I propose to reduce the import duty on adventure sports equipment from rates ranging from about 100 to 300 per cent to 40 per cent.

131. In keeping with the recent exchange rate adjustments of the rupee, I propose to raise the baggage allowances including duty free limits for bonafide gifts suitably; for instance the general duty free allowance for personal baggage is being raised from Rs. 2000 to Rs. 2400.

132. Let me now turn to the major proposals for additional revenue mobilisation.

133. At present special excise duty is being levied at the rate of 5 per cent of the basic excise duty. I propose to raise it to 10 per cent. Since the increase is only a percentage of the basic excise duty, the impact of the additional levy would be minimal on prices. For instance, in respect of any article on which the basic excise duty is say, 20 per cent, the increase would be only 1 per cent of the value. Tea, coffee, sugar kerosene, matches, and vanaspathi, being items of mass consumption, would remain exempt from special excise duty. In addition, I am ensuring that the increase in special excise duty will not apply to diesel and two wheelers. The proposal involves a revenue gain of Rs. 1010 crores in a full year, a substantial portion of which will accrue to the States.

134. One of the promises made in our election manifesto is to evolve policies and measures to curb conspicuous consumption. In pursuance of this, I propose to increase the excise duty rates on refrigerators, air-conditioners including compressors, motor cars, audio and video cassette tapes, video cassettes, picture tubes, colour television sets, VCRs and VCPs.

135. I propose to increase the excise duty on refrigerators by amounts varying from Rs. 200 to 800 depending upon the capacity, and in the case of air-conditioners, by amounts varying from Rs. 2000 to Rs. 30000. I also propose to raise the excise duty on compressors for air conditioners of a capacity not exceeding 7.5 metric ton by Rs. 1800. The expected additional revenue from these proposals is about Rs. 91 crores in a full year.

136. Motor cars at present attract excise duty at the rate of 50 per cent. I propose to increase the excise duty to 60 per cent. The duty on taxis at 30 per cent will, however, remain unchanged. The proposal will yield an additional revenue of Rs. 150 crores per year.

137. I propose to increase the excise duty on audio cassette tapes from Rs. 3 to 5 per sq. metre and on video cassette tapes from Rs. 10.50 to Rs. 15 per sq. metre. The estimated revenue gain from the proposal will be Rs. 29 crores in a full year.

138. As regards colour television sets, I propose to increase the excise duty by Rs. 500 and Rs. 750 per set, depending on the screen sizes. I propose to raise the excise duty on colour picture tubes as well. I am exempting all black and white television sets from excise duty and shifting the burden to picture tubes. I also propose to increase excise duty on VHS type VCRs and VCPs by Rs. 400 per set and Rs. 250 per set, respectively, and on other types of VCRs and VCPs, from 25 per cent to 30 per cent. The revenue gain on this account is Rs. 66 crores in a full year.

139. Every Finance Minister has to do his bit to curb smoking, which is injurious to health, I must also fall in line and add to the tax on cigarettes. In respect of non-filter cigarettes, I propose to raise the duties by Rs. 10 to Rs. 25 per thousand cigarettes depending upon the length. In respect of filter cigarettes, the increase will be between Rs. 35 and Rs. 125 per thousand cigarettes. However, filter cigarettes exceeding 85 mm will attract the ceiling rate prescribed in the excise tariff. This will give us additional revenue to the extent of Rs. 300 crores in a full year.

140. The excise duty on hand-made branded biris is Rs. 3.75 per thousand. Although the duties on cigarettes have been increased almost every year, excise duties on biris have remained unchanged since 1936. I feel that biri smokers should not be denied the opportunity of increasing their share of contribution to the national exchequer. I accordingly propose to increase the duty on hand-made branded biris, other than paper rolled biris to Rs. 4.50 per thousand. Paper

rolled biris will attract a duty of Rs. 10 per thousand. The present exemption on other hand made biris would, however, continue. The expected additional revenue is Rs. 33 crores in a full year.

141. Pan masala not containing tobacco, attracts a specific rate of excise duty. I propose to raise the excise duty on the same by Rs. 5 and Rs. 10 per kg. depending on its value. This involves a revenue gain of Rs. 4 crores in a full year.

142. The excise duty on sugar, which is levied on a specific basis, has remained unchanged since 1983. With the result that the ad-valorem incidence has come down as the price of sugar has increased considerably over this period. In ad valorem terms, the present incidence of excise duty on levy sugar is more than the incidence on free sale sugar. In order to correct the situation, I propose to increase the excise duty on free sale sugar from the present level of Rs. 50 to Rs. 71 per quintal. This would mean an additional tax burden of 21 paise per kilogram of free sale sugar which costs about Rs. 10 per kg. in the market place. This proposal is expected to yield an additional revenue of Rs. 122 crores in a full year. I would like to make it clear that I am not proposing any increase in excise duty on levy sugar which is sold through the public distribution system.

143. I propose to exclude khandsari sugar from the list of items chargeable to additional excise duty. The State Governments will be free to levy sales tax on khandsari sugar, if they so desire.

144. Molasses which is a bye-product of the sugar industry is presently subject duty at the rate of Rs. 120 per metric ton. A substantial portion of molasses is used in the manufacture of liquor. In the circumstances, it can bear a higher rate of duty. Accordingly, I propose to increase the excise duty on molasses to Rs. 150 per metric ton. The estimated revenue gain from the proposal is Rs. 13 crores in a year.

145. The details of the revenue implications of the measures announced are given in the Explanatory Memorandum to the Finance Bill.

146. I have also proposed certain amendments in the Finance Bill seeking to effect changes in the Customs Act, and excise and customs tariffs. These include certain consequential amendments to the customs tariff based on the amendments to the Harmonised Commodity Description and Coding System which has been adopted by our country in terms of the International Convention on the Harmonised System. The amendments are merely enabling provisions and do not have significant revenue implications. Besides, there are proposals for amendment of some of the existing notifications. In order to save the time of the House, I do not propose to recount them.

147. The increases in excise duties will lead to a revenue gain of Rs. 1799.00 crores while the reliefs will amount to Rs. 358.06 crores in a full year. The net revenue gain from excise duties is thus Rs. 1440.94 crores in a full year of which the States will get Rs. 750.04 crores leaving the balance of Rs. 690.90 crores for the Centre. The proposals in regard to changes in the customs duties imply a revenue loss of Rs. 822.52 crores and a revenue gain of Rs. 78.00 crores in a full year. The net impact of the proposals relating to customs duties is a loss of Rs. 744.52 crores in a full year. Thus, as compared with the additional net revenue of Rs. 696.42 crores from customs and excise duties the States would gain Rs. 750.04 crores, while the Centre would lose Rs. 53.62 crores in a full year.

148. Copies of notifications giving effect to the changes in customs and excise duties effective from 25th July, 1991, will be laid on the Table of the House in due course.

149. The proposals I have made in regard to direct taxes will yield Rs. 2139 crores of which Rs. 97 crores will accrue to the States and Rs. 2042 crores to the Centre. My proposals in regard to customs duties will involve a net revenue loss of Rs. 510 crores in the current year while those relating to Union excise duties are estimated to yield a net additional revenue

of Rs. 988 crores in the remaining part of the current year of which Rs. 515 crores will be the share of States and Rs. 473 crores will be retained by the Centre. Taking both direct and indirect taxes into account, the net gain to the Centre in the current year is estimated at Rs. 2005 crores and with this, the budgetary deficit of the Centre for the current year is estimated at Rs. 7719 crores, the revenue deficit at Rs. 13854 crores and the fiscal deficit at Rs. 37727 crores.

150. Sir, I have now nearly come to the end of my labour. Before I conclude, let me end on a personal note. Years ago, in a letter which Jawaharlal Nehru wrote to the young Indira Gandhi, he advised her that in dealing with the affairs of the State one should be full of sentiment but never be sentimental. But the House forgive me if on an occasion like this I cannot avoid being somewhat sentimental.

151. I was born in a poor family in a chronically drought prone village which is now part of Pakistan. University scholarship and grants made it possible for me to go to college in India as well as in England. This country has honoured me by appointing me to some of the most important public offices of our sovereign Republic. This is a debt which I can never be able to fully repay. The best I can do is to pledge myself to serve our country with utmost sincerity and dedication. This I promise to the House. A Finance Minister has to be hard headed. This I shall endeavour to be. I shall be firm when it comes to defending the interests of this nation. But I promise that in dealing with the people of India I shall be soft hearted. I shall not in any way renege on our nation's firm and irrevocable commitment to the pursuit of equity and social justice. I shall never forget that ultimately all economic processes are meant to serve the interests of our people. It is only

through a commitment to social justice and the pursuit of excellence that we can mobilise the collective will of our people for development, to give it a high moral purpose and to keep alive the spirit of national solidarity. The massive social and economic reforms needed to remove the scourge of poverty, ignorance and disease can succeed only if backed by a spirit of high idealism, self sacrifice and dedication.

152. The grave economic crisis now facing our country requires determined action on the part of Government. We are fully prepared for that role. Our party will provide an effective Government to our country. Our people are our masters. We see the role of our Government as one of empowering our people to realize their full potential. This budget constitutes a vital component of a comprehensive vision, a well thought out strategy and an effective action programme designed to get India moving once again.

153. Sir, I do not minimise the difficulties that lie ahead on the long and arduous journey on which we have embarked. But as Victor Hugo once said, "no power on earth can stop an idea whose time has come." I suggest to this august House that the emergence of India as a major economic power in the world happens to be one such idea. Let the whole world hear it loud and clear. India is now wide awake. We shall prevail. We shall overcome.

154. With these words, I commend the budget to this august House.

SMT. JANAKI KATHPALIA, Addl. Secy. (Budget)

